MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS —(Contd)...

MR. CHAIRMAN: We shall now resume the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Satish Chandra Misra.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ-साथ अपनी पार्टी की लीडर बहिन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने की इजाजत दी है।

मान्यवर, जहां तक माननीय प्रेजीडेंट साहब का भाषण है, उसको देखने के बाद यही लगता है कि यह जो एक प्रक्रिया है कि जब भी एक ज्वाइंट सेशन होता है, उसमें इस तरह का एक भाषण, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने के बाद यही लगा कि कोई फर्क नहीं है। पहले जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने लोगों के बीच में जो आकांक्षाएं और उम्मीदें जगाई थीं, उसी प्रकार की उम्मीदें, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने जगाई है। इस एनडीए की सरकार ने भी इसमें यही सब कहा है, यही उम्मीदें जगाई हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आज भाषण में जो बात कही गई कि हम लोग करप्शन और डेवलपमेंट पर वोट लेकर आए हैं, मैं समझता हूं कि करप्शन नहीं, बल्कि जो करप्शन था, उसके विरुद्ध जो बात रखी गई थी कि करप्शन फैला हुआ है, ये उस पर वोट लेकर आए हैं। अभी ये क्या करेंगे, यह तो आगे की बात है। जब इनका सिलसिला शुरू होगा, अभी तो 15 दिन हुए हैं, 15 दिन के बाद आगे बात और चलेगी, तब उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं और करप्शन को किस तरीके से दूर करने की बात करते हैं, जिसके लिए वे स्वयं कह रहे हैं कि हम वोट लेकर आए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे अभिभाषण में, जबकि आपने यह बात कही कि हम करप्शन को दूर करने के नाम पर वोट लेकर आए हैं, इसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया कि आप इस करप्शन को कैसे दूर करेंगे। यहां से लोकपाल का बिल पारित हुआ, दूसरे सदन से भी पारित हुआ, लेकिन आज इस देश में लोकपाल नहीं है। लोकपाल के लिए पूरी लड़ाई सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी हुई और यह उम्मीद थी कि आप इस बात को जरूर कहेंगे कि हम लोकपाल की नियुक्ति करने का काम करेंगे और यह भी कहेंगे कि आप इसे कितने दिन में करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपने कोई ज़िक्र नहीं किया।

आपने सरकार बनाने के पहले इलेक्शन के दौरान वोट लेने के लिए लोगों के बीच बहुत सी उम्मीदें पैदा कीं। आपने नौजवान युवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो महिलाएं हैं, उनके लिए, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में वोट के समय अनेक वादे किए, लुभावने वादे किए और उन्हीं वादों को आपने इस भाषण में भी सम्मिलित किया है, लेकिन देखना यह है कि आप इन वादों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। पहले यूपीए की सरकार ने इस तरह के वादे किए

थे। इस तरह के अनेक लुभावने वाले यूपीए-I में भी और यूपीए-II में भी किए गए थे, लेकिन उनको पूरा न कर पाने की वजह से आज यूपीए की सरकार बाहर हो गई है। क्या आप भी उन्हीं पदचिह्नों पर चलेंगे? इसके लिए यह जरूरी है कि आपको मौका मिले। अगर आप इन वादों को पूरा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग ही नहीं, बल्कि पूरा सदन आपको धन्यवाद देगा और आपकी तारीफ करेगा कि आपने इनको पूरा किया। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हम इस देश से बेरोजगारी दूर कर देंगे, आपने इस बात का वादा करके और पूरे देश में घूम कर, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में इस बात को कहा कि जो नौजवान युवक हैं, जो आज आकांक्षा रख रहा है, जिसने अपना घर बेच कर और अपनी रोटी एक वक्त खाकर अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करके यह उम्मीद रखी कि उसको रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, आपने कहा कि हम उसको शत-प्रतिशत रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आपके इस अभिभाषण में आपने इस बात के लिए यह कहा है कि हम सबके हाथ में हुनर दें, हर हाथ में हुनर रहेगा। आपने हुनर की बात कही है, लेकिन आपने रोजगार की बात नहीं की। इससे इस बात का एक शक सा पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कि जो बाहर कह रहे थे, वह दूसरी बात थी और अब जब लिखित में कहना पड़ रहा है और जब आपकी सरकार बन गई है, तो आपके इरादे कुछ और हैं! आपने कहा कि हर हाथ में हुनर होगा। हुनर जो आज भारत के हर व्यक्ति के हाथ में पहले से ही है, उसको आप और क्या हुनर देंगे! हुनर उसके पास है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आप क्या गारंटी लाते हैं, आप उसको किस तरीके से रोजगार देने का काम करेंगे, इसके लिए कौन से कदम उठाएंगे और कितने दिन में उठाएंगे, आपके पास इसके लिए क्या रोडमैप है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आप उनको किस प्रकार से नौकरी देने की बात करेंगे और इसको कैसे बढ़ाने का काम करेंगे।

आपने अपने इस भाषण में पब्लिक सेक्टर को किनारे कर दिया। आपने इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका ज़िक्र अपने जवाब में करें कि पब्लिक सेक्टर का क्या स्वरूप रहेगा, चाहे वह ओएनजीसी हो, गेल हो, एचएएल हो या अन्य संस्थाएं हों। क्या आप उनको प्राइवेटाइज करना चाहेंगे? क्या आप उनको खत्म करना चाहेंगे? क्या आप उनका स्वरूप बना कर रखेंगे या आप उनका स्वरूप खत्म करके उनको भी प्राइवेटाइजेशन पर ले जा कर उनको खत्म करेंगे? यह पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के माध्यम से लाखों लोगों को नौकरी मिलती है और नौकरी की एक उम्मीद रहती है। उनको यह मालूम रहता है कि हम यहां पर सेलेक्ट होकर अपना अप्वायंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ-साथ, खास तौर से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था चल रही है। वह रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में तो है ही, पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइजेशंस में भी है। आपने नगर निगम और अन्य जितनी भी नगरीय संस्थाएं हैं, उनको धीरे-धीरे प्राइवेटाइज कर दिया है और वहां पर नौकरियां खत्म करके, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया है। आज आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं कि वे सफाई करें। जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं या जहां

पर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, वहां रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रेक्टर्स बगैर रिजर्वेशन के लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं, वे अपने हिसाब से नौकरी देते हैं। इस देश के जो करीब 25% लोग हैं, 22%-23% तो आपके आंकड़ें भी बताते हैं यानी जो इस देश के लगभग एक-चौथाई लोग हैं, वे भी तो आपके इस देश की ही जनता हैं। उनके लिए रोजगार की जो जगहें हैं, उनको धीरे-धीरे आप खत्म कर रहे हैं। यह काम पिछली सरकारों ने किया है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो नगर निगम अथवा अन्य नगरीय स्थानीय निकाय हैं अथवा जो पब्लिक सेक्टर हैं, इनके संबंध में आपकी क्या मंशा है? इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इसका खुलासा आप जरूर करें, क्योंकि इनसे लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। वे सभी लोग आपसे यह बात जानना चाह रहे हैं।

आपने कहा कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल का एक सपना आपने दिया और गुजरात मॉडल के नाम पर आपने वोट मांगा। आपने कहा कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे, लेकिन यह गुजरात मॉडल है क्या? इसका इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? अब तो चुनाव खत्म हो गया और गुजरात मॉडल के नाम पर वोट भी मिल गया, लेकिन गुजरात मॉडल आखिर क्या चीज है? गुजरात मॉडल के अंदर ऐसा कौन सा तिलिस्म या जादूगरी है, जिसके मिलने के बाद यह पूरा देश गुजरात की तरह हो जाएगा, इसके बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं बताया है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर यह गुजरात मॉडल है क्या, जिसके नाम से आपने कहा कि गुजरात आइए? हर व्यक्ति तो गुजरात नहीं जा सकता।

उत्तर प्रदेश के काफी लोग गुजरात में हैं और काफी लोग महाराष्ट्र में भी हैं। उनकी वहां पर क्या दुर्दशा हो रही है, उनके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से वहां उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र में आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने आपसे खुद टेलीविजन चैनल पर आकर कहा था कि नरेन्द्र मोदी जी, हम तो सबसे पहले आपसे यही विनती करेंगे, जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप इनकी देखभाल करिएगा और इनको यहां से वापस ले जाइएगा। अब तो आप उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुन कर आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित हुए हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों से आज महाराष्ट्र में काम लिया जा रहा है और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उनको इस देश का नहीं माना जा रहा है। आप कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, ये गलत बात बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: प्लीज, आप बैठ जाइए। Misraji, please continue.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मैं मान सकता हूं कि आपको दर्द हो रहा होगा। आपको दर्द इसलिए

भी हो रहा है, क्योंकि आप वहां यह कह रहे हैं। आज आप केन्द्र की सरकार में सरकार के साथ भी आ गए हैं और आपकी पार्टी से मंत्री भी बने हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी वहां पर है, वह खुलेआम इस तरह की बात कर रही है, उनके लोग भी आपके सहयोगी हैं। पहले वे आपके साथ थे और आज वे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं।

जिस तरीके से वहां पर आप खुलेआम टेलीविजन में दिखा-दिखा कर उत्तर भारतीयों और बिहार के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर उसका जिक्र हम पार्लियामेंट के अन्दर भी नहीं कर सकते, तो कहां करेंगे? हम महाराष्ट्र में तो उसका जिक्र नहीं कर सकते, तो आप बताइए कौन सा ऐसा स्थान है, कहां जाकर हम इसका जिक्र करें? क्या गुजरात में जाकर करें? गुजरात मॉडल तो पूरा देश हो रहा है। कहां जाकर हम उसका जिक्र करें? अगर हम यहां भी उसका जिक्र नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें कहां उसका जिक्र करने देंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

आपने स्वयं अपनी बात में कहा है कि आप चाहते हैं कि एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। आपके ये शब्द इसमें लिखे हैं, जिसमें आपने कहा है – "एक भारत-श्रेष्ठ भारत"।

डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमने भी पढ़ा है और हमारे अन्य साथियों ने भी पढ़ा है। पहले जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और जो आज इस हाउस के लीडर हैं, वे एक बहुत ही महान वकील हैं। इस समय जो हमारे विधि मंत्री जी हैं, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, वे भी एक बहुत बड़े वकील हैं। इन लोगों के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। मैं भी 38 वर्षों से वकालत करते हुए कांस्टीट्यूशन पढ़ रहा हूं। मैंने भी देखा है कि उसमें कहीं पर दो तरह का भारत नहीं लिखा हुआ है। उसमें पूरा भारत एक है और एक भारत में हर किसी को अधिकार है कि वह देश के हर कोने में जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी नौकरी कर सकता है और कहीं पर भी अपनी जीविका चला सकता है। तो इस 'एक भारत' की बात आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपके अन्दर पहले से ही यह बात है कि आप इस देश को एक भारत नहीं मानते हैं। आप शायद इसको अलग-अलग मानते हैं। अगर आप इसको अलग मानते हैं और अब आप इसको एक मानना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि अब आप इस देश को एक मानना चाहते हैं। 'श्रेष्ठ भारत' तो हम लोगों का है ही और इसको आप श्रेष्ठ मान रहे हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन, जब आप 'एक भारत' मान रहे हैं, तो सभी भारतवासियों के साथ चाहे वे बंगाल के लोग हों, चेन्नई के लोग हों या उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनके साथ आप किसी भी तरह का भेदभाव पूरे देश में मत कीजिए और उनको एक साथ लेकर चलिए। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपने कहा कि हम उनका बड़ा ख्याल रखेंगे, हम उनकी इन्क्लूसिव ग्रोथ करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसमें उनके बारे में क्या बात कही है? मैं इसको बार-बार देख रहा था कि आपने उनके लिए और उनके इन्क्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या है? आपने इसमें शायद कुछ नहीं कहा है। हमारे बहुत से लोग मंत्री हो गए हैं और जोकि खुद भी शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं,

लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वे लोग तो कम से कम दबाव डालेंगे और अपनी सरकार से कहेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए। आपने अपना मत जाहिर नहीं किया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोमोशन में रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या मत है? प्रोमोशन में रिजर्वेशन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अड़ंगा लगा था। Reservation in promotion आज भी कांस्टीट्यूशन में है। मैं बीजेपी को इसलिए कहता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। आप लोग इसको लाए थे। आप लोग इसको शुरू में अमेंडमेंट करके लाए थे। लेकिन, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके अमेंडमेंट को निष्क्रिय कर दिया, तो एक दूसरे तरीके से उसको कांस्टीट्यूशनली वैलिड होल्ड करते हुए भी उसमें ऐसी चीजें कह दीं कि आप पहले यह कीजिए तब आप इसको इम्पलीमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमेंडमेंट यहां आया था। अमेंडमेंट आया तो राज्य सभा में उस अमेंडमेंट का काफी विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद वह पारित हुआ और वह यहां से पारित होने के बाद लोक सभा में गया। लेकिन, अफसोस की बात है कि लोक सभा में जाने के बाद वहां पर उसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया गया, क्योंकि समूची भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन वहां पर उसका विरोध करने का काम किया था और इसलिए वहां पर वह पारित नहीं हो पाया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु: एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... पहले मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं। उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। ...**(व्यवधान)**... Mr. Misra, you are aware of the fact that what happens in the other House cannot be quoted in this House. ...*(Interruptions)*... आप मेरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**... आप क्यों जवाब दे रहे हैं? He is capable, आप लोग क्यो कष्ट करते हैं? Secondly, they are taking the name of a Party, which is highly objectionable. BJP has not done any such thing.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, मैं चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, I yielded to Venkaiahji, I would not yield to Mr. Paswan. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. आप बैठ जाइए। ...*(Interruptions)*... Ramvilasji, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... He is not yielding.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सर, अगर मंत्री लोग ही ऐसा करेंगे, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: नरेश जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, मैंने उनके लिए यह नहीं कहा था ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: जब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: सर, ...**(व्यवधान)**... इनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया था ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: जब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... अभी इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: जब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। आपको तो इस पर बोलना भी चाहिए कि आप क्या करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: मैं बोलूंगा ...**(व्यवधान)**... मैं अभी एक घंटा वहां बोल कर आया हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: लोग आपका मत जरूर जानना चाहेंगे। ...**(व्यवधान)**...

25 करोड़ लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Ramvilasji, no cross-talking.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: 25 करोड़ लोग आपकी आवाज सुनना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या मत है। आप घबराइए नहीं, पासवान जी।

MR. CHAIRMAN: Satishji, please continue with your speech.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: लोग आपका मत जरूर जानना चाहेंगे। ...**(व्यवधान)**... आप एन.डी.ए. के सहयोगी हैं, इसलिए लोग आपका मत जरूर जानना चाहेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, no; no cross-talking. Please address the Chair.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: लेकिन, मैं तो बीजेपी से पूछ रहा हूं, मैं तो एनडीए से पूछ रहा हूं कि उनका क्या मत है, इसमें उनको लिखने में क्या दिक्कत थी, आपने क्यों नहीं कहा? आपने कहा कि हम 'महिला आरक्षण' को लाएंगे। हमने उसको सपोर्ट किया। हमने यहां पर पास कराया। हम लोग कहते हैं, हमारा सिर्फ इतना मत है कि 33 प्रतिशत नहीं, आप 50 प्रतिशत महिलाओं को लाइए, क्योंकि इस देश में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं और आप 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप 50 प्रतिशत लाइए, लेकिन इसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोलना चाहा, आखिर ऐसा क्यों? लगता है कि आपकी मंशा साफ नहीं है। इस प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल की वजह से लगभग ढाई लाख लोग नौकरियों में रिवर्ट कर दिए गए हैं, आज वे बाहर हो रहे हैं, उसके लिए आपने कुछ किया होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और न ही आपने इस अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। हो सकता है कि यह स्लिप हो गया हो, हो सकता है कि आपसे मिस हो गया हो। मैं चाहूंगा कि आप इस संबंध में अपने स्टैण्ड का जरूर खुलासा करें। इस सदन में खुलासा करें और बताएं कि आपका इसमें क्या स्टैण्ड है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का संविधान में ऑलरेडी प्रावधान है, जिसमें एक संशोधन आया था, उसके बारे में आपका क्या मत है, यह मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा।

मान्यवर, सरकार ने चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी उम्मीद बनाई है और सबको एक आश्वासन दिया, एक सपना दिखाया और दिखाना भी चाहिए। जब वोट लेना होता है, तो सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन वोट मिल जाने के बाद अगर आप उन सपनों को क्रियान्वयन में नहीं लाएंगे, तो मान्यवर, यही जनता जिसने आपको वोट दिया है, ये छः महीने भी वेट नहीं करेगी। आज के जो यूथ हैं, आज के जो लोग हैं, वे काफी रेस्टलेस हैं और वे चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि हमने तो एक सपना दिखाया। आपने सपना दिखाया कि हम 24 घंटे की बिजली उपलब्ध करा देंगे, 24 घंटे बिजली सबको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आपने जाकर कहा कि यहां तो दो घंटे की बिजली नहीं मिलती है। बिजली मिलती है या नहीं मिलती है, आपने इस तरह के प्रश्न पूछे। अपनी मीटिंगों में प्रश्न पूछे और आपने जवाब भी सुना कि नहीं मिलती है। फिर आपने कहा कि हम दिलाएंगे। हम 24 घंटे की बिजली देंगे। महिलाओं से आपने पूछा कि तुम्हारे घर में चूल्हा है या नहीं है, तुम्हारे घर में गैस है या नहीं है, इतना महंगा तुम खरीद पाती हो या नहीं खरीद पाती हो? उन्होंने कहा कि हम नहीं खरीद पाते हैं। हमारे पास तो एक वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं है, तो हम इतनी महंगी गैस कैसे खरीदेंगे? आपने कहा कि चिंता न करो, हम आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे आने के बाद आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपको गैस आधे दाम पर मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। आपको खाद कम दाम पर मिलेगी। आपने इन सब चीजों के लिए एक सुनहरा सपना दिखाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार को आए 15 दिन हुए, आते ही आपने पहला सदमा यह कह कर दिया कि पहली जुलाई से रिलायंस को गैस के लिए हम दोगुने दाम देंगे। अगर इसके लिए दोगुने दाम दिए जाएंगे, तो जाहिर है कि इससे गैस के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल के दाम इस देश में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, यह हम लोग जानते हैं और आपने बढ़ा भी दिया। आपने आते ही दाम बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। यह बात दूसरी है कि पचास पैसे बढ़ाए, छोटे-छोटे हिस्से में बढ़ाइए, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। इस तरह का इंतजाम कीजिए और साल भर में इतना बड़ा झटका लग जाए कि साल होते-होते लोग मुंह के बल गिर पड़ें। अगर आप इस तरह की योजना बनाने का काम करेंगे, तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज भारतवर्ष की जो जनता है, वह इन सब मामलों में चुप बैठने वाली नहीं है। वह आपसे प्रश्न करेगी और प्रश्न हम लोगों के माध्यम से भी होंगे और वे आपसे सीधे-सीधे भी प्रश्न करेंगे। अगर आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वे अपने वोट के माध्यम से जिस तरीके से इन लोगों को बाएं से दाएं पहुंचाया है, उसी तरीके से आपको भी पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ आपने कहा कि हर व्यक्ति को पक्का मकान और शौचालय मिलेगा, यह बहुत अच्छी बात है। यह होना भी चाहिए। जब हम लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, पिछली सरकार में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, तो हम लोगों ने मान्यवर कांशीराम जी के नाम से एक योजना बनाई थी। केन्द्र की सरकार से मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए प्रदेश के कोटे से लगभग 20 लाख मकान बनाने की योजना बनाई और जो लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे थे, उनको ले जाकर मुफ्त में एक कमरे का नहीं, बल्कि दो-दो कमरे के मकान दिए गए। आज वे लोग उसमें रह रहे

हैं। यह बात दूसरी है कि अब जो सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसने आते ही उस योजना को बंद कर दिया। आधे मकान जो बने हुए थे और जो योजना थी कि उत्तर प्रदेश में अगले पांच सालों में एक भी ऐसा व्यक्ति न रह जाए, जिसके पास अपना खुद का मकान न हो और कोई ऐसा गरीब व्यक्ति न हो, जिसके पास अपना मकान न हो, उस योजना को ठप्प कर दिया गया। वह अलग चीज है, लेकिन आपने कहा है कि हम इस योजना को पूरे देश में लागू करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इसमें कह दिया कि जब 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 2022 में आप इसको ले गए। आपने कहा कि 2022 तक इंतजार करो, तब हम तुमको मकान देंगे। ऐसी भी क्या बात है? आप मकान देना कब से शुरू करेंगे? आप इस योजना को कब से लागू करेंगे? कितने लोग बेघर हैं, क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं? अगर यह है तो आप इस योजना के बारे में बता सकते हैं कि आपका किस तरीके का रोडमैप होगा, आप किस तरह से इसको चलाएंगे, लेकिन आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

आपने कहा है कि हर घर में शौचालय होगा। शौचालय एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में आप और हम सब लोग जानते हैं कि उसके कारण हमारे गांवों में महिलाओं को किस तरीके से बेइज्जत होना पड़ रहा है। शौचालय न होने की वजह से उनको घरों से बाहर जाना पड़ता है और घरों के बाहर जाने पर उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है, ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। जब-जब गाड़ी सड़क से निकलती है, उनको उठकर खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद बैठना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इस देश के लिए यह शर्म से डूब मरने की बात है कि हम लोग उस देश के वासी हैं जहां पर हमारी महिलाएं, जिन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हम कह रहे हैं, जिनको हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आज उनके लिए हम यह कह रहे हैं कि हमें अभी उनको शौचालय देने हैं। शौचालय देने की बात आपने कही कि हम यह सन् 2022 तक देंगे। हम उन्हें यह 2022 तक देंगे, लेकिन यह तो उनका मूलभूत अधिकार है, यह 'Right to live with dignity' है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो इस बात को उसमें डाला कि हर व्यक्ति को 'Right to live with dignity' है, लेकिन क्या यही dignity है? आज उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिस प्रकार से हुआ, वह तो एक उदाहरण है, जहां दो बच्चियां, जब वे मजबूरन शौच करने बाहर गईं, तो उनके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उनको मारकर लटका दिया गया। उसके बाद वहां के डीजीपी की बात सुनकर हमें शर्म आती है। यह किस प्रकार का डीजीपी है जो कहता है कि यह प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था, जबकि उसे या तो तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए था या उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए था। वे दोनों दो सगे भाइयों की लड़कियां थीं और घर के नाम पर उनके पास रहने के लिए एक कमरा था, जबकि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कह रहा है कि यह झगड़ा प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

हमारी नेता बहन मायावती जी ने वहां जाकर इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच रिकमेंड करने के लिए हम

राजी हो गए हैं और हमने इसकी सिफारिश भेज भी दी है। अगर उन्होंने इसकी सिफारिश भेज दी है, तो वहां का डीजीपी कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? वहां की लोकल पुलिस किस तरीके से प्रेशर डाल रही है और केन्द्र की सरकार इसमें क्यों चुप बैठी है? माननीय प्रधानमंत्री जी तो बैकवर्ड क्लास से हैं। उन्होंने यह हमेशा कहा और चुनावों में भी कहा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम बैकवर्ड क्लास के हैं, अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और जब हम अपने को ऐसा कहते हैं तो गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन इस मामले में अति पिछड़े वर्ग की दो बच्चियां, जिनके साथ इस तरह का जघन्य हादसा हुआ और जिनकी हत्या हो गई, उनके बारे में हम लोग अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से एक शब्द सुनना चाहते हैं। अभी भी हम लोग उनकी संवदेना के शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। अगर आपके पास सीबीआई जांच की रिकमंडेशन आ गई है, तो आप उस फाइल के ऊपर क्यों बैठे हैं? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप सीबीआई को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहते हैं कि हम बर्खास्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो साझे में चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में टिकट के बंटवारे भी किए थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति जी, इसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं रही है। अगर इस तरह का गलत और अनर्गल आरोप कार्यवृत्त में आ जाएगा, तो यह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: We will verify and then take a decision on it.

श्री नरेश अग्रवाल: सभापति जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको प्रोसिडिंग्स से निकलवा दीजिए।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री नरेश अग्रवाल: क्योंकि कभी भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ते रहे। ...**(व्यवधान)**... कभी भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ी हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Satishji, please continue.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : आखिर एन.डी.ए. की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं, यह तो वे ही बताएंगे। इसके अलावा आपको अगर इतना दर्द हो रहा है कि आप उनसे मिल करके नहीं लड़े और आपने मिल करके रणनीति नहीं बनाई तो उनको बताने दीजिए कि वे इस पर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त

करने के लिए पहल करते हैं, क्यों नहीं वहां से रिपोर्ट मंगाने का काम करते हैं? यह प्रश्न मैं उनसे कर रहा हूं और इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब उनसे सुनना जरूर चाहती है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि 2022 तक शौचालय देने की जो आपकी योजना है, इसको आप दोबारा से देखिए और अगर आप 2022 तक इस प्रदेश की महिलाओं को शौचालय देंगे, तो यह बहुत ही अफसोस की बात होगी। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अखबार में निकला था कि इस मद में जो 250 करोड़ रुपए केन्द्र ने भेजे, प्रदेश की सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अगर इस्तेमाल नहीं किया है और आपने भेजा है तो आप क्यों नहीं पूछते? आप इसको बनवाने का काम करिए। वहां सुलभ इंटरनेशनल पहुंच गया और उसने कहा कि हम बदायूं में सुलभ शौचालय बनाएंगे, इस गांव में बनाएंगे। एक गांव से नहीं होता है, पूरे प्रदेश को देखना है, पूरे देश को देखना है और यह एक ऐसी चीज है जो कि महिलाओं का मूलभूत अधिकार है और इसको एक फास्ट ट्रैक में डालकर और योजनाबद्ध तरीके से बना कर आगे चलने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, अगर आप इसको क्रियान्वित करेंगे तो हमारी पार्टी यहां पर खड़े होकर भी और बाहर भी आपका धन्यवाद जरूर देगी और इस बात के लिए आपकी तारीफ करेगी।

किसानों के लिए सुविधाओं पर आपने कहा कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि यू.पी.ए. की जो रणनीति थी वह इस तरह की थी कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन हम उसको उस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। आप क्या सुविधाएं देंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब तो एक वैसे वाले संटेंसेज हैं, जिनको कह दिया कि हम किसानों को बहुत सुविधाएं दे देंगे। हम किसानों को ऐसा कर देंगे कि किसान उसके बाद आत्महत्या नहीं करेंगे, किसानों के बारे में कभी आपने सोचा कि वह जो उपज करते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, जो उनके पास छोटी-छोटी जमीनें होती हैं उनको बेच करके वे धीरे-धीरे अपना गुजारा कर रहे हैं या कर्जे में डूबे हुए हैं। किस तरह से वह किसान अपनी जीविका चला रहा है, जबकि उसके पास पैसा है नहीं। किसान जो उपज करता है और उसका जो दाम आप उसको देते हैं और जो सरकार देती है, उस पर आप कभी गौर करिए। उसको अगर 5 रुपए मिलते हैं तो बाजार में वही चीज जाकर के 25 रुपए में मिलती है जो कंज्यूमर को मिलती है। तो यह जो बीच में 20 रुपए का फर्क आता है, यह क्यों आता है इस पर आप शोध करिए, इस पर सोचिए। किसान को आप 25 मत दीजिए लेकिन 20 तो जरूर दीजिए, जिससे वह किसान भी जीवित रह सके और सुविधाएं पा सके और उसके साथ में अपना पालन-पोषण, अपने बच्चों का पालन-पोषण वह कर सके। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।

भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों के बारे में आपने कहा कि इनके लिए हर तरह की सुविधा करेंगे जिससे कि जो लघु उद्योग हैं और कुटीर उद्योग हैं, वे आगे पनप सकें। लेकिन कब करेंगे,

क्या योजना है? खाली कह देने से, यह तो इन्होंने भी कहा था, ऐसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन कह देने से कुछ नहीं होता। आप किस तरीके से करेंगे, उनके लिए क्या योजना ला रहे हैं, किस तरीके से करेंगे? आपके पास गुजरात में 24 घंटे की बिजली है, वहां पर 24 घंटे की जगह 18 घंटे कर दीजिए और छः घंटे की बिजली आप दे दीजिए उत्तर प्रदेश को तथा और प्रदेशों को, क्यों आप अपने पास सारी बिजली रखे हुए हैं और क्यों आप दूसरे प्रदेशों को नहीं देना चाहते हैं? और प्रदेशों में जो उद्योग हैं, खाली गुजरात के उद्योग चलेंगे तो यह देश गुजरात नहीं है, गुजरात के अलावा भी है और प्रदेश हैं यहां पर, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): If you yield for a minute.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मालूम है पीयूष गोयल जी, आप बिजली मंत्री बने हैं, आप यह कहेंगे कि पैसा दो और बिजली लो। ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल: आपके प्रदेश ने चुनाव के बाद खरीदना क्यों बंद कर दिया? ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: पीयूष गोयल जी, अभी-अभी आप इस मंत्रालय में आए हैं और मंत्रालय में आने के बाद अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं अभी आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह शुरुआत की बात है। आप इन बातों को ध्यान में रखें और आप जो योजना बनाएं, वह इस तरीके से बनाएं कि गुजरात को देश का हिस्सा समझें। आप गुजरात को खाली गुजरात न समझें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो इससे आपका भला होगा, देश का भला होगा और देशवासियों का भी भला होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Please continue. ...*(Interruptions)*... Please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: अब क्या करें, हमारे साथी गुजरात के नाम से कुछ ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Satishji, your time is running out.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आपने नक्सलवाद के बारे में क्या सोचा है? मैं जानना चाहूंगा कि आप नक्सलवाद को किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं? आप कहते हैं कि हम नक्सलवाद को बंदूक और गोली से ठीक कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप बंदूक की गोली से उसे कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको उसे खत्म करने के लिए देखना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जंगलों में रहने वालों के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं। उन्हें बंदूक उठाने के लिए क्यों मजबूर होना

3.00 P.M.

पड़ता है? वे नक्सली क्यों बन जाते हैं? आप उनकी जमीन छीन लेते हैं, उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि हम चिह्नित करेंगे कि कितनी जमीन पूरे देश में ऐसी है, जोकि एग्रीकल्चर के लायक नहीं है। हम उसका इस्तेमाल इनके लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने इसे पहले से ही चिह्नित कराया था और उसके बाद वहां जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं थी, उन्हें दो-दो एकड़ के प्लॉट काटकर वह जमीन मुफ्त दी गयी। आज वे उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से सीखिए और इस तरह की योजना बनाइए न कि किसी खुली जमीन को आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दें, किसी इंडस्ट्रियल हाउस को दे दें और वहां वहां अपनी इंडस्ट्री लगाए। इस तरह की योजनाओं से काम नहीं चलेगा। आप जंगल में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक दीजिए। उनका डेवलपमेंट कीजिए। आप नक्सलवाद को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपए बंदूकों व दूसरे इक्यूपमेंट्स पर खर्च करते हैं, अगर आप इस का एक-चौथाई पैसा भी उनके डेवलपमेंट पर लगा दें, तो शायद यहां कोई नक्सली पैदा न हो। महोदय, हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा कर के देखा है। उत्तर प्रदेश के जिस एरिया में नक्सलवाद की बात चली, जब वहां उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया गया, उनको वहां रोजगार दिया गया, काम दिया गया तो जब बहन मायावती जी की सरकार थी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी नक्सलवाद की वारदात नहीं हुई। हम चाहेंगे कि आप जंगलों में रह रहे लोगों की शिक्षा और विकास पर रुपए खर्च करें न कि उन्हें खत्म करने के लिए बंदूकों व गोलियों पर पैसा खर्च करें क्योंकि इससे कभी भी नक्सलवाद खत्म होने वाला नहीं है।

महोदय, अदालतों में लंबित मामलों के बारे में हमारे कानून मंत्री जी भलीभांति जानते हैं। इसमें कहा गया है कि हम अदालतों में मामले कम करेंगे, अदालतों में लंबित मामलों पर रोक लगाएंगे, जजेज की वेकैंसीज को फुलफिल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह कैसे करेंगे? आज से 10 वर्ष पूर्व, अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, तो वहां पर 160 वेकैंसीज डिक्लेयर हुई थीं और आज 10 वर्षों बाद, एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है, जिसमें वहां पर 80 से ज्यादा जजेज रहे हों। महोदय, 15 लाख से ज्यादा मुकदमे अकेले उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ में पेंडिंग हैं। आप इसके लिए कैसे योजना बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम जजेज की नियुक्ति जल्दी करेंगे। आपने तो एक दिन पहले अभी श्री रंजीत कुमार को सॉलिसिटर जनरल अपाइंट किया है। आपने 15 दिन तो सॉलिसिटर जनरल अपाइंट करने में ले लिए। वह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। हम आपको बधाई देते हैं कि आपने एक सीनियर एडवोकेट को सॉलिसिटर जनरल बनाया जोकि इस पद से भी आगे जाने के योग्य हैं। लेकिन आज सरकार बने इतने दिन हो गए, आप यह नहीं कह सकते कि कल की ही बात है...

इस सरकार को बने आज इतने दिन हो गए हैं, आप यह नहीं कह सकते कि अभी कल की बात है, इस देश में जो कंस्टीट्यूशल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल की, उसे भी आप एपायंट नहीं कर सके हैं।

[**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए]

अटॉर्नी जनरल आज भी एपायंट नहीं हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हो जाएंगे, हम मान रहे हैं, क्योंकि यह होना तो है ही, यह देश बगैर अटॉर्नी जनरल के नहीं रह सकता है, लेकिन कब एपायंट होंगे? अगर अटॉर्नी जनरल बनाने में इतना समय लग रहा है, इतने पुल्स एंड प्रेशर्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जजों की नियुक्ति के बारे में क्या होगा? जजों को जब आप एपायंट करने चलेंगे, तो उसमें किस तरह के प्रेशर्स होंगे? इसलिए आपको इसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपने इसको करना है। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां 21 करोड़ जनता रहती है और वहां हाईकोर्ट की दो बैंच हैं, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में। पूरा जो उत्तर प्रदेश है, उसमें दूर-दूर से नोयडा से लेकर, गाजियाबाद से लेकर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने केस के सिलसिले में इलाहाबाद जाना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है और बराबर यह हमारी डिमांड रही है, हमारी नेता बहन मायावती जी ने भी बार-बार इस सदन में कहा है, बाहर भी कहा है, कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बैंच बनाइए, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिले और लोगों को सैकड़ों मील चलकर वहां उस हाईकोर्ट में न जाना पड़े। इसके बारे में आप जरूर सोचिए और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में अपना मत जरूर दें।

उपसभापति जी, जहां तक लोकपाल की नियुक्ति का सवाल है, उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। जब आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन हटाने की बात करते हैं, करप्शन हटाने के नाम पर आप चुनाव जीत कर आए हैं, तो आप इस लोकपाल की संस्था को क्रियान्वयन में कब लाएंगे, इस बारे में आप जरूर बताएं। माननीय वित्त मंत्री जी, जो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, इत्तफाक से वह इस समय यहां नहीं हैं, मैं उनसे यह जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इसमें कहीं भी टैक्स एग्जम्पशन की बात नहीं की है। चुनाव के दौरान आपका यह नारा था कि पांच लाख रुपए तक आप टैक्स में छूट दे देंगे। इस पांच लाख तक की छूट के बारे में मैं उनको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपनी उस बात का जरूर ध्यान रखें, आप बजट बना रहे हैं और इस देश की जनता आपकी ओर देख रही है कि पांच लाख तक की छूट तो मिल ही जानी चाहिए, अगर ज्यादा मिलेगी तो आप और बधाई के पात्र होंगे, लेकिन पांच लाख का जो आपने देशवासियों से प्रोमिस किया है, उसके लिए इस देश के देशवासी इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, खाद्य सुरक्षा बिल का इसमें जिक्र नहीं है। यह बहुत ही अफसोस की बात है, या तो फिर से इसमें चूक हो गई है, क्योंकि आपने सब बातें तो लिख दी हैं, खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में जिक्र नहीं किया। आपने राइट टू फूड और राइट टू एजुकेशन, इन दोनों को किनारे कर दिया, जैसे कि आपने एससी, एसटी के प्रोमोशन को किनारे किया है। यह एक छोटी सी किताब, जिसमें बहुत सी बातें हैं, इसमें आपने इनको हटा दिया। आपने इसमें इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आज आप कहते हैं कि हर आदमी को खाना मिलेगा, हरेक को रोटी मिलेगी। आप किस

तरीके से उनको रोटी देंगे? यहां जो एक एक्ट पास हुआ था, जिसमें आप भी भागीदार थे, क्या उसको आप क्रियान्वयन में लाएंगे? अगर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? उस बारे में क्या करेंगे? इसे लाएंगे या नहीं लाएंगे? जो लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उनके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? इसके बारे में आपने इसमें कुछ नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में जरूर कुछ करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के बारे में, आप राइट टू एजुकेशन को कैसे इंपलीमेंट करेंगे? यह एक अमेंडमेंट हो गया, जो एक कागज पर रह गया, लेकिन यह कह देना कि हम आदेश जारी कर देंगे कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, वे इतने परसेंट बच्चों को एडमिट करेंगे, पर्याप्त नहीं है। यह तो आप भी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल उनको क्यों एडमिट करेंगे? और अगर एडमिट कर भी रहे हैं, तो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, नहीं मालूम। आप अपने स्कूलों की फिक्र क्यों नहीं करते हैं? जो गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल हैं, जो नगर निगम के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनके बारे में आप योजना क्यों नहीं लाते हैं? उनको ठीक करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आज आप लड़कियों के स्कूलों में चले जाइए, तो लड़कियों के उन स्कूलों में शौचालय तक नहीं हैं। उनके खाने की व्यवस्था को तो आप छोड़िए, कुपोषण है वह तो अलग है, उनके पढ़ने के लिए ब्लैड बोर्ड नहीं है, उनके पढ़ने के लिए कुर्सी मेज नहीं हैं और फिर हम उनका कंपीटीशन किससे कराते हैं? जो कि अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर आते हैं। ठीक है, टेलीविजन में वही लोग आकर बैठते हैं और टेलीविजन वाले भी उन्हीं को इन्वाइट करते हैं, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे डिबेट कराते हैं, लेकिन कभी उनकी ओर भी देखिए, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, आप उनको किनके साथ कंपटीशन में लाते हैं? इन बच्चों को छठे दर्जे तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा था कि इन सरकारी स्कूलों में पहले दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही उसको खत्म कर दिया। आप देश के लिए उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इन स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने की बात कहते हैं, जिससे कि वे बच्चे जिनको आप कहते हैं कि रिजर्वेशन से आ जाते हैं, वे गरीब बच्चे जिनके लिए आप कहते हैं कि रिजर्वेशन से आकर वे मेरा हक मार देते हैं और हम लोग, जो इतना पढ़-लिखकर आए हैं, वे हमारी नौकरी ले लेते हैं, तो मेरा कहना है कि आप उनको शुरू से इस लायक बनाइए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तब फिर किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश में रिजर्वेशन की बात भी नहीं उठेगी, लेकिन आप उनको पहले एक लेवल पर लाइए और लेवल में लाकर उनको अपना कंपीटिटर बनाइए। उनके लिए इस तरह की कोई योजना आपके इस अभिभाषण में नहीं है और मैं समझता हूं कि जब आपको इतना भारी मत मिला है तो आप इनके बारे में सोचें और कुछ करें और आपको सोचना भी चाहिए।

महोदय, दुग्ध उत्पादन की बात कही गई। दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गौ संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने गौ संरक्षण के बारे में नहीं सोचा। लोग गायों का संरक्षण कैसे करेंगे? आपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में तो टैक्स एग्जेम्प्शन दे दिया

है, यह बात मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता था, लेकिन पीयूष गोयल जी यहां हैं, वे जरूर इस बात को उन्हें बताएंगे। दूध के मामले में फाइनेंस कमेटी में हम भी थे, वे भी थे और कई बार यह प्रश्न उठा कि आखिर दूध उत्पादक को टैक्स एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं आप इनको प्रोत्साहन देते? जो दूध उत्पादक हैं, जो डेयरीज हैं, उनको आप टैक्स एग्जेम्पशन दें तो एक तरह से आप उनको नरिश करेंगे। जैसे आप एग्रीकल्चर को लेकर चल रहे हैं, इसको भी आप लेकर चलें, इसके बारे में आपको जरूर सोचने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी ने जरूर इस बात को ध्यान में रख लिया होगा और मैं जानता हूं कि वे इसे जरूर उन्हें बता देंगे। प्रधान जी काफी मुस्करा रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये जरूर इसमें कुछ न कुछ करेंगे।

महोदय, इन्होंने "एक भारत - श्रेष्ठ भारत" कहा है। श्रेष्ठ भारत तो तभी हो सकता है, जब हर वर्ग के लोग खुश हों। चाहे वह गरीब हो, चाहे वह कॉरपोरेट हो। हम यह नहीं कहते हैं कि हम कॉरपोरेट के विरुद्ध हैं। यू.पी.ए. की सरकार ने ऐसे-ऐसे कानून पारित किए जिनका हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वे पारित हो गए। आज कॉरपोरेट जगत को बिल्कुल अपंग बना दिया गया। आपने इतनी तरह के एक्ट्स लगाए जैसे सेबी वगैरह कि अगर आदमी धंधा करने चलता है तो पहले सोचता है कि जेल की व्यवस्था हम कर लें, जेल जाना तो निश्चित ही है और अगर जेल नहीं जाना है तो उसके करीब पहुंचना जरूरी होगा, इस तरह की व्यवस्था बनी है। आप उनका ख्याल रखिए, उन चीजों को देखिए। कॉरपोरेट जगत ने इस चुनाव में आपकी काफी मदद की। कॉरपोरेट ने आपके ऊपर काफी मेहनत भी की। उस मेहनत का फल आप उनको जरूर दीजिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा वर्ग है, जो इस देश का 95 प्रतिशत है, जो गरीब है और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से अलग है, उसका भी जरा ध्यान रखिए, उसके बारे में भी कुछ सोचिए। उसके लिए कुछ ऐसी स्कीमें लाइए जो कॉरपोरेट के साथ-साथ उनके भले के लिए भी हों और उसके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, तो आज आपने जो सोचा है कि हम गांवों को शहर बना देंगे, आप कहते हैं कि सौ नए शहर बना देंगे, तो यह एक हसीन सपना हो सकता है। आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट खुद पारित कराया है। आप जमीन एक्वायर नहीं कर सकते, आप जमीन खरीदेंगे। आप फॉरन कंट्री से घूमकर आने के बाद जो हाई क्लास सिटी बनाने के सपने की बात कर रहे हैं, तो आप कितने हजार गांवों को खत्म करेंगे? किस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और वहां नया शहर बनाएंगे? इसके लिए आप रुपया कहां से लाएंगे? एस.आई.टी. से यह रुपया आने वाला नहीं है। एस.आई.टी. का नतीजा साल भर नहीं, पांच साल के बाद भी आपको इसमें शून्य मिलेगा, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि वे लोग भी आपसे एक कदम आगे होंगे, जिनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन...

MR. CHAIRMAN: Yes, Misraji.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: I will take only two minutes. लेकिन जहां आप

कह रहे हैं कि आप सौ शहर बना देंगे, तो केवल एक शहर की जमीन एक्वायर करने के लिए आपको दस हजार करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए होगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उससे बहुत ज्यादा चाहिए होगा। और आप इतने लाखों-हजार करोड़ लाकर इस तरह से शहर बनाएंगे, तो इस तरह से शहर बनाने की बात मैं समझता हूं कि आपको चुनाव के दौरान कहनी चाहिए थी, चुनाव के बाद अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको तो वोट मिल ही गया, अगले पांच साल आप इंतजार करते और फिर अगले चुनाव के पहले इस तरह की चार-छ: चीजें और ले आते। लेकिन इस समय आप ऐसी चीज लाए हैं, जिसको आप कभी कर नहीं सकते। आपने महिला आरक्षण की बात कही। महिला आरक्षण के संबंध में मैंने पहले ही कहा कि महिला आरक्षण 33 प्रतिशत नहीं, 50 प्रतिशत करिए। महिलाएं 50 प्रतिशत हैं। आप क्यों उनको 33 प्रतिशत मान रहे हैं? क्यों एक-तिहाई मान रहे हैं? वे आधे पर हैं। आप उनका सशक्तिकरण करिए, लेकिन उस तरीके से नहीं, जैसे आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा है, जैसे देश में अन्य जगहों पर हो रहा है, चाहे वह कांग्रेस शासित प्रदेश हों या बीजेपी शासित प्रदेश हों, चाहे पूना हो, चाहे हरियाणा हो, आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है, वह एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आज उनका सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण के बिल को आपको तुरंत पारित करना चाहिए। हमने यहां पर उसका समर्थन करके उसको पारित करने का काम किया था। सर, मुझे नहीं मालूम कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों की एक योजना बनाई थी...।

श्री उपसभापति: मिश्रा जी, अब समाप्त करिए।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: I will just take five minutes more. उन्होंने सड़कों के लिए योजना बनायी थी और पूरे देश को सड़कों से जोड़ने की बात कही गयी थी। वह बहुत अच्छी योजना थी। उसको आपने अब की बार क्यों किनारे कर दिया, यह मैं नहीं जानता। आप ही लोग बता सकते हैं कि उस योजना को आपने क्यों खत्म कर दिया, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे।

महोदय, पेंशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में सबके लिए पेंशन की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आप वृद्ध लोगों की ओर भी ध्यान दीजिए। वे वृद्ध लोग, जिनके बेटे-बहू, जिनके बच्चे उन्हें घर से बाहर कर देते हैं, वे कहीं के नहीं रहते। उनके लिए आप एक पेंशन की योजना बनाइए। वृद्ध लोगों की आप एक डेफिनेशन बना लीजिए, उनकी एलिजिब्लिटी बना लीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं 60 साल से ऊपर हो चुका हूं तो मुझे भी वृद्धावस्था पेंशन चाहिए क्योंकि मैं सीनियर सिटिजन हो गया हूं। आप एक योजना बनाइए कि कौन लोग एलिजिबल हैं? ऐसे लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए पेंशन की योजना आपको बनानी चाहिए, उस क्लास के लिए भी आपको सोचना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एफडीआई के बारे में आपने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। आप किस तरीके से एफडीआई लाएंगे, किस-किस चीज में लाएंगे? कभी कहा जाता है कि हम मीडिया

में सौ प्रतिशत एफडीआई ले आएंगे। फिर टेलीविजन पर माननीय मंत्री के इंटरव्यू में सुनने को मिलता है कि वह ठीक नहीं रहेगा। वे पहले कहते हैं कि हम लाएंगे, फिर बाद में कहते हैं कि अगर लाएंगे तो फॉरेन कंट्रीज के सब लोग आ जाएंगे। कभी आप कहते हैं कि आप डिफेंस में 100 प्रतिशत एफडीआई ले आएंगे। आप किस चीज में एफडीआई लाने की बात कर रहे हैं? यहां पर बैठकर आप एफडीआई का विरोध करते थे। आज आप एफडीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको अधिकार है कि आप अपनी पॉलिसी बनाइए। लेकिन जब आप अपनी पॉलिसी बना रहे हैं तो एफडीआई के बारे में आप पॉलिसी का खुलासा करिए, लोगों को भ्रम में मत रहने दीजिए। लोग भ्रमित न रहें, लोगों को सही चीज मालूम होनी चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

महोदय, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात कनक्लूड करूंगा। जहां तक गंगा नदी की बात है, गंगा नदी की सफाई की बात आपने कही। आपने पूरे देशवासियों को कहा। गंगा नदी हम सब लोगों से जुड़ी हुई है, हम लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है, वह पूज्य है। जिस तरीके से हम गाय को मां मानते हैं, उसी तरह से हम लोग गंगा को भी मां मानते हैं। आपने गंगा नदी के निर्मल होने की बात कही है। आपने पूरे चुनाव में कहा कि गंगा मैया को हम निर्मल बनाएंगे। अब आपने गंगा की बात तो की है, किन्तु यमुना नदी को आप भूल गए। आप यमुना नदी को क्यों भूल गए, आप अन्य नदियों को क्यों भूल गए? जब सब नदियों की बात आप कर रहे थे और कह रहे थे कि इस देश को स्वच्छ जल मिलेगा, अब पानी पीने के लिए फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्टर बॉटल की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिम बंगाल): दक्षिण की नदियां हैं, कावेरी है ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: बिल्कुल। सभी जगह हैं। आपने यह कहा है कि जितनी नदियां हैं, वे इतनी स्वच्छ हो जाएंगी कि फिल्टर वॉटर नहीं खरीदना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। इसको आप पूरा करिए। आप लोग जिस तरीके से कहेंगे, उस तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। श्रम दान से लेकर, धन दान से लेकर जिस तरह से आप कहेंगे, हम लोग आपके साथ तन, मन और धन से लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको आप करिए। आप उस तरह से मत कर दीजिएगा जिस तरह से राजीव गांधी जी ने गंगा के लिए कहा था। आज 25 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, वह और मैली होती गयी, और सूखती गयी, और खराब होती गयी। ऐसा न हो कि यही दशा अब की बार भी हो जाए। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उस तरीके की स्थिति न आए कि खाली वोट के लिए हम इस बात को कहकर रह जाएं। आप इस तरह से मत करिएगा। अगर आपने कहा है तो उसका क्रियान्वयन कीजिए और करके दिखाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका साथ ही नहीं देंगे, बल्कि हमेशा आपकी तारीफ करने का काम भी करेंगे।

जहां तक आपने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की है, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि आप मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे और उनके लिए योजना बनाएंगे। जब आपने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की, तो आपके मुंह से यह बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।

लेकिन इसके साथ-साथ अफसोस भी हुआ। अफसोस यह हुआ कि आपने मदरसों की बात तो की, जिसको हम समझते थे कि आप नहीं करेंगे, परन्तु आप संस्कृत को भूल गए। जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली, लेकिन आप संस्कृत को क्यों भूल गए? आपने संस्कृत के स्कूलों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, आपने संस्कृत के कॉलेजों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, उनके आधुनिकीकरण की कोई बात नहीं कही। संस्कृत की जो लिपि है, जो हजारों साल पुरानी है, आपने उसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप संस्कृत को भूल गए। इसलिए मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनकर आए हैं, जो संस्कृत का एक केन्द्र है, जहां से संस्कृत शुरू होती है और जहां पर संस्कृत चलती है। आप इस बात को प्रधानमंत्री जी की नॉलेज में लाइए, हो सकता है, वे भूल गए हों, उनको मदरसों की याद रही, संस्कृत की याद नहीं रही तो आप संस्कृत को याद कर लीजिए और संस्कृत के बारे में सोच लीजिए, उनकी योजना के बारे में भी सोच लीजिए, उनके उद्धार के लिए भी कुछ काम करिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उससे केन्द्र की सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। केन्द्र की सरकार यह नहीं कह सकती है कि यह लॉ एंड आर्डर का मामला स्टेट का है। कांस्टीट्यूशन की धारा 356 में यही प्रोवाइडिड है कि अगर स्टेट फेल कर जाती है, कांस्टीट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाती है, तो केन्द्र के ऊपर दायित्व आता है कि वह उसमें दखल देकर, उस पर रिपोर्ट मंगाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। आज जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दादरी में हत्या हुई, जिसकी हत्या हुई, उसकी बेवा खुलेआम नाम लेकर कह रही है कि किसने हत्या कराई है। जिस तरह से बदायूं में हुआ, जिस तरह से सीतापुर में महिलाओं के साथ हुआ और उनको मार दिया गया, जिस तरह इटावा में हुआ, जिस तरह से आजमगढ़ में हुआ, जिस तरह से देवरिया में हुआ और आज भी दो जगह पर जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। इससे आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आपको इसमें उचित कदम उठाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।

SHRI DEREK O BRIEN (West Bengal): Sir, we join the hon. President in congratulating the people of India for voting peacefully. They voted to punish poor performers and rewarded the good work. There are a lot of States where good work has been done. Those States have really been well rewarded— be it Tamil Nadu or Odisha or Bengal or other States.

Sir, we join the hon. President in celebrating this wondrous democracy where each of those 543 Members who have been elected to the Lok Sabha has a beautiful story. I don't have the time to tell you all the stories. But, one story bears special mention of a region where starvation deaths were an order of the day till 8-10 years ago. And, those starvation deaths were due to people in that area ate ant eggs, because they did

not have anything else to eat. Today, that region – Jangal Mahal – is represented by a 28 year old doctor. She is the first woman to come to the Lok Sabha and take her oath in Al-chiki (Santali language). Sir, this is our wondrous democracy; let us celebrate it.

Sir, my party, the Trinamool Congress, would also like to place it on record the people who do all the hard work but often get unnoticed; it is the Election Commission of India. It has conducted this election in the best way possible. I do not get into percentages today. But, in all the happiness of the new Government – someone has mentioned this before – the overall vote share was 30 per cent. So, that is a humble pill which will, perhaps, temper this mandate.

Sir, everyone makes election promises. Those who are in opposition last are in Government this time and vice-versa. One promise they make every time is about Women's Reservation Bill. All talk, no go. The last time's Opposition and this time's Government, and between them all the major parties, the number of women they brought to Parliament in spite of promising 33 per cent or one-third is between 8 per cent to 13 per cent. That is the average. The all India average is 11 per cent. Sir, we, at the Trinamool Congress, are indeed proud to say that out of our 34 Members of Parliament, eleven are women. We have already done the women's reservation; 33 per cent of women from Trinamool Congress are already in Parliament. If anyone tries to sneakily take credit for giving women the reservation should remember one thing; you may all want to share the credit now, but please remember, you all have talked, but we have done it.

Sir, what will be our role for the next few years? We will watch; we will play the role of a constructive Opposition. We will support good initiatives and we will oppose them when necessary. Sir, we believe, all these new programmes which will be announced, which may be announced, need to be put through what we call the three-way-test. The first test is, how will you implement your programmes to touch the poorest of the poor. That is our first test. The second test is, how will you pursue unity in diversity and secure safety of all minorities, women and SCs/STs? This is the second test where we will subject all your programmes. The third one is, how will you deliver economic stability?

Sir, in the next few minutes–because we have two speakers from our party, I will just take the first half–one would have been tempted to talk about all the things that

you did not say or the Government missed out in the President's Address. We will not fall into that trap. We will give you the benefit of doubt and we will say that maybe you will bring all this up in Part-A of the Budget Speech, which seems the logical thing to do; otherwise, very often, the President's Address and the Budget Speech become photocopies of the same thing. So, we will wait for the Budget Speech, especially Part-A of the Budget Speech. We will restrict our response to eight or ten points to give specific and constructive suggestions on the President's Address itself.

Coming from a party which has just come with the blessings of the people, I am sure, you will listen to us with some attention. Sir, specifically, we start with para 9 where he talked about rural infrastructure. Our specific suggestion from the Trinamool Congress is, and we urge you, to set up the Rural Infrastructure Mission. The party in power loves catchy acronyms and that kind of things, this should also pass your acronym test; that also sounds nice, the rhyme sounds quite nice, but more seriously, the Rural Infrastructure Mission should have two broad objectives. First, build bridges and, second, build pucca roads in rural areas. These are two objectives.

Sir, paragraph 8 talks of food inflation. Lots of speakers before me have spoken about this. Sir, in West Bengal, we are providing tribals rice at Rs. 2 per kg. Our suggestion, Sir, is that this is a good scheme for tribals. Satishji also spoke about forest rights of tribals. But, on the specific scheme, can this rice at Rs. 2 per kg. for tribals be passed on to the rest of the country?

Sir, our third suggestion, which is for para 10, on agriculture is, agriculture engages 50 per cent of our work force, offers livelihood to 75 per cent of our people, consumes 80 per cent of our water, 25 per cent of our power, and must be availing 70 per cent of our subsidies. For agriculture, we have two specific suggestions. The first is, the Minimum Support Price for agricultural products and the loan waiver to poor farmers; the operative word being poor. West Bengal, in fact, has a land, agriculture and industrial Policy. And, more interestingly, we have a Land Policy which was implemented about 18 months ago, and we would urge you to take a very close look at that.

Paragraph 11, we could not agree with you more. Each drop of water is precious. In the Trinamool Manifesto, three years ago, we made a promise to have 55,000 water bodies. In three years, 55,000 is not the number, it has become 1,06,000. The bureaucrats, perhaps, went and counted the numbers. My colleague, Mithunda – you are not the

only person taking helicopter rides—also went for a few helicopter rides over Bengal and saw lots of water. So, 1,06,000 is the number. The programme there is called *Pani Dharo, Pani Bharo*. In fact, the basic concept of what we are suggesting is that there are lots of State Governments who first thought out, then, tested out programmes. Those programmes have been tested on a small scale, before they have been rolled out on a large scale. Our observation is, that is the way to do it. I want to give you another example which would relate to paragraph 19, which is about the girl child and women. Sir, there are so many issues. In fact, sadly, seven lakh girls are killed every year before they are born. Seven lakh! It is not a coincidence. We are happy that the Prime Minister has chosen Bhutan to be his first neighbourhood destination, but it is a sad irony that the population of Bhutan, which is seven lakh is equal to the number of female girl child killed before they are born in India.

Sir, through you, we want to bring to the notice of this new Government a Scheme which is called *Kanyashree*. Now, how does this work? The problem here was that lot of girls had to stop their education. So, that was the problem. They stopped their education because they need to get married very quickly. *Kanyashree* is a Scheme, started exactly one year ago, here how it works, the girl's family gets Rs. 500 per year from Class 8, 9, 10, 11, 12. If she wants to continue her studies after class 12, the family gets Rs. 25,000. Two things happen — economic help to the girl who gets educated and the child marriage is also stopped. Under this *Kanyashree* Scheme, thirteen lakh girls and their families have already registered, and by the end of the year, the number would go up to seventeen lakh. Sir, this Scheme was so useful that the U.N. have now tied up with the West Bengal Government to take this Scheme ahead.

Sir, being a Member from West Bengal, I am giving you one example from West Bengal, but the thought we are trying to leave you behind, I am sure, my colleague, Dr. Maitreyan, is going to speak from Tamil Nadu, I think, after this, there have been such examples from many, many States, which have been tested, tried and moved on.

Another one is, medicines, where generic drugs are sold at 67 per cent discount. Real stories, real schemes implemented, loved by voters, and that is why they are sending us here.

We strongly support and approve the decision to bring back black money, paragraph 22, but we don't know who wants to take the credit. Let us not forget in all this brouhaha that this is the Supreme Court Judgement, and we are happy that you

are following the Supreme Court Judgement. But whatever it is, it is a step in the right direction. I don't share the cynicism of not anything happening in the next five years, we are optimist.

Sir, in paragraph 24, you have mentioned about comprehensive reform of the Judiciary. We, at the Trinamool Congress, want to take it one step further. We believe, there is serious corruption in the media. Some of our most brightest men and women, some of the most brightest talent in this country are media professionals. We respect them very, vey much. But the media corruption is an issue which needs to be taken up at the earliest because first, we were all concerned about paid news, but after seeing what has happened in the last few months, there is a new form of news, which is beyond paid news, this is super-paid news. Sir, in paragraph 29, you talk about, 'set up a task force to review our MSME sector'. I know there is a lot of discussion on this mirage, the Gujarat Model, so I am tempted to give you one example. For the MSME sector I suggest you to follow one State where the model was right. The best way to judge MSME perhaps is to see how banks are lending to MSME. You know a lot of banks want to lend. If the percentage of lending goes up, the things are well. Last year, bank lending in Karnataka increased to 48 percent. Good. In Gujarat, it was 20 something per cent. Not bad. In my State, it was 105 per cent. Maybe, we can share with you some ideas as to how to revive the MSME. Thank you, Mithunda, for being the only one who is clapping his desk. ...*(Interruptions)*... Okay, thank you, Sir.

Sir, paragraph 20 was music to our ears and I quote, 'highest priority will be accorded to bring the eastern region of this country on par with western region in terms of physical and social infrastructure.' Very good, excellent. 'Look East' policy is acceptable but we will prefer, from 'Look East' it becomes 'Act East'. 'Act East' is even better because Kolkata is not only the gateway to North East, Kolkata is also the gateway to South Asia. In fact, we are also promoting Yoga in Bengal. The President also through his speech mentioned Yoga. So, it is a very good system where every morning this Government gets up and the sun rises in the east. So, it is a very good idea to do some Suryanamaskar every morning before you start your Government works. We will assure you that it will bring lots of good luck. Mithunda had written a line for me in Hindi, but I dare not deliver it because he is sitting here. He said, "सुबह सूर्य प्रणाम करने से दिन अच्छा जाता है।" ...*(Interruptions)*... Sir, that is the basic concept which we are trying to bring about. We are trying to communicate through you, Sir, to this Government and respond to the President's Address. Bring the States on board. If you

want an AIIMS in Bengal, yes, give us hundred days, we will find you a location for a new AIIMS. If you want to talk about the border areas, especially States like ours, which have Nepal, Bhutan, Bangladesh, sensitive areas, talk to us, we will sort things out. If you are talking about modernizing Madrasas, it is a good idea. Don't go cut-brush and then do it. Consult with the States, and then do it. Funding for education— you are talking about IIMs, IITs, very good. Keep counting the IIMs and IITs. Our requirement: we believe, more than IIMs and IITs, with no disrespect to them, more polytechnics are needed. If you want to improve telecommunication in rural areas, there again bring the States on board. E-governance, my colleague who will speak after this will give you all the great things we have done on e-governance. So, this is the basic feel we have. As I said, we have restricted our comments to what has appeared in the speech. Sir, the States are not subordinate jurisdiction to the Centre. They are partners. Treat us as friends and we will never let you down. Treat us as hostile, the people will feel let down. In the hope that this new Government has learnt from coercive federalism of its predecessor, all we can say is that since you have loved all kinds of acronyms, you had the last one, which says the '5 Ts', tradition, talent, tourism, trade and technology. Very nice. But also remember before the 'T' comes the 'S', that is, the States. Thank you, Sir.

डा. वी. मैत्रेयन (तमिलनाडु): सर, आपने बहन जी के प्रतिनिधि के ऊपर जो मेहरबानी की है, अम्मा के प्रतिनिधि के लिए भी मैं आपसे मांगूंगा कि आप घंटी मत बजाइए। हम खुद संयम रखेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I belong to the House.

DR V. MAITREYAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, on behalf of my party's General Secretary, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, and on my own behalf, I welcome the comprehensive and inclusive Address by His Excellency, the President of India, to both the Houses of Parliament, yesterday. The Address outlines the policy priorities of the BJP Government very eloquently and with absolute clarity. The Address reflects the high expectations of the people who have given a decisive mandate. I congratulate my esteemed and dear friend, the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his spectacular victory. I would also, at this stage, like to thank the people of Tamil Nadu who have placed their overwhelming immense and unshaken faith in the leadership of Puratchi Thalaivi Amma by sending 37, out of 39, MPs to the Lok Sabha.

On 17th May, one day after the massive verdict, I had a chat message. I quote,

"India is a strange country. Earlier, there was no Government; now, there is no Opposition". And, what a mandate! नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत लम्बा खींचा। उन्होंने कहा कि हमने यह किया, वह किया, कि आप लोग जो सोच रहे हैं, वह हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया है कि आप लोगों ने अभी जिस स्कूल में एडमिशन लिया है, हम उस स्कूल के हैडमास्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि यदि आपने इतना किया है तो जनता ने आपको क्यों हराया? उसने आपको हराया ही नहीं उखाड़कर फेंक दिया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। यहां तक कि नामोनिशान नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यहां तक कि नामोनिशान भी नहीं है। ...**(व्यवधान)**... What a mandate, Sir, both, at the national level as well as in Tamil Nadu! I would be comparing both. At the national level, the BJP got a comfortable and an independent majority. As far as Tamil Nadu is concerned, it was virtually a Jaya Tsunami. She won 37 seats, out of 39. This is all the more very significant because of certain reasons. The legendary late M.G.R. founded the party, Anna Dravida Munnetra Kazhagam in 1972. In 1976, he changed the name of the party to All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, by adding the two letters A.I. to the ADMK, M.G.R. gave the party a national perspective. Thirty-eight years later in 2014, by winning 37 out of 39 seats in Tamil Nadu, that too on our own strength, Puratchi Thalaivi has given a national recognition to our party. It is also important because ever since 1967, elections in Tamil Nadu, whether it was for Assembly or for Parliament, were always fought with allies. All major political formulations had alliance with somebody or others. Even the late M.G.R. did not venture to contest alone. He had contested sometimes in alliance with the Comrades and sometimes with our Congress friends. But, for the first time, in 2014, Puratchi Thalaivi took a bold decision of contesting alone. Why did she take that decision? She took this decision based on the performance and track record of the Government, headed by her, in the last three years; based on the unflinching loyalty and the hard work of the one-and-a-half crore cadre of the Party; and based on the immense support of the people of Tamil Nadu. And, you will be astonished that the AIADMK, contesting alone, got 44.3 per cent of the vote share in these elections. The next party, which came after us, the DMK, got 23.6 per cent of the vote share, a wide gap of nearly 20 per cent vote margin. That was the importance of these elections. Hence, it is purely Puratchi Thalaivi Madam's victory, Madam's victory and Madam's victory only. Another important factor in these elections was that the restrictions imposed on our Party, the restrictions imposed *...(Interruptions)...*

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): What about 1996? *...(Interruptions)...*

DR. V. MAITREYAN: If I start talking, you have no numbers there, and very soon you will have no numbers here also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay, now please let him speak.

DR. V. MAITREYAN: Sir, severe restrictions were imposed singling out AIADMK in this election process. In fact, because of the huge mass base, lakhs of people used to assemble to hear Madam's election campaign. Obviously, you have to have election campaign meetings on the outskirts of the cities, only in the constituency.

Naturally, people come for that. Unfortunately, the restriction put forward on us was that candidates cannot be in the dais where Madam would be Addressing. Leave alone candidates being present there, even the name of the candidate was not to be taken. In fact, halfway through the election, in more than 15 to 20 election meetings, Puratchi Thalaivi Addressed the people of Tamil Nadu without the candidate on the dais and without even mentioning the name of the candidate for that constituency. Even after that, if we get 44.3 per cent of the vote share, it is Madam's victory; the vote is for Madam. Another important factor in this election is the huge victory margin. We won 37 seats out of 39 that we contested. In four seats only, that is, Vellore, Coimbatore...*(Interruptions)*... No, no; I know how the other meetings were arranged — how the meetings for yuvraj were arranged and how the meetings for the Congress President were arranged. I don't want to go into that now.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Go ahead.

DR. V. MAITREYAN: So, the huge victory margin in four constituencies, that is, Coimbatore, Vellore, Central Madras and North Madras, the victory margin was less than one lakh but in the rest of the 33 constituencies the victory margin was between one lakh to three lakhs. In fact, in Thiruvalluvar parliamentary constituency, it was 3.23 lakhs. So, in almost all parliamentary constituencies, the victory margin was more than a lakh. That again shows how the Opposition was decimated in this election.

SHRI NARESH AGRAWAL (Uttar Pradesh): What about Shivganga?

DR. V. MAITREYAN: I will come to that. I will never forget that. Sir, the essential theme in this election campaign by *amma* was anti-Congressism, – to throw out the corrupt Congress-led UPA Government that had plunged this country into total collapse and darkness due to the policy paralysis. In fact, Mr. Modi also had a similar agenda. He spoke about a Congress-*mukt Bharat*. To a large extent, he was successful, but, still, he allowed 44 people from Congress to win in the country. But in Tamil Nadu, Madam's success mission is absolute and total. We have achieved a Congess-*mukt*

Tamil Nadu as far as the Lok Sabha elections are concerned. The people of Tamil Nadu were so angry with the Congress-led UPA for the betrayal of the causes of Tamils that they not only gave Congress a zero, but also its ally, the DMK, a big zero. In fact, the Congress lost deposit in 38 out of 39 constituencies it contested. The former Finance Minister of this country...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I think the speech is on Motion of Thanks on the President's Address.

DR. V. MAITREYAN: It is in relation to the election also...*(Interruptions)*... I have 30 minutes...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Maitreyanji.

DR. V. MAITREYAN: I speak for my pride, Sir...*(Interruptions)*... Why should I not speak? I don't have to oblige him. People have rejected them out, thrown them lock, stock and barrel into Bay of Bengal. Why should I not speak?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is a Member of the House...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Why should I not speak, my friends? Why should I not speak about my achievements?...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is a Member of this House...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Why should I not speak, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, he is a Member of the House...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot ignore him. Mr. Tiruchi Siva, he is a Member of the House. You cannot ignore him...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I have not taken his name...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Maitreyanji, if you can concentrate on the President's Address, that will be better. If you can concentrate on the President's Address, that will be better. That will be better.

DR. V. MAITREYAN: Sir, the President's Address mentions about the election. It congratulates the election...*(Interruptions)*... I am speaking only about that. Sir, the

former Finance Minister, a great man, who was responsible for the entire country, did not campaign in the rest of the country. He did not campaign even in Tamil Nadu; he campaigned only in one constituency, of his son, and his son lost the deposit!

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: This is too much.

DR. V. MAITREYAN: Yes, it is too much for us. The former Finance Minister concentrated only on one parliamentary constituency. Even the Tamil Nadu Congress blamed the former Finance Minister for the total rout of the Congress. The former Finance Minister is singularly responsible for the economic slide-down. I urge the BJP Government and the Finance Minister to present a White Paper on the economic situation and the financial position during the last ten years of the UPA misrule.

Now, I come to the President's Address...*(Interruptions)*... I am taking them one-by-one. I have two President Addresses in my hand — the 2014 President's Address of the BJP Government and the 2009 President's Address of the UPA Government...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Rapoluji, please.

DR. V. MAITREYAN: No, no, I will tell you how it is not. I will tell you. In 2009 President's Address, in point no. 8, they mentioned that 'there would be ten broad areas of priority for my Government for the next five years.' They listed so many of them— internal security, preservation of communal harmony, governance reform, prudent fiscal management, etc., etc. They had completed five years at that time. What is the report card? Today, of course, the Leader of Opposition gave a report card. But the people of the country gave marks for that report card — 44 out of 543. Those are the marks that the people of the country gave to that report card...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Don't interrupt.

DR. V. MAITREYAN: Sir, in the 2009 President's Address, they had mentioned their agenda — the first hundred days' agenda. It was said, 'My Government will initiate steps within the next 100 days of the following measures'—hundred days of the formation of the Government in May, 2009. The first item in that 100-day agenda was, the early passage of the Women's Reservation Bill in Parliament providing for one-third reservation to women in State Legislatures and Parliament. Sir, full five years have passed. This House had passed it earlier. But for five years, they did not even move an inch on that. Compare that with the way the Telangana Bill was passed. I don't want

to go into the merits of the Bill because it is a done-deal. I don't want to go into the merits of the Bill but the way the Telangana Bill was forced on the Lok Sabha at that time, they could have done a similar thing for the Women's Bill also. Why didn't they do it? When it came to Telangana Bill, the television channels were blocked, doors were closed, inside the House whatever was done is past; but in case of Women's Reservation Bill, even if a one-Member party objected, they took that as an escape-route and said that there was no consensus. This is how they behaved as far as their first item in the hundred-day agenda was concerned. In fact, as far as AIADMK is concerned, we are committed to the Women's Reservation Bill. In fact, Dr. Puratchi Thalaivi is the only leader and our Party is the first party to reserve 33 per cent of the seats in the Party to women. Hence, we strongly urge the Government to pass the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha next month itself in the Budget Session. That will send a strong and a positive signal to the country. Of course, in their 100-day agenda, they had mentioned so many other things also. They have mentioned about the roadmap for judicial reforms to be outlined in six months and implemented in a time-bound manner — outlined in six months and implemented in a time-bound manner. Then, they also talked about a delivery-monitoring unit in the Prime Minister's office to monitor flagship programmes and iconic projects and report their status publicly...*(Interruptions)*... But, then, the custodian of the country so has said in this House that 'I am not the custodian of the files even.' They talked about a delivery-monitoring system...*(Interruptions)*... The files were missing. He said in the House here itself that 'I am not the custodian of the files.' The then Prime Minister said so on record in this very House. A person who could not even safeguard the files talked about the delivery-mechanism.

Sir, in the President's Address, there is a mention about the *Swachh Bharat Mission* which will seek to provide each household access to toilet by 2019, on the occasion of 150th anniversary of Mahatma Gandhi. It is a very noble gesture.

In fact, our Chief Minister, *Puratchi Thalaivi*, when she issued a statement yesterday welcoming the President's Address, mentioned, and I quote, "I have set a more ambitious target of Tamil Nadu becoming open defecation-free State by 2015 and we will redouble our efforts to achieve this challenging goal and look forward to Government of India's support."

In this regard, I would like to quote a newspaper item which mentioned that in

the recent unfortunate incident which took place in UP, the Union Water and Sanitation Ministry has asked the State Government to take a cue from Tamil Nadu to set up women-specific integrated community sanitation complex to prevent such crimes. So, we have been pioneers in this and we expect the Government of India to help us further in achieving our goal by 2015.

Sir, I now come to the vexatious issues of Cauvery and Mullaiperiyar. Sir, on 3rd June, our Chief Minister, *Puratchi Thalaivi,* came to Delhi, met the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and submitted a memorandum. In fact, with reference to the Cauvery issue, the Cauvery Tribunal gave its final Order on 5th February, 2007 for full five years, the UPA Government, of-which our opponents from Tamil Nadu were also a part, did not do anything to even get it notified in the official Gazette of India. After we came to power in 2011, our Chief Minister approached the Supreme Court, we got the Order and accordingly, the Cauvery Tribunal's final Award was notified in the Gazette of India on 19th February, 2013. But then, mere notification is not enough. For that Tribunal Order to become effective and implementable, we need to have the Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee. From February, 2013 till the elections the UPA Government did not bother to appoint that Committee. In fact, our Chief Minister, when she met the hon. Prime Minister and gave this memorandum, appealed to him that the Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee be formed immediately.

Sir, another issue that she had mentioned at that time was the Mullaperiyar issue. The Supreme Court, in a historic judgement dated 7th May, 2014, has ruled in favour of Tamil Nadu. Again, in all these vexatious problems, be it Cauvery or Mullaperiyar, our Chief Minister got positive results only from the Supreme Court and not the previous Government of India. It declared in favour of Tamil Nadu and declared Kerala's amended Act of 2006 as unconstitutional and *ultra vires*. Sir, the Court allowed the Government of Tamil Nadu to increase the storage capacity of water in the dam to 142 feet under the supervision of a three member-supervisory committee. Our Chief Minister has requested the hon. Prime Minister to nominate the Central Government's nominee at the earliest. There were some news items in the papers—in fact, I thought that any news item that appears in *The Hindu* would have some validity—that mentioned that the Water Resource Ministry had moved swiftly on these demands and that draft Cabinet Notes had also been circulated. But I hear now, people whisper into my ears, that the present Government has not done anything and they have not taken any

decision on that. In fact, representatives from Karnataka have also passed some Resolutions. They have come to Delhi today and they have also met the hon. Prime Minister. As far as we are concerned, when we approached the Supreme Court for the Management Board to be formed at the earliest, the then UPA Government, through its Additional Solicitor General, Mr. Siddharth Luthra, told the Supreme Court that the UPA Government is committed to forming the Cauvery Management Board. The people of Tamil Nadu are eagerly hoping that the new regime under Shri Narendra Modi will take a positive and early decision and appoint the Cauvery Management Board at the earliest. सर, बहुत उम्मीदें हैं इसमें। हम आपसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको कर दीजिए। हम मानते हैं कि आप 56 इंच छाती वाले हैं इसलिए without bias, without any partiality, please do what is judicially applicable, what is committed in the Supreme Court. We do not want favours from you. When my Chief Minister met the hon. Prime Minister and when she Addressed the Press, people asked, "Have you asked for any economic package?" She said that she had not asked for any economic package. All the time, she interceded, 'Please pay us our arrears; please pay what is due to us'. So, that is what we are again asking. After the Supreme Court's orders both with reference to Cauvery as well as to Mullaperiyar, fulfil the commitment of Government of India. Whether it is the UPA or the BJP Government, it is a Government in continuity. We demand, we expect, and we hope that they will do justice to the people of Tamil Nadu.

Sir, now I come to another thing with reference to the power problem. Tamil Nadu has been facing a lot of problems in the power sector. In fact, at this moment, I vividly remember my dear colleague, Mr. Narayanasamy. In fact, I used to call him 'two-weeks Narayanasamy' because for the last two years, ever since the Kudankulum Nuclear Plant came into the picture, he always used to say—every two weeks he used to land on the Chennai Airport—in two weeks Kudankulum will be operative. Two years have gone by that time. But, now, ultimately, the Kudankulum Nuclear Power Plant's first Unit has started functioning and it is generating 1000 MWs. In fact, when the previous UPA Government was there, my Chief Minister had written to hon. the then Prime Minister that because of the special situation of power problem in the State, at least, initially, say, for the first one or two years, the entire 1000 MWs be given to Tamil Nadu. Afterwards, it can be divided. But the UPA Government never bothered even to reply or acknowledge it. I will come to that again later. Now, out of 1000 MWs to be generated, Tamiil Nadu's share will be 462 MWs; Karnataka's share will be 221 MWs; Kerala's share will be 133 and Puducherry's share will be 34 MWs. There is an unallocated share of 150 MWs. If you give the entire 1000 MWs for one or two years to us, we

4.00 P.M.

will be very happy; we will praise you and we will be thankful to you. If that is not possible, at least, the unallocated share of 150 MWs may be given to us because the plant is in our place. Kerala refused it. Then it was given to us. So, give additional power of Kundankulum Plant to us.

Now, I come to two pet issues of mine. Sir, I now refer to the repeated attacks on the Indian fishermen from Tamil Nadu by the Lankan Navy. Sir, in fact, I show you this book. Sir, this is a very nice book. This is a compilation of the letters written by my Chief Minister from 2011 to 2014 to the then Prime Minister of India. It has 281 pages; 89 letters written, and half of them are nearly on attacks on Tamil Nadu fishermen. Leave alone acting on these letters, leave alone responding, there was not even an acknowledgement from the then Prime Minister of India on these letters. So, I humbly submit this book here...*(Interruptions)*... I hope that they will not give any room for the second volume. In fact, nearly 40 letters written on this issue are related to the last three years. If you see, in the last four months, six letters were written. No response; no reply! So, the action of the UPA Government was deplorable. Now, with the Modi Government, two incidents have happened one, on the 1st June, and the second on the 7th June. On both the occasions, when it comes to the rights of Tamil Nadu and the welfare of the people of Tamil Nadu, my Chief Minister will leave no stone unturned. So, she wrote the letters on both the occasions. The difference this time is that on both the occasions the Modi led Government acted swiftly...*(Interruptions)*... On both the occasions, fishermen who were arrested by the Lanka—I again place it on record; I refuse to call that country as 'Sri Lanka' because it doesn't deserve the adjective 'Sri' ever since 2009 when the genocide took place.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not make such comments, please.

DR. V. MAITREYAN: They got the fishermen released promptly, but then we need a lasting solution. People talk about international boundary, that our fishermen have crossed the international boundary and all those things. We don't accept it because when a fisherman goes inside the sea, he does not decide which is the international boundary; he goes according to the flow of the water, and the present Prime Minister knows that very well. So, he will not talk about international boundary. Sir, I want you to be a little more liberal to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am always liberal to you. Why are you saying this?

DR. V. MAITREYAN: Thank you, Sir. So, the Prime Minister knows about it very well because in Tiruchi, on September 26, 2013, BJP had a rally and Mr. Narendra Modi came to that rally and he spoke about the fishermen issue. I just want to quote that. He compared the fishermen of Tamil Nadu and Gujarat. He said, "Being coastal and border States, we also have common problems. As Gujarat fishermen are arrested and tortured by Pakistan, the fishermen in Tamil Nadu are often arrested by the Lankan Army." This is Mr. Narendra Modi's speech in Tiruchi on September, 2013, and then he goes on, "आप लोगों को लगता होगा कि हमारे फिशरमैन को श्रीलंका उठाकर के क्यों ले जाता है, हमारे फिशरमैन को पाकिस्तान उठाकर के क्यों ले जाता है? मित्रों, यह ले जाने की हिम्मत इसलिए करते हैं, क्योंकि समस्या उस समुद्र के भीतर नहीं है, जहां मछुआरे जाते हैं। समस्या उस दिल्ली सरकार की दुर्बलता से है, जिसके कारण यह दुर्दशा होती है"। वह दुर्बल सरकार तो अब गई, अब तो मजबूत सरकार आई है, तो हम मांग करते हैं कि इसके बारे में आप कुछ करें। We need everlasting solution. "मूल कारण यह है कि पड़ोसी देश हिन्दुस्तान को टेकेन फॉर ग्रांटेड मानते हैं और इसके कारण यह परिस्थिति पैदा होती है।" These are the words of Shri Narendra Modi.

Every time some incident happens, we write a letter and then the Government interferes and the fishermen are released. This cannot go on and on. We need a lasting solution. When my Chief Minister wrote a letter to the hon. Prime Minister on the 8th June, she mentioned about it. She mentioned, "A permanent solution to this problem must be found by a decisive initiative under your leadership. In my memorandum dated 3rd June, I had outlined the contours of some of the elements of such a permanent solution, including the retrieval of Katchatheevu which was historically part of India's territory until it was unilaterally ceded to Sri Lanka by the Government of India. Talks between the fishermen of two sides could also help resolve day-to-day issues, provided they are held in a conducive atmosphere and in an accommodative spirit of mutual understanding and reciprocity. Even on this limited issue, the Lankan side had adopted obdurate and obstructive attitudes which led to the failure of the last round of talks held in May, 2014. In order to put an end to the unabated, brutal, unprovoked attacks on and abduction of our fishermen by the marauding Lankan Navy, the time has come to lay down a time-bound action plan to achieve long-term permanent solution to the problem and also to put in place a strong and robust diplomatic response." We talked about coercive diplomacy. The then Government talked about friendly diplomacy. We insisted that there has to be coercive diplomacy. "I am confident

that with the Government of India and the Government of Tamil Nadu acting in concert, it would be possible to achieve a permanent solution to this vexatious issue."

Lastly, I come to the issue of Eelam Tamils. The Congress Party, in their 2009 Presidential Address at the beginning of their second five-year term, mentioned, "We will support initiatives in Lanka, which can lead to a permanent political solution of the conflict there and ensure that all Lankan communities, especially the Tamils, feel secure and enjoy equal rights so that they can lead a life of dignity and self-respect. India will make appropriate contribution to rehabilitate those affected by the conflict." This is what they mentioned in 2009. Five years have passed and nothing has changed on the ground. Now, my Chief Minister met the hon. Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and in the memorandum, she has mentioned, "There are very strong sentiments among Tamils and in Tamil Nadu on a range of issues relating to India's relations with the present regime in Lanka in the aftermath of the final stages of the civil war in Lanka which was marked by an ethnic pogrom and genocide perpetrated on the Tamil minority in Lanka." Sir, the Tamil Nadu Legislative Assembly had already passed four unanimous Resolutions condemning the continuing discrimination against the Tamil minorities in Lanka and violation of the human rights. So, she has requested the hon. Prime Minister that India should sponsor a Resolution in the United Nations condemning the genocide in Lanka and to hold to account all those responsible for the genocide, thereby rendering justice to the Tamils in Lanka.

The Resolution should also provide for holding a referendum amongst Tamils in Lanka and displaced Tamils across the world for the formation of a separate 'eelam'. Now, the moment we mention the word 'eelam', or, 'referendum', we find that these words are allergic to both the national parties. Immediately, they talk about Kashmir or Arunachal Pradesh, and, say that if you talk about referendum and other things in Lanka, what will happen to Kashmir. But, how long can the people of Tamil Nadu and the Tamil race go with these arguments? In fact, there is a very good point in saying that Tamil race has become a sacrificial goat in the geo-political map and the strategy of India. Even taking for granted their pet theory, the Congress and the BJP harp on the 13th amendment, the so-called Rajiv-Jayawardene Accord.

MR. DEPUTY CHAIRMAN (Prof. P.J. KURIEN): Please conclude.

DR. V. MAITREYAN: Sir, I will take only four minutes. Please remember the concession given to Mr. Satish Chandra Misra.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I can remember you...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: In fact, when the Lankan President came to India to attend the swearing-in ceremony, the next day, he had a one-to-one meeting with the hon. Prime Minister. The Secretary in the Ministry of External Affairs, Shrimati Sujatha Singh, met the Press, and, I quote the official version as told by her. "Shri Narendra Modi requested the Government of Lanka to expedite the process of national reconciliation in a manner that meets the aspirations of the Tamil community for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Lanka." Early and full implementation of the 13th amendment and going beyond will contribute to this process." This is what the Foreign Secretary said. The 13th amendment introduced provincial councils with specific powers like land and police. And, then, what has been the response of the Lankan Government! On Thursday, speaking in the Lankan Parliament, their Minister of External Affairs, Prof. G.L. Peiris, said that the Government would not be implementing the 13th amendment in its current form. Prof. Peiris said that the President, Mahinda Rajapaksa, had informed the Indian Prime Minister, Shri Narendra Modi, about the Government's decision when they met in Delhi. This is what the Lankan External Affairs Minister said in his Parliament. Now, where do we go from here? Even your pet theory of 13th amendment, the Lankan President is not willing to accept! So, where do we go from here? That leads to the approach of the Government of India towards the foreign policy. The 2014 President's Address, unfortunately, does not mention anything about Tamils, Eelam Tamils, the 13th amendment or anything of that sort.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

I even see it from a positive point. Probably, Mr. Narendra Modi wants to start on a clean slate. I want to remind Mr. Narendra Modi is an outsider to Delhi. I mean to say this in good sense, not otherwise. He has shaken the Delhi sultanate. Contrary to the popular expectations, his actions...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Don't say 'sultanate'. Ours is a democracy...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: It is my privilege. I will say whatever I want to say. You cannot dictate me to say what you want...*(Interruptions)*... Sir, I will take only three minutes more. Whatever concession was given to *Behanji's pratinidhi,* it should be given to *Amma's pratinidhi* also. So, my strong suggestion to the Prime Minister is not to depend upon the babus of the External Affairs Ministry. Whether they are

Narayanans or Menons, please do not depend on them because they always take you to the failed path of the last three decades. They will only tell the usual story. I read in the papers that probably the Government of India is thinking in terms of appointing a Special Advisor in the Ministry of External Affairs also. I don't want to go into the details of that. Whether you appoint somebody or not, that is a different issue but my submission is that, at least, with regard to these issues, especially with reference to Lanka, the Tamil issue, you have got very good friends in your own party who are well-versed in this, who will not talk about the Lankan side and who knows the problems of the Tamils. The best example is Shri Yashwant Sinha, the former External Affairs Minister. Please listen to him. Please ask him what needs to be done. He will guide you properly. Lastly, with respect to the foreign policy of the country—we have already said, I have said, Mr. Raja has said and others have also said—the approach of the Government of India needs to be revisited. I will again quote Mr. Narendra Modi, when he came to Chennai on 19th December, 2013, to Address the 11th Nani Palkhivala Memorial Lecture. He gave his vision about the foreign policy. I will quote only one line from that. He harped on the familiar key making State Governments' stakeholders in the pursuit of foreign policy. In fact, on several occasions, I remember distinctly at least on two or three occasions, Mr. Modi, in his speeches, has mentioned that as far as foreign policy is concerned, they have to be formulated and guided in consultation with the State Governments because it is the State "Governments which are affected. After all, we are a part of India. Where is the country if we are not a part of that? Where is the country if we are not a part of the decision? So, our foreign policy needs to be revisited where States have to be consulted.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

DR. V. MAITREYAN: Then, I come to the last point because when we say that the States have to be consulted, the President's Address mentions about cooperative federalism. Sir, I will finish in two minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no, you just said 'three minutes', out of which two minutes are over.

डा. वी. मैत्रेयन: आपने बहन जी के प्रतिनिधि पर जो मेहरबानी की, वही मेहरबानी मुझ पर भी कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, we have to manage time...*(Interruptions)*... No cross-talking, please.

DR. V. MAITREYAN: It says, "In order to engage with States on the national issues, my Government will reinvigorate fora like the National Development Council and the Inter-State Council. The Centre will be an enabler in the rapid progress of States through cooperative federalism." In fact, my party's one of the strongest bases is cooperative federalism. And, I would like to remind Mr. Narendra Modi about his one more speech. Couple of years ago, when he spoke to an audience in Ludhiana, he gave a discourse about the federal structure of the country. The Constitution of India provides for cooperative federalism and for the Centre to give powers to States through decentralisation. He quoted Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar's observation in the Constituent Assembly clarifies the power of the States. "The Constitution is a federal Constitution in as much as it establishes a dual polity. The Union is not a league of States, united in a loose relationship, nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution."

MR. CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, please conclude.

DR. V. MAITREYAN: "Both derive their respective authority from the Constitution." I would urge the Union Government to respect this cooperative federalism in letter and spirit, be it the domestic policy, be it the State-specific policy, be it the foreign policy. With this, I welcome this President's Address and offer our support on this issue. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. We need cooperation in time management also. Now, the hon. Leader of the House.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to the hon. President for his Address to the Joint Session of both Houses of Parliament. The Address is the present NDA Government's roadmap for the next several years. It is not an agenda for one year, but it is a futuristic vision of NDA, and, therefore, when a new Government does take over, it is but obvious that the Government gives its larger vision to the country and to the world as to what is the roadmap that it thinks that India must get on to. Sir, we have just finished our General Elections, which is the largest electoral activity in the world anywhere, and we are proud of the fact that India is a vibrant successful democracy, ensuring free and fair elections, where there is a peaceful transformation of power from one Government to another. And this takes place in a highly democratic manner. The Leader of the Opposition, Azad *saheb*, rightly said that we keep moving places without any rancour,

without any ill-will and then perform the functions which the electorate has given to us. That is the strength of Indian democracy. Sir, five years ago, exactly on the same occasion, I was sitting where my friend Mr. Ghulam Nabi Azad is sitting, I had said that the election results always produce a winner and a loser. But the strength of a democracy is that the winner must never get arrogant. He must always have the modesty of a winner and realise that he is a trustee of popular mandate which is a challenge for him to perform. The loser can't be bitter. He has to be gracious. Nobody is born to rule for ever and therefore people will change places. Any person who does not succeed in an election must always be gracious when he does not succeed. He can't be grudging about the role that the electorate has given him.

But, Sir, these results have a much deeper meaning. If we seriously, in the historical perspective, analyse these results, besides the result, which produces a popular government, there are many significant aspects of this result. After three decades, thirty years after 1984, we have a Lok Sabha where the electorate has voted one single party with an absolute majority. We are an alliance Government. We will continue to be an alliance Government. In the last thirty years, in none of the general elections was a single political party able to get a figure of 272. We had thought that we're in an era of alliances and we're in an era of coalitions. My party believes, despite the figure of 282, that we are in an era of alliances because alliance represents the federal character of India. They represent the strength of India. We don't treat alliances as a burden; we treat this as a great credit. One great significance of this result is that after thirty years you can have a party with an absolute or a tall majority. But within that majority the changing character of India is visible.

I should not be misunderstood in this analysis. There are many cases where people have not governed to the best of their abilities. They thought that despite inadequate governance, the social support base of the party which is a political word that we use for caste support base in India will come to their rescue. It has happened in the past. But the second lesson is that if you don't govern well, caste alone will not save you. Therefore, you either perform or perish. There are parties which have got single digit seats or not even a single seat. My friend Mr. Satish Chandra Misra was giving us sermons that the Congress has travelled from here to the other side and we have travelled here and that we are in danger of moving there. He must seriously introspect why his party did not get that figure in U.P. What people want is governance and not merely combinations or a social combination as a substitute for governance.

People who thought that even if there are allegations of corruption, and there are conviction orders against them and there are serious allegations, by just manipulating their position in coalition politics they can continue to survive have received a serious setback across the board. Those who thought that they could switch alliances and therefore defy the mandate which put them in power earlier were taught a lesson by the electorate. Those who thought that political leadership does not grow on merit but only grows within families either in the Centre or in the States and relied on dynasties as the only instrument of leadership creation, by and large, have suffered a serious setback in this election. And most of those who thought and who used phrases like consolidation of a particular caste or community, vote bank politics, strategic voting, again suffered a setback in the election. What do all these facts indicate? It indicates that the Indian democracy now is evolving. We have seen maturing of Indian democracy where people gave a verdict, which is far higher than what some of us also expected. People don't want political instability. People want Governments to govern for five years. They want Governments to govern and govern well; and dynasties or castes or merely religious issues, as somebody said, will not be substitutes for governance. People were feeling helpless. They even got angry sometimes and, therefore, this verdict is all about anti-incumbency against a particular party or a Government and an expression of hope in another party or Government. So, my party or coalition or alliance has benefited on both counts. We gained because of anti-incumbency against our opponents. We also gained because we were the beneficiaries of a hope being expressed in us and, in particular our leader, Mr. Narendra Modi. Sir, it is not surprising. We may try and defy this reality. But, after decades, I saw the return of massive crowds in public rallies and they could not understand this trend as to why this was happening. These were not managed crowds. These were people who came because there was a larger expression of hope and this hope was born out of helplessness. That is why, I feel that the burden on our Government is going to be much higher because people expect us to perform. My only appeal to my friend and senior colleague, Azad *Saheb*, is that there is one danger if we continue to be in Government for a very long time. Your party has been in power for a very long time since Independence. During the last ten years, you were in power in one stretch and when Governments give big advertisements and spend hundreds of crores of rupees on them, they get into a trap of believing in all their own advertisements. The world is not believing those advertisements, but those who give those ads start believing in them. When I heard my learned friend today, I saw the same problem that he was buying his own propaganda. So, all that had

appeared in those Bharat Nirman DAVP ads is really not all what the people see happening on the ground. If you have already done the 90 per cent of what is required to be done, then we should be on velvet. If there is very little that we have to do, then the people will be satisfied. But, if our target, as per your advice, is only ten per cent, then within days, not weeks, we will find hostile people outside. The verdict against you is not that you had done 90 per Cent and the people were only upset about the balance ten per cent, but people were angry why 'things' were happening. Are you aware of the state in which you have left the country behind? In 2004, when you came to power, despite slowdown, Asian crisis, etc., we had limped back to 8.5 per cent growth rate. I used to hear my friends, the Ministers in the previous Governments, saying, "Our average is better than your average". You inherited 8.5 per cent. What have we inherited? For the last two years, India has grown at less than five per cent. And less than 5 per cent for India is a disappointing figure. If India did not have a Government it can probably still grow at less than 5 per cent. The April figure of inflation is 8.9 per cent. So, low growth rates, high inflation, fiscal deficit more than 4.5 per cent. Because of low growth rate tax collections have suffered. Your budgeted tax GDP ratio was 10.9 per cent, actually you ended the year at 10.1 per cent. So, you have left the country behind at low growth rates, high inflation, high fiscal deficit, lower tax collections, and what is worse, the enthusiasm in the Indian economy was shattered. The investment cycle was broken. Forget people coming from outside and investing in India, domestic investors were moving outside. And if you have no investment, there will be no jobs, there will be no revenue. The Government won't have money for infrastructure projects. The Government won't have money for social sector schemes. So, it won't be poverty alleviation. You have left the country behind, to use your own language, not at the level of poverty alleviation, but you have elevated poverty. If that is the situation there are only one or two good trends that we concede.

The Current Account Deficit situation is better. But the election results itself has become an important political statement for India. Therefore, this country has got a second advantage that once again the investing community, both national and international, has started looking at India. Therefore, who are real repositories of public confidence? All elected Members in both the Houses and State Assemblies. The onus is now on us whether we can convert this once again into an opportunity or not. I think any Government when it takes over must honestly understand and learn lessons from what went wrong and why did it go wrong so that we do not commit the same mistakes. My honest assessment is, I am sure some of my friends here will disagree with me, in

any democracy, particularly parliamentary democracy, one party Government, or, a coalition Government, the office which is most accountable is that of the Prime Minister. The Prime Minister must have the last word. I have gone on record publicly, praising the Prime Minister of your Government, at least, in some matters. I called him a man of great scholarship which I believe he is. I called him a man of great personal integrity which I do believe he is. I have no difficulty in reiterating that. But then unless you give such a man the last word, the right to overrule others, unless he had that power, Governments can't run. You can't create structures outside the Government with obsolete ideas and make them more powerful than the Council of Ministers; and make them more powerful than the Prime Minister himself. Cases of corruption have; been brought to the notice of the then Prime Minister. Go back to November and December, 2007 when letter after letter was being written that all was not well in the Spectrum allocation. That is when the Prime Minister must have the last word and he must say, "I overrule it."

When there was nepotism in the coal block allocations, the Prime Minister must step in and say, "I won't allow it." Let us not be under this impression that a Prime Minister is of some kind of super human being. He is the leader of the Government. The bucks stop with him. Therefore, that is where he had to act. If there is instability in the taxation policy, something which became a defining moment against us, the Prime Minister must step in and say, "Well, I think, the repercussion of this will be far worse. I don't allow it." And let me say that for any Government to be able to take the country forward, it has to forge a larger consensus with almost all political parties or, at least, the main political parties in the Opposition. If you think that you will deal with the Opposition parties only through investigative agencies, then, investigative agencies can harass your opponent, but they cannot win an election for you. And, in the process, you end up destroying an atmosphere of consensus. So, the lessons that we have learnt from this are these. The Government must function. The principal body, which runs the Government, is the Council of Ministers. The Prime Minister has the last word. If our Prime Minister sees a corruption anywhere, he has to step in and stop it. He has to be tough, at times, even ruthless in dealing with such situations. And it is only then that the country can proceed. Misraji asked, "How long will it take for the Lokpal to be constituted?" But first let us look at the history. You spent years to decide whether you need a Lokpal or you do not need a Lokpal. You came out with a weak Lokpal. Then the Select Committee of Parliament produced a better Bill. For months, you did not allow the Bill to be passed. After it was passed, you framed rules which were contrary to the Act so that you could still control the Lokpal so appointed. All

these things, which had been done, are now to be undone and the spirit of that law, which this Parliament has enacted, has to be given full effect to, and I do not have any doubt that it will be given full effect to very soon.

Sir, with regard to what is contained in the hon. President's speech, my party and the Government, of which I am a representative here, are very clear that the first right of all our resources does belong to the poor. There are areas, even geographical areas, say, the North-East, the tribal areas, etc., where we have not spent the kind of money which we should have spent in the past, and, therefore, the priority will have to be given to these areas. But we have major challenges. Firstly, we have to revive the national economy. Our manufacturing sector growth has gone into the negative. And jobs are created in the manufacturing sector in a big way. If for two years continuously, your growth in the manufacturing sector is in the negative,—it is nose-diving Southwards—then, where are the jobs? India missed the first Industrial Revolution. We got the opportunity for the second time when several Asian countries were going in for low cost manufacturing. We were on the verge of missing that, and I think, this is our last opportunity to catch up with that and make India into a low-cost manufacturing hub. We have to concentrate both on physical and social infrastructure in this country. Let us not be under the impression and buy our own propaganda and say, "We have done 90 per cent." In the Indian Railways, after 1947, the track length has only increased by ten per cent. So, most of the Railways that we have is on the lines that the British left us. Are we ready to unlock the potential of the Indian Railways in a country Of our size? Take the case of our National Highways programmes. Just ask somebody to introspect to find out how many kilometres of Highways have been built in the last two years! Since the time the National Highways programmes have been started, the lowest performances were the last two years'. Towards the end of your term, some contracts have been given for the future. Then, the other areas are rural infrastructure, ports and airports. In Skill Development, you started a programme. But we have much longer to travel in that. Some programmes may overlap; some we may have to tweak. There is no copyright in the matter of poverty elimination or poverty alleviation as you call it. So, if healthcare programmes have to start, it is the same people whom you have to provide healthcare. There is no copyright on ideas. But, at the same time, are we in a position, whether it is higher education or universal primary education, collectively willing to take all this as a challenge.

Dr. Maitreyan referred to an important part of the President's Address which

referred to co-operative federalism. If we want India to move toward co-operative federalism, States have to be equal partners in the entire growth process. You can honestly ask representatives of the States—it is the Council of States—whether they had targeted in the past by not clearing their programmes and the proposals in relation to those States not being cleared. It hurt the country; it does not really hurt that State. And, we do believe—our hon. Prime Minister has said it in the course of the campaign repeatedly—and seriously try and find out whether in clearing large projects the participation of States, even in the decision-making process where the Central Government decides, has to be encouraged. After all, no project can be implemented in a State without the active co-operation of State. When you do that, you don't have to look at the political complexion or colour of that State if India has to grow.

Sir, a lot has been said about various issues relating to minorities and other incidental facts where India has to function in a compassionate manner and in a non-discriminatory manner. There will be issues in the future also. But the majority of our society will be happy if we are able to resolve them with a sense of responsibility and make country stronger and don't allow issues of social tensions to precipitate or perpetuate beyond a point. My party, particularly on issues of national security, has always given it the topmost priority. Therefore, it is needless to say that the Government will also give the topmost priority to issues relating to insurgency, terrorism or Maoism. We will try and see that strongest measures are taken, both socially and in terms of security, in order to see that these are curbed at the initial stage itself.

Finally, I will make only one sentence. Our policy with regard to our neighbours is predominantly guided by our own security considerations. Our policy with regard to dealing with the world depends on our traditional relationship as also our own economic interest. We will be guided in those matters by theses interests itself.

All that I have to say is that the President's Address, in many ways, may agree with what some of the things that your Government planned in the past. Therefore, these are the areas on which there is a need to build a national consensus and if we are able to build national consensus on these areas, I think, it will be in the larger interest of the country.

I had said that we must all have modesty and graciousness that the elections are over. We meet for elections after five years. So, we can effectively use these five years to make this country far stronger and far mature than what we are today. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Sitaram Yechury.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Mr. Chairman, Sir, with the permission of Shri Sitaram Yechury, I would like to say one sentence to the Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute only, please.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, in spite of having got 2.5 crore votes in the country and being the third party in the percentage of votes cast in the country, if we have not won a single seat, it does not mean that you would say that we should not speak and put our views before the House. The Leader of the House took my name specifically and said that I should not give sermons here. I was not giving any sermons. We are not here to give any sermons. But, we definitely have a right and we will continue to say what we have to say here. So far as winning and losing is concerned, it is a game. The BJP also had lost and came to the single digit, then to double digits and the other digits. If that is the criteria that bar us from speaking in the House, I don't know whether this will be the right thing.

SHRI ARUN JAITLEY: Nobody has suggested here that the hon. Member or his party should not speak. All that I am saying is, when you are analysing their position and our position, give us a little analysis of your own position also.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, we are not giving any positions of the parties. We are saying here what we feel you should do and how we are expecting you to do. So, it is the analysis of situations and issues and not of individual parties.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Sitaram Yechury now.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to associate myself, as is the norm, as are our Constitutional scheme of things, with the Motion of Thanks to the hon. President's Address. But, this does not mean and is never meant that we agree with the content of that Address. While being deeply grateful, as the Motion suggests, to the President of India for delivering the Address, we would like to express our concerns which I consider are very, very important to understand actually the mandate and what the people of our country are expecting. Therefore, Sir, I must confess that I begin with a sense of confusion at the moment.

Having heard the hon. Leader of the House just now, a dear friend and colleague with whom we have served when he was the Leader of the Opposition and the hon. Leader of the Opposition with whom I worked here when he was a hon. Minister and even earlier, now when both of them speak, I only recollect what Winston Churchill once said after the Second World War when he lost elections in England. He was surprised when he lost the elections. He said, 'The only lesson that I learnt from this is you have to show magnanimity in victory and humility in defeat.' That unfortunately is what has not really emerged from this. For which, I am actually pained. It is not that I am blaming anybody. I am actually pained for the fact that neither humility nor magnanimity has come. Sir, if you permit me, it is a slight sense of digression. I appeal to the House to take it as a sense of humour and not misunderstand me. There is a very popular film that came out of Hollywood, not a Bollywood film, called Hangover. I didn't understand what was the hangover in politics till now. Now, I do understand. The elections are over, Sir. We have settled our scores. Sir, the pointed issue is what the hon. President has now outlined, what he thought or what we all consider it to be the blueprint for the future. Since we are talking of that, I think, since elections are over, the votes have been cast, let us actually begin this exercise of what needs to happen in future. The new Government has come and assumed office. We only wish it well. We want it to serve the expectations of the people. We have done so even outside the House and we will do that in the House as well. But, the hon. President's Address somehow does not evoke that sense of confidence that these are matters that are being Addressed with the gravity and seriousness that they should be Addressed with. Why do I say this, Sir? Firstly, this Address is a compilation of all the election slogans that emerged during the campaign. I have no dispute with it. Perfectly, it is an easy reckoner, so to speak, like the guide books we have in our schools. I mean, we can always look back to it and refer to the various slogans that came up during the election campaign. Fine; it can do the job. I mean, you can also rehash the Election Manifesto of the Party that won the election. That is also perfectly permissible, but then, how are you going to achieve what has been promised? That is what is expected, and, there, I think, it has been a very, very dismal failure. That is where, I think, the blueprint is not there on how you approach, what the prioritization is. We have all ridiculed the first 100 years jocularly—I think, the then Leader of the Opposition pointed out to me, from that side, and instead of saying 'the first 100 days', I said, '100 years'—and that was about the then Government saying that these priorities were not going to be fulfilled, that did not happen. We may have said what we have said in 2009 about their 100 days' agenda.

But, there was a prioritization. They said that 'we will do this'. They did not do that. They paid the price. But, today, in this Speech, Sir, there are no prioritizations that have come. It is just only a declaration of intent. However noble the intent may be, however valid the intent may be, the country wants to know how do you proceed in achieving it, what is the road map, what is the blueprint; and that is not available here. The slogans that are repeated here is one of 'good governance' and one of 'development'. The Leader of the House, then as the Leader of the Opposition, we were both together in shouting our voice out in denouncing what was called the 'Ordinance Raj'; we both opposed that on earlier occasions. Now, the first thing this Government does is to issue Ordinances, when the Parliament is meeting a week later, and start governing through Ordinances, and on what issue? Okay, when we come to that, we would discuss the merit of it. It is for appointment of officers of the Government. The point is, it sounds very ominous on how the beginning has happened. But the moot point here is the question of development. The President of India also refers to this. In fact, he says this in paragraph 4, "This has been an election of Hope", which is true. It has been an election of hope. When I and the hon. Leader of the House both passed out of our higher secondary, and when we were looking for our future education, we only had the Delhi University before us. Both of us joined the Delhi University, different colleges, of course. But we went there. Today, when my youngest son passed out of the higher secondary, he has got 16 institutions in front of him to choose from, in the same city. Now, there has been growth; there has been development; there has been an expansion of opportunities. But the hopes that this generated amongst the youngsters have to be fulfilled. That is the moot question. How are you going to fulfill that? *'Yeh Dil Maange More'* is the slogan that has been used, but how are you going to fulfill that expectation from the people, and for that, I think, you have to consider the existing realities which, I am afraid, have not come into consideration, I am saying this because if we go by the first section of what the hon. President has said this in paragraphs 1, 4, 5, 7, and then paragraph 7 is actually a little moving, I quote, Sir, Poverty has no religion, hunger has no creed, and despair has no geography. The greatest challenge before us is to end the curse of poverty in India. My Government will not be satisfied with mere "poverty alleviation", and commits itself to the goal of "poverty elimination". Very poetic and very noble. But, then, Sir, what is the actual reality in our country today? The actual reality in our country today, according to the Planning Commission's Tendulkar Committee's Report, 38 per cent of our population is below the poverty line.

Very maligned, highly debated statistics that are involved in it. But, on this, there is no doubt, that the poverty numbers are huge. Now, mere declaration of intent is not enough. How are you going to eliminate this poverty? What are the specific methods in which you are going to tackle it, and how is the beginning going to be made? We are not saying that you can do everything now. But, how are you going to make this beginning? This is something which I can't *find even* with a microscopic eye it in this Speech, Sir. You talked about inequalities. What is the reality, Sir? I remember saying here, from the same place, and, I can assure both of them, and, in the last occasion when we were moving a Motion for Thanks, I said, 'the two of you may change your places, but I will remain here.' And I am still here. And we will continue with our *critique* and which I think is in the country's and people's interest. What is that *critique*? Why do we say that? The net worth of India's billionaires in the last fifteen years has grown 12-fold. There are 59 billionaires in our country. I have nothing against them. Please, may their tribe increase. Let them grow. But the point is that these 59 individuals have an asset value that is equal to nearly between one-third and one-half of my country's GDP. Then you have 80 crores, 800 million, of our people today who cannot survive on more than twenty rupees a day. This is the two 'Indias' that we have been making. If poverty has to be eliminated, this gap of growing inequality has to be bridged. We have one of the highest gini coefficient in the world today of income inequality. If this is the case, how are we going to actually Address this issue? Yes, that is not possible without a higher growth rate, without the higher growth of employment. Every one of us knows that. But how are going to achieve that, Sir? In order to achieve that, you have not really substantively spoken of anything in this Address. The other concern that has been at the outset referred to is the question of inflation. The hon. Leader of the House has just now spoken about the rate of inflation being high and the rate of growth being low. Now how is this inflation going to be tackled? Not a word in this entire Address on how this inflation is to be tackled. We maintain that one of the major causes for this inflation is the permission given for speculative trading in essential commodities. Unless you ban that for some period of time, it is not possible to contain inflation. Secondly, there is no blueprint, roadmap to suggest that that is even being considered. You have this huge stock of foodgrains with you. Why are you not releasing those foodgrains to your Public Distribution System at the BPL rates to the States? Allow that to reach the market which will dampen your inflation. No, that is not being done. On the contrary, the first act that happens when this Government comes into office is a further hike in the price of diesel which will increase the transportation

costs, and, therefore, trigger off inflation. So, what are the signals that are being sent? This is where I think there is a lot of concern on how we are going to tackle this problem which the hon. President of India has actually mentioned. Then he has given this hope, he has added to this hope saying that these elections have been an election of hope. Yes, we all have congratulated our people, we have congratulated our Election Commission, we have congratulated the youth who have voted. The President of India actually says that youth is the driving force today in our country, is the largest section of our population. In fact, he says, 'my Government will strive to transition from youth development to youth-led development.' Now how will this youth-led development happen, Sir? If you provide our youth with health, with education and with employment, a better India will be built by them. All of us need not debate here any future policies. I have that confidence in our youth, all of us have that confidence in your youth. But give them the wherewithal. What is the state of affairs as far as the wherewithal is concerned? Will just read out one passage from what Nobel Laureate Amartya Sen has written recently in New York Times. I will just quote what he said. It is a small paragraph. I quote, "India has elite schools of varying degrees of excellence for the privileged, but among all Indians, seven or older, nearly one in every five males and one in every three females are illiterate. And most schools are of low quality; less than half the children can divide 20 by 5, even after four years of schooling. India may be the world's largest producer of generic medicine, but its healthcare system is an unregulated mess. The poor have to rely on low–quality–and sometimes exploitative — private medical care, because there isn't enough decent public care." Now, with this situation, what is that empowering of youth, which we are doing? And, what is the employment situation? The latest National Sample Survey informs us that the growth rate of employment between 2005 and 2010 is 0.7 per cent. This the rate of employment growth. Our youth, today, is the backbone of our population, of our society, the demographic dividend that we have. This is the state of their education; this is the state of their health. Our former Prime Minister had to bemoan, saying that this was a national shame that the children's malnutrition in our country continues to remain at a very, very high level. If this situation cannot be changed, what are all these hopes about? And, this situation has to be changed, not the slogans of high-speed trains or hundred new cities. Wonderful, if you can have all of them. But please remember that the civilizational advance informs you that cities develop not because you wish them to develop, but cities develop because of economic development. It is not that the economic development will happen because you build cities. Unless there is economic

5.00 P.M.

development, no cities can be built. We have had Muhammad Bin Tuglaq. All of us know that history. I hope these hundred cities do not end up in that sort of example. And, we also know what happened to *Badshah Akbar's* Fatehpur Sikri. We are all aware of that. So, buiiding cities is not the answer. The answer is economic development that leads to the development of cities. But you are putting the cart before the horse. ...*(Interruptions)*... I am not going into the history. The question is, what the solution is. You are now talking of the question of great investments that will lead to growth. You talk about the greater investments in terms of the FDI. The paragraph 40 of the hon. President's Address talks about the liberalized FDI in the defence production. Now, the FDI coming into India, according to us, must always be based on three conditions that are beneficial to my country — (a) The FDI must expand my productive capacities; (b) The FDI must increase employment generation; and (c) the FDI must upgrade India technologically. If these three conditions are not fulfilled, any other type of FDI is not in India's interest, not in the interest of its people. What is this FDI in Defence production? That, in addition, also creates problems for our security concerns. I remember my friends in the Congress, who are now in the Opposition, used to chide me saying that I support 100 per cent FDI in telecom sector in China, but why I was opposing that in India. China is allowing FDI in telecom only in the hardware production. Why is it that everyone of us today is having a cell phone that is made in China? Why are those cell phones not made in India? Now, they are slowly coming. But why did we not allow them in hardware production? Why did we do it in services? We allow them in services, which is profit-generating! All services provided in China are by the public sector. But here all services are by the private sector. Hardware production is imported. What is this FDI policy? Mere appeasement of foreign investors? Is it going to benefit us? You talk of infrastructural development. You talk of agriculture. For all that, we require resources. The question is, how do you marshal these resources?

There is not one word in this entire speech on from where do you marshal these resources from. Last year, the default in direct tax collections, according to the Department concerned, was Rs. 5.1 lakh crores. That is a straightforward pilferage. That is what the official record is. This is in addition to the tax forgone which comes to Rs. 5.73 lakh crores. Okay, half of this may be disputed. There may be legal litigations. But even half of that plus this Rs. 5.1 lakh crores comes to more than Rs.7 lakh crores. If you collect

and use that for public investments, agricultural infrastructure, rural infrastructure, urban infrastructure, all this can be Addressed and you can also provide crores of new jobs for our youths who are today wanting it. And, Sir, the tax foregone last year was Rs. 53,000 crores more than the entire fiscal deficit. Fiscal deficit was Rs. 5.2 lakh crores and tax foregone was Rs. 5.73 lakh crores. If these policies are not reversed and if there is no indication that they are going to be reversed, there is nothing of this hope that will be realized. Then, it will be the same story five years later when positions may be switched, when you say that people's hopes have been betrayed and you have not lived up to your promises. That is why, unless you seriously Address yourself to these issues, forget who will win who will lose. I am talking of my own country, our own youths, their own future and their own aspirations of converting our demographic dividend as an asset. That is where, Sir, I think, there is a very serious drawback in this Address, which needs to be Addressed by the Government in the future. I hope this discussion will, at least, in the coming days throw some light. There is no point saying that because of me so and so thing happened and because of you that so and so has not happened. Ten years ago when I entered this House I was 50 years old. Now I am 60 years old, a senior citizen. You can't say that because of the Rajya Sabha I have become 10 years older. I would have aged anyway, Sir. So, the country would have progressed in any way. But you go on saying that yes, that happened because of me and this did not happen because of you. The point at issue is how you are going to Address. What is the direction? I am sorry I have to say it to the hon. President, while we associate with the Motion of Thanks, that there is a very, very serious lacunae and a drawback in this.

Coming to the other issue, Sir, cooperative federalism, much has been talked about it. All of us have the experience of being in State Governments. We have all talked about it. But, Sir, federalism in our country can never be strengthened unless you have an equitable distribution of finances between the Centre and the States. You have the Finance Commission that has not once till date since independence allocated even one-third of the Central tax collections to the States put together. Today, it is about 27 or 28 per cent. At the time of independence, we promised 50 per cent— 50 per cent for the States and 50 per cent for the Centre. But that has never happened. If you are talking of cooperative federalism, are you prepared for a Constitutional amendment to come and say that 50 per cent of the Central tax revenue will be shared with the States? If you are not prepared for that, then all this is a hollow slogan. This does not mean anything. Elections are over. So sound bites are no longer necessary. At least the votes have been cast.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Then, Sir, I come to the issue of terrorism. You talked of zero tolerance to terrorism in para 39. While talking of zero tolerance to terrorism, he said, everything else is said, all the States will be assisted, modernized, etc. But, then, what has been happening since the election results have come, Sir. Since the election results have come, you have had a spate of growth in communal violence all across the country. You have seen in Karnataka, you have seen in Pune how a technical person was killed. Mr. Sharad Pawar was only telling me a little earlier that in the State of Maharashtra 22 communal riots have taken place during the last three, four days. Now, all this just brings to mind the fact that in India, terrorism knows no religion, knows no areas, no bounds, no regions. Mahatma Gandhi was assassinated by a Hindu fanatic; Indira Gandhi was assassinated by a Sikh fanatic; and Rajiv Gandhi was assassinated by a fanatic of Sri-Lankan LTTE variety. So, `who the culprit is' is something that goes beyond any religion. Is there any assurance on the issue of thousands of youth who are illegally-detained because of no fault of theirs, because they are routinely-picked up, because they belong to a particular religion on charges of a terrorist attack? There is not one assurance that wrongly-detained Muslim youth who have nothing to categorically prove against them on not even one issue will be released. And then you have all such statements that come which give very contrary signals. Madam, the Minister of Minority Affairs, is coming towards you now. But she was saying in her statement 'Muslims are not a minority in our country.' The Ministry of Minority Affairs is saying this. She is saying that 'Reservation for Muslims kills the competitive spirit.' These are the Ministers who are making such statements. The question of providing some relief to the Muslim minority came not because of their numbers. It came because of their economic and social status which was brought out by the Sachar Committee Report. That is why the Justice Ranganath Mishra Report talked in terms of reservations within the OBCs. But none of those issues is concerned here but what we have is a very passionate reference to article 370 which comes in para 20, and, on that issue, there can be no dispute, Sir, that our brothers, Kashmiri Pandits, who have been displaced internally in their own country should get back a sense of their belonging, should get back to these areas. There is no dispute on it. But then what is it that it talks of, Sir? It is said that special efforts will be made for their return for a settlement in Kashmir. This is very ominous. It just reminds us of the Jewish settlements in the occupied Palestinian territories. What are the settlements that you are talking of? And, this is a very ominous trend indicator if that is. the sort of trends that you are talking of, because on the entire foreign policy issue, the traditional statement expressing solidarity of India with the Palestinian's

liberation is completely missing. So, this Israeli inspiration to deal with this problem is something that goes completely against the very concept and conception of what India is all about or the idea of India.

That is why I think, Sir, when you come to the final stages of this Address, there is a reference to India being a softpower. I am talking of para 48. I quote, 'To fully realize our softpower potential ...` So far, the criticism that I have heard for the last ten years in this House when they were in the Opposition was that India is a soft State under the former Government, that because we were a soft State, we were not able to handle cross-broader terrorism that has come in from there. Today, you are talking of a softpower potential. What does that mean? What are we talking about softpower potential?

Yes, improving relations with everybody is absolutely correct. We should do that in our interest; but remember the hon. Chairman of this House, who was here a little while ago before you came on to the Chair, as the hon. Vice-President of India, went to attend the swearing-in of the President of Maldives on his election. The then hon. Prime Minister was invited for Nawaz Sharif's swearing-in ceremony and he couldn't go for some other reason but he deputed a Minister of his, of the Government of India, who attended it. These have been happening. It is not that it has suddenly sprung up only with the election of this Government. The SAARC cooperation was on, it is going on. It is good that we are continuing it. I am very happy about it. But then let's not begin with this idea that the world has been created with me. Then we will only end with the idea like Charles XVI who said, 'After me, the deluge!' So, if you begin with the idea that the world has been created with me, you will only end with 'after me the deluge, and that would be disastrous for our country. Therefore, please remember, when we talk, as the hon. President talks, of "our rich spiritual, cultural, philosophical heritage", that is the idea of India.

Sir, I would finish with this point. I know, you are all beginning to be impatient, but I will just finish with this point.

The idea of India, the rich spiritual, cultural, philosophical heritage, is the all-inclusive idea of India. That inclusive idea of India is both on economic matters and on matters of identity. Talking of economic matters, you cannot solve the problem of unemployment by giving, like what you said in your election manifesto, the right to employers to 'hire and fire', or like the BJP Government in Rajasthan has implemented

in that State, as media reports suggest. What about the rights of the working people? Where is the working class in this entire speech? Where is the agricultural labourer in this entire speech? Where is the national law for agricultural labourers in this entire speech? They create our wealth, Sir. All of us are here on the basis of the wealth that is created by these working people. There is not one mention of them. What is this inclusive India that we are talking about? That is why, I think there is something very serious in this entire outlook. If we are talking of the rich cultural and philosophical heritage, then we must remember that. Dr. Karan Singh is not here. He signed the first Constitution of Jammu and Kashmir when it acceded into India, which became the law that is still in force in that State, as the Maharaja of Jammu and Kashmir. He is a Member of our House. He would know that in his city, Srinagar, there was a small place which has now been restored. All of us have helped in doing that, including the Standing Committee. That place is the famous Pari Mahal, where Dara Shikoh authored that famous treatise which was titled as Majma ul Bahrain—the mingling of two oceans. He was talking of Vedanta and Islamic Sufism, of how this syncretic culture evolved in our country, of how the objectives were served. As we learnt, Swami Vivekananda said, different rivers flow in different directions but merge finally in the same waters of the ocean. How all of them come and converge into a syncretic civilisational ethos is India, Sir.

Now, that cannot be done through an excluvist viewpoint on any aspect at all. While we are talking of a rich diversity, I keep recollecting Firaq Gorakhpuri. Firaq saab, as all of us know, was born a high-caste Hindu, as Raghupati Sahay. He taught English; he was a Professor of English in the Allahabad University. He wrote admirable Urdu poetry. One day, there was a very bad communal atmosphere in our country but there was shero shayari going on in Allahabad. Permit me to say this, Sir; you would also enjoy this. There was a *shero shayari* that was going on in Allahabad and he was asked to join. He was told, 'how can it be that we are having *shero shayari* in your city and you are not participating?' He said, 'No, the atmosphere in the country is bad; I do not want to say anything today. This is not the time for your sort of poetry.' People insisted and so he said, 'okay, I will go there and recite just one *sher*.' He spoke just two lines in that milien of was Urdu poetry—poetry had a lot to do with enjoyment, with life, etc. So, he said in Urdu,

"हासिले हुस्नो-इश्क बस इतना,
आदमी आदमी को पहचाने।"

There is no India if we don't recognize the other person irrespective of religion, caste, creed or whatever it is, as also a human being. If you don't recognize people coming from different religions, castes, labour class or billionaires in our country as equals, there is no India that would be left. So, when you talk of this cultural, philosophical heritage, etc., yes, the Ganga, you clean, but you also clean Godavari on which I was born and brought up, and also the Cauvery and the Periyar. Please clean ail of them. But the Ganga cleaning is a part of the President's speech. You had an MP from Varanasi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI SITARAM YECHURY: For the last two decades, you had the MP from Varanasi, the former President of the BJP. The Mayor of the city is from the BJP. But only now, you suddenly think that cleaning is possible. Anyway, even now, if you are going to do it, it is very good. Finally, Sir, I come to three D's. The last paragraph talks about it. The three D's are Democracy, Demography and Demand on our side. First, I talk about democracy. First, you think seriously about the election reforms. You know and I know, you come from a State where this sort of money is not normally spent. But you have seen what these elections have been reduced to. I mean, for parties like ours, it is impossible to function in these elections because you don't allow us to do wall writing; you don't allow us to put up posters. But then there is no restriction on going to electronic media; there is no restriction on spending thousands of crores of rupees on hiring aeroplanes and then criss-crossing across the country. Then, there is a lacuna in the law that political parties expenditures are not under any ceiling. Candidates are restricted, but not political parties. What is this discrepancy? It is a very incongruous situation. Unless you correct these things, it is just money power that will distort your democracy. We have been talking about electoral reforms all these years, but that is required. Hon. President should be reminded when we send back the Motion of Thanks expressing our gratefulness that you bring in electoral reforms and bring in proportional representation. Thirty per cent of the vote, you get the majority. Four or five per cent of the vote, but you get no seat. This is absolutely incongruous. Are we a democracy? Not once did we have a Central Government that had more than 50 per cent of the people who voted. Forget 50 per cent of Indians. Fifty per cent of the people who voted have not voted for any Government in India since Independence. There are more people who voted against the Government than for the Government. Is that democracy? Serious thinking is required. If you want democracy, if you want demography on our

side, empower our youth, as I said earlier. Give them health, education and employment. Yes, if you want the demand, increase the purchasing power in the hands of people. That you can do only if you take care of your working class, your agricultural labour and the working people. When the Government invests in infrastructure, it creates job, and gives people money through that job creation. So, Sir, unless these are done, these final three D's cannot serve the country. Therefore, I do hope that this august House, while sending back the Motion of Thanks to the President, will very humbly remind him of these issues so that his Government may be urged in the coming days to address these issues. I hope, we will do that, and with that hope, I thank you.

श्री के.सी. त्यागी: उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष अगर यहां होते, तो मैं दो-तीन चीजें उनके लिए भी कहना चहता था। प्रस्ताव के मूवर, मेरे दोस्त नक़वी साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है और हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, तो हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, तो हम आपको याद दिलायेंगे। आप नहीं करेंगे, तो हम आपको चेतायेंगे और अगर आप गलत करोगे, तो हम आपका विरोध करेंगे। इसके साथ ही, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। चार पीपल्स मेंडेट के नतीजे मेरे सामने हैं और मैं चारों का साक्षी हूं। वर्ष 1971 में कांग्रेस पार्टी 352, सीपीआई, सीपी (एम) 48, बीजेपी, that is, Jan Sangh of those days; very poor. 1973 आते-आते इंदिरा गांधी के इस मेंडेट का नतीजा हमने-आपने इकट्ठा देखा था जब गुजरात में आंदोलन हुए और जय प्रकाश जी 1974 में आ गए और 1975 में इमरजेंसी लग गई। एक मेंडेट में तीन साल के बाद ही जनता हमसे और आप से ऊब गई और फिर मेंडेट 1980 का आ गया। उसमें कांग्रेस पार्टी को 351 सीटें मिलीं, कम्युनिस्ट पार्टी व सीपीएम को 35 सीटें मिलीं, हमारी पार्टी Lok Dal of that time got 41 और आपकी पार्टी को काफी कम सीटें मिली थीं। लेकिन इस मेंडेट में भी जब पंजाब का अकोर्ड हुआ, मैं आपसे Rajiv-Longlwal pact से पहले का कह रहा हूं, जब पंजाब के अंदर आंदोलन चला, तो कांग्रेस पार्टी का फिर बुरा हाल हो गया और और 1984 में मिसेज़ इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, तो उसकी संवेदना से फिर एक चुनाव हुआ, माफ करना 1984 का, उसमें 414 सीटें मिली थीं। इतने सीटें तो जवाहर लाल नेहरू को भी नहीं मिली थीं। आपकी पार्टी को तो बहुत ही कम सीटें मिली थीं और आपके सारे बड़े-बड़े नेता हार गए थे। यहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं किसी की शान में खराब बात नहीं कहना चाहता। 1987 में हरियाणा में चुनाव हुआ, हमारे नेता चौधरी देवी लाल को 90 में से 85 सीटें, हमें और आपको इकट्ठे होकर मिली थीं। उसके बाद 1989 आया and the rest is history. इसीलिए किसी को भी मेंडेट पर बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। आपने उन चारों का नतीजा देखा है। आपको जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिए हैं, खराब करने के लिए नहीं दिए हैं। मैं आपका भाषण सुन रहा था, यहां पर जो बीच वाली पंक्ति में लोग बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूं,

"कुछ इस कदर बदहवास हुए आंधियों से लोग,
जो पेड़ खोखले थे, उन्हीं से लिपट गए।"

आपकी इससे शुरुआत हुई है। नक़वी कह रहे थे धर्मनिरपेक्षता, वोट बैंक, फेक सेकुलरिज्म शब्द नहीं हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्षता उससे निकला हुआ शब्द है। हिन्दू महासभा के नेता और मुस्लिम लीग के नेता आजादी नहीं चाहते, अंग्रेज रहें तो रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर नज़मा जी बैठी हुई हैं, इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 1947 में मुसलमान गांधी जी के पास गए और कहने लगे कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। गांधी जी के कहने पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लाल किले से भाषण दिया कि लौट आओ, तुम्हारे पुरखों की कब्रें यहां पर हैं। यह लाल किला तुम्हारा है, यह जामा मस्जिद तुम्हारी है। तुमने गंगा-जमुना के पानी से वजू किया है, वे मुसल्ले तुमको याद कर रहे हैं। जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, हम उन मुसलमानों को रेलों में से निकालकर लाए। वह गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता। आज आप गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आज एक समाचारपत्र में पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि यह सावरकर के विचारों की जीत हो गई और गांधी की हार हो गई। यह ठीक नहीं है, क्योंकि गांधी तो इतना बड़ा है कि स्वीडन के अंदर जो नोबल पुरस्कार कमेटी है, उससे पूछा गया कि आपने गांधी का नोबल पुरस्कार क्यों नहीं दिया, तो उसने कहा कि हम जीसस क्राइस्ट को इन पुस्कारों से बड़ा मानते हैं। गांधी जी तो इतने बड़े हैं, आप उनको छोटा मत करो। नेताजी सुभाषचन्द बोस गांधी जी की कई बातों के खिलाफ थे। मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि यह मुझको खड़ा हुआ जीसस क्राइस्ट जैसा लगता है और जब बैठकर भाषण देता है तो गौतम बुद्ध लगता है। आजदी के बाद और आजादी से पहले हमने कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं किया कि जिसकी पूरी दुनिया में यूएनओ ने 2011 में जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई हो। इसमें मुझे भी विदेश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप कितना भी अपना एजेंडा चलाइए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिडन एजेंडा मत चलाइए। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को इकट्ठा किया है, तब ये शहर बने हैं। आप मुजफ्फर से नगर को, अली से गढ़ को और गाजी से पुर को बनाकर उनको कब्रिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? यह हमारे मुल्क की इकट्ठी तहज़ीब है। बड़ी मुश्किल से शहर बसे हैं। मैं इसके लिए मुजफ्फरनगर का जिक्र नहीं करना चाहता था। आपके पास एक एक काबिल आदमी थे। सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले फैसला दिया है कि जिस-जिस अभियुक्त की जमानत है, कैंसिल की जाए। इसके आपके बालियान साहब भी मौजूद हैं। आपके बाद वहां पर श्री हुकुम सिंह जी थे, जो 74 से एमएलए थे, आपके डॉ. सत्यपाल सिंह जी वहां पर थे, लेकिन आपने उनको परपजफुली बनाया है। मैं बालियान जी को जानता हूं। मैं वहां का रहने वाला हूं। मैंने वहां से लोक सभा का चुनाव लड़ा है। एक साल पहले बालियान साहब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। सोहनबीर सिंह जी आपके वर्कर थे, लेकिन उससे आपके समाज में उत्तेजनाएं पैदा नहीं होती हैं, आपको बालियान साहब, सोहनबीर सिंह नहीं चाहिए, जो आपकी आर.एस.एस. का तीस साल पुराना वर्कर था। इसलिए मान्यवर, यदि प्रधानमंत्री महोदय होते या हमारे दोस्त अरुण जेटली साहब होते तो मैं उनसे यह कहता। मैं अपने बाएं बाजू के मित्रों को, जिनके साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कंधमाल में कुछ ईसाई मार दिए गए थे, यहां भी और बाहर भी यह सवाल उठा था,

Atal Bihari Vajpayee is on record saying, देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता खतरे की घंटी है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है, हमारी सभ्यता सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सारे विश्व की चिन्ता करने वाले, सारे ब्रह्माण्ड की चिन्ता करने वाले भारत में अगर संप्रदाय के आधार पर अनुभव करें कि उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा या वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह चिन्ता का विषय है और एक चुनौती भी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे और आपके पुरखे इकट्ठा कहकर गए हैं। एक हफ्ते से पुणे में क्या हो रहा है? आप तो यहां राज्य सभा में बैठे हैं, वहां पर कॉमन सिविल कोड लागू हो गया है। शरद पवार जी यहां नहीं हैं, महाराष्ट्र के इधर के एम.पी. हों या उधर के एम.पी. हों, जुम्मे की नमाज में एक भी मुसलमान पठानी सूट पहनकर नहीं आया। इस बार जब जुम्मे की नमाज हुई तो किसी के मुंह को छोड़कर दाढ़ी नहीं थी। मैं आपसे गलत बात नहीं कहना चाहता हूं। वहां पर ऐसा मंजर है। वहां का जो सबसे बड़ा अखबार है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। आपने हिंदू राष्ट्र सेना बना दी, आपने कहीं मोदी सेना बना दी, आपने कहीं हिन्दू विचार मंच बना दिया। आप उनके जरिये समाज को बांटने की जितनी गंदगी हो सकती है, करते हैं और फिर एक सेटेन्स कह देते हैं कि देश सबके लिए है। यह मैंने आपको अभी बताया है। यह यहां रखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आपका एम.पी. कह रहा है कि ऐक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। यही हम गोधरा में सुनते थे। आपको मेन्डेट मिला है, आप सड़कें बनाइए, आप इलाज कराइए, आप देश को दुनिया का सबसे उन्नत भारत बनाइए, हम आपके साथ हैं, यह हमने पहले ही कह दिया है। अभी हमारे मित्र श्री जितेन्द्र सिंह जी लोक सभा में पहली बार जीतकर आए हैं। वे कह रहे हैं कि हमें बहुत वोट मिले हैं। यहां पर गुलाम नबी आजाद जी नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वैली में 9 लाख वोट पड़े हैं। नकवी साहब सुनिए, 9 लाख में से 14 हजार वोट बीजेपी को मिले हैं। जम्मू-कश्मीर की तीन सीटों पर इतने वोट मिले हैं कि इनको धारा 370 खत्म करने का मेंडेट मिल गया। लद्दाख में आप भी गए थे, आपके उम्मीदवार को 31 हजार, 111 वोट मिले हैं, जो नंबर दो पर कैंडिडेट रहा है, उसको 31 हजार 75 वोट मिले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो तेन्जिग शैम्पेल है, उसको 26 हजार वोट मिले हैं, एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सैय्यद मोहम्मद काजिम है, उसको 28 हजार वोट मिले हैं। यानि कि इनको 31 हजार वोट मिले हैं और वहां लद्दाख में 85 हजार वोट मिले हैं, They got the mandate to remove Article 370! मैं यह मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी पार्टी के साथ मेरठ में चुनाव लड़ने को गया था। मुझे एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया, लेकिन इससे मेरा मन खराब नहीं है। यह गांधी की सीट के लिए है, वोटों के लिए नहीं, जो वोटों के लिए कर रहे हैं उनके लिए कहिए। ऐसे तो सारा मुल्क ही ऐसा हो जाएगा कि वह लेबनान बन जाएगा। धारा 370 हटा दीजिए। मैं इस हाउस में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आर्टिकल 370 का प्रोविजन आया था। उन्होंने उस दिन कहा कि क्यों हटा रहे हैं। हमारे और आपके जो नेता थे, श्री वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और जवाहर लाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 1950 में गांधी-नेहरू लियाकत पैक्ट पर सरकार छोड़ी है। वहां पर परमिट सिस्टम शुरू हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि जहां कुर्बान हुए, वह कश्मीर हमारा है। आप क्यों बार-बार कहते हैं? कश्मीरी पंडित होने के लिए ये बैठे हैं मेरे मित्र। बसपा के कश्यप साहब बैठे होंगे। हम तीन लोग ऐसे हैं, जो ऑल पार्टी डेलिगेशन में सुषमा जी और अरुण जी के साथ गए थे। कश्मीरी पंडितों को देखने के लिए कैंप में जाने वाले

हम तीन आदमी थे। हम कहते हैं कि लानत है वहां पर, अगर वहां के कश्मीरी पंडित वहां जाकर एडजस्ट नहीं होते, लेकिन 50 हजार लड़के भी पिछले 12 सालों से अपने घरों से गायब हैं, गुमराह होकर, आजादी की तलाश में, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, उनके बारे में भी कंसर्न दिखाइए। आपके जितेन्द्र सिंह ने पूरे देश में सवाल उठा दिया। क्यों उठा दिया? क्योंकि चुनाव होने वाला है। अभी मैं अपने दोस्त राजीव शुक्ल जी के यहां मुनव्वर राणा की ग़ज़ल सुन रहा था कि "सीमा पर बहुत तनाव है, क्या फिर कोई चुनाव है।" वहां पर जो आर्टिकल 370 की बात हो रही है, तो क्या फिर कोई चुनाव है? हां, चुनाव आने वाला है। इसलिए आपने इसे वहां उठा दिया। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो आपने पुणे उठा दिया। ये इस समय के इश्यूज़ नहीं थे। जनता ने इतने जज्बात के साथ आपको वोट दिया। हम तो आपके साथ नहीं, 6 महीने पहले अलग हुए हैं और अरुण जी होते, तो मैं उनको जवाब देता। वे नीतीश कुमार जी पर कमेंट करके गए थे, जब इतनी पुरानी मित्रता हो। आप आइडियोलॉजिकली करिए। एक जमाना वह था कि नीतीश कुमार को इसी दिल्ली शहर के अन्दर पांच-पांच तरह के प्राइज मिले हैं, जो देश के बड़े पूंजीपतियों के संगठन और अखबारों के संगठन ने दिए हैं that he is the best governing Chief Minister of the country. आपसे अलग होकर क्या गुनाह कर दिया! हमारा-तुम्हारा कोई जिन्दगी भर का बॉन्ड तो था नहीं। तलाक है, तो इसकी इद्दत की भी कोई सीमा तय नहीं है, सदा के लिए तलाक है। ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं, वह हमारे-इनके बीच की बात है। इसलिए मेरा निवेदन यह है ...**(व्यवधान)**... नक़वी जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, त्यागी जी पानी पी-पीकर बहुत ही अच्छी तरह से कोस रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उपसभापति महोदय, आदरणीय त्यागी जी बहुत सी चीजें तथ्यों से परे बोल रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Naqvi, you can reply to that later. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उससे भी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का जिससे कोसों का रिश्ता नहीं है, उस पूरे के पूरे विषय पर वे भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can reply later. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। वे बोलें, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी को सीधे जोड़ कर सारे मुद्दे के साथ बोलेंगे, तो यह ठीक नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can reply at your turn. Tyagiji, please continue.

श्री के.सी. त्यागी: कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने इसे क्यों उठाया? जिन्दगी में पहली बार जीता है और मुझे पता है। अभी मेरे मित्र गुलाम नबी आज़ाद यहां नहीं हैं, जो कश्मीर का आंदोलन चला था, वे उसके नेता थे। जब वहां पर भूमि आंदोलन चला था, जितेन्द्र सिंह उसके नेता थे, वे जिन्दगी में पहली बार चुनाव जीते हैं और आपने उनको पीएमओ का इनचार्ज बना दिया। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। लेकिन वे कहते हैं कि मैनडेट मिला है, which mandate? मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को मना कीजिए।

दूसरी बात यह है कि किसानों के मामले में हमारे दायें बाजू वाले मित्रों की भी जो राय थी, मैं उस पर पहले अपनी राय रख चुका था और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप जो वाइब्रेंट भारत बना रहे हैं, उसके 42 प्रतिशत किसान खेती छोड़ कर जाना चाहते हैं। खेती अब पहले जैसा लाभ का सौदा भी नहीं बची है। यहां पर किसान की जो मासिक औसत आय 4960 रुपए रह गई है और नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक पूरे स्रोत को मिला कर यह आय 165 रुपए प्रति दिन थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कर्जदार किसान परिवार का औसत बकाया 25, 895 रुपए था। नक़वी जी, आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, साथी भी हैं, पड़ोसी भी हैं, मैं आपसे क्या कहूं। सिर से सीने में, पेट से पांव में, एक जगह हो, तो कहें दर्द यहां होता है। मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकार्ड बता रहा हूं। वहां पर सारे आत्महत्या के मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई असत्य नहीं होता है। 2005 से लेकर 2011 तक, जब हमारे दायें बाजू वाले मित्रों की सरकार थी, 2,90,740 किसानों ने आत्महत्या की है। *to this Parliament, * to this nation.

जो भारत माता का सीना चीर कर दौलत पैदा करता हो, ऐसे तीन लाख किसान आत्महत्या करके मर जाएं और उसका कोई एड्रेस न हो, उसके लिए कोई योजना न हो। 'हर खेत को पानी पहुंचाएंगे' तीस साल पहले भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नारा हुआ करता था ...**(व्यवधान)**... जहां तक इंसेंटिव की बात है, यहां नालंदा से मेरे एम.पी. मित्र बैठे हुए हैं। नालंदा के दो किसानों ने, हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति एकड़ चावल पैदा करने का और सबसे ज्यादा प्रति एकड़ आलू पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन, इस देश के अन्दर 'पद्मश्री' उनको नहीं, बल्कि नाचने-गाने-कूदने वाले लोगों को मिलेगा। अगर आपने उन दोनों किसानों को 'पद्मश्री' दे दिया होता तो देश खाद्यान्न के मामले में जितना सम्पन्न है उसका सौ गुना ज्यादा हो गया होता, लेकिन आपकी प्रायरिटीज़ डिफरेंट हैं। मैं उनके नाम भिजवाऊंगा। आप उनके नाम देख लीजिए। इनकी पिछली सरकार ने लगभग पांच करोड़ रुपये के लोन पूंजीपतियों को दिए हुए हैं। ये इनके बड़े लाडले थे। दुर्भाग्य यह है कि जिनकी इन्होंने मदद की, वे चुनाव में आपकी मदद कर गए। चुनाव आयोग का कहीं जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा 300 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गई है। हमारी जैसी पार्टी चुनाव कहां से लड़े? श्री शरद यादव पर या नीतिश कुमार पर पूरी जिन्दगी में एक नये पैसे का भी आरोप नहीं लगा। वे न तो डिस्प्रोपोर्शनेट में हैं, न ही सीबीआई में हैं। वे पैसे कहां से लायें? मैं आज का दिन तल्खी वाला नहीं करना चाहता कि कैसे चुनाव लड़ा गया है, लेकिन 300 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गयी है। हम गांव में होते हैं तो वहां अठन्नी-चवन्नी की खरीद होती है, उसे पैसे नहीं कहते। यह राशि किसकी थी, किन लोगों से पकड़ी गई थी? मैं चुनाव आयोग के पास गया। सम्पत साहब के पास गया। जैसे पेड न्यूज हैं, वैसे ही पेड सर्वे हैं। याद रखना, इस पार्लियामेंट के अन्दर जो गरीब लोग आ रहे हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनके राजनीति करने के और चुनाव जीतने के दिन अब सदा के लिए चले गए हैं। अपने नेता की गुलामी करोगे, तो उसकी इच्छा है कि वह चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे या न दे और टिकट तो उसी को मिलेगा जिसके पास माल होगा। इसलिए, सबसे ज्यादा करोड़पति इस पार्लियामेंट में आए हैं। आपके नेता ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, हम और आप तो बहुत दिन साथ रहे। आप याद कीजिए कि एक तारकुंडे कमिशन बना था। जय प्रकाश जी ने खुद अपनी कलम

*Expunged as ordered by the Chair.

से इसे बनाया था। उसमें क्या था? उसमें चुनाव सुधार था। चुनाव लड़ना अब आपके बस का भी नहीं है, यह मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं। चुनाव ऐसा हो जाएगा कि पर्चे लगाने के लिए तरसोगे। जैसे आपके राज में कभी हम और ये तरसते थे, लेकिन ये हमसे और आपसे ज्यादा होशियार निकले। ऐसे पूंजिपति आपसे मदद करके ले गये, अम्बानी, रुइया, अदानी वगैरह और चुनाव में पैसे सब इनको दे दिए। तो आपसे बड़ा * तो कोई निकला नहीं।

मैं दूसरी बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: सर, * शब्द तो अनपार्लियामेंटरी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी: मेरा पानी खत्म होगा तो मैं दोबारा फिर पीऊंगा। ...**(व्यवधान)**... राष्ट्रपति महोदय का पूरा भाषण आपका था। आपको नीतीश कुमार से शिकायत हो सकती है कि उसने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन बिहार की 10 करोड़ जनता ने क्या गलती की? भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में 'बिहार' शब्द का जिक्र नहीं है। मैं यह बिहार के लिए नहीं कहना चाह रहा हूं। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में 'बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा चारों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए' यह मांग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सुशील मोदी से लेकर रवि शंकर प्रसाद तक मोदी जी के कान में मंचों पर कहते थे कि 'विशेष उस' का जिक्र कर दीजिए, लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की मदद करूंगा। लेकिन, राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण और जो भारतीय जनता पार्टी का फुल फ्लेज्ड मेनिफेस्टो है, वैसा आपका भी नहीं है, उसमें एक भी शब्द 'बिहार' का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप नीतिश कुमार जी से लड़ते रहिए, स्कोर तय कीजिए, लेकिन बिहार की गरीब जनता के साथ अन्याय मत कीजिए।

सर, ये लोग साम्प्रदायिकता विरोधी कानून ला रहे थे, राज्यों को ठीक से एड्रेस नहीं कर रहे थे। आपकी भी मुख्यमंत्री जयललिता जी थीं और नीतीश कुमार जी भी उस समय थे। हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मुजफ्फरनगर में...। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूं। आप अपनी कांस्टीचुएंसी को ठीक से एड्रेस नहीं करते। गोधरा के बाद 1200 लोग मरे थे और इनके भागलपुर में 1800 लोग मरे थे, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की, चूंकि मरने वाले जिस कौम के आदमी थे, उससे आपको हमदर्दी नहीं है। वरना एक बार भी आप कहते कि गोधरा में 1200 और इनके यहां 1800, लेकिन आप किसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... जो साम्प्रदायिकता विरोधी कानून है, उसको लाइए। राज्यों को एड्रेस कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मिश्रा जी शायद बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया और कहा कि कानून और न्याय सबके लिए हैं, जिसका जिक्र डा. अम्बेडकर ने किया है। पश्चिमी यूपी की दस करोड़ की आबादी है। गाजियाबाद से लाहौर 418 किलोमीटर है और इलाहाबाद 680 किलोमीटर है। हमें वहीं भेज दीजिए। यह सस्ता न्याय है? कोई वकील, कोई मुवक्किल, कोई गरीब आदमी वहां पर जा सकता है? आप यह काम कीजिए कि हमारे पश्चिमी यूपी के 15 जिलों को दिल्ली में मिला दीजिए। हम वहां पर नहीं रहना चाहते हैं। हमें वहां न्याय नहीं मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इए नए मुद्दे को भी आप जोड़ें। आपने अच्छा किया कि इसमें इरिगेशन का जिक्र किया है। इस देश में चालीस प्रतिशत भूमि सिंचित है।

*Expunged as ordered by the Chair.

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। इस देश में कई लाख पोखर थे। हम गांव के रहने वाले हैं। पशुओं के पानी को लेकर पानी का संचय तक वहां होता था। जितने भी ग्राम प्रधान हैं या उनके henchmen हैं, उन्होंने सारे के सारे पोखरों पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। आप इस संबंध में एक कानून बनाइए, हम इसके लिए आपकी जिन्दाबाद करेंगे, कि जितने भी पोखर हैं, they must get back to their original position. इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप इसको भी जोड़ें, उसको ठीक करें। गाडगिल आयोग की सिफारिश है, जिसके संबंध में अभी सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि आप पचास परसेंट कीजिए। राज्य कोई गुलाम नहीं हैं। जो गलतियां वे करते थे, जिनकी वजह से आज वे यहां बैठे हैं, अगर आप भी वही गलती कीजिएगा, तो फिर आप भी वहीं जाकर बैठ जाइएगा। आपने और हमने मिल कर federalism चलाया था, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री जी ने भी किया और हमारे मित्र जेटली साहब ने भी इसका जिक्र किया।

महोदय, शायद जयराम रमेश जी उपस्थित हैं, क्योंकि मैं "मनरेगा" के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे डर है, मैं चार चीजों के बारे में कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं। ये "मनरेगा" को खत्म करना चाहते हैं। सुन लीजिए, ये Land Acquisition Act में अमेण्डमेंट करेंगे। क्यों? यह भी मैं अभी बताऊंगा। ये डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करेंगे और खाद्य सुरक्षा में कटौती करेंगे। यह इनकी गलती नहीं है। पहले रॉयल्टी में पूंजीपति चंदा देते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने निवेश किया है, इसलिए उनको उसकी रकम चाहिए। "मनरेगा" का कई लाख करोड़ का बजट है। ये जो पीले अखबार हैं, The Economic Times, The Business World, आजकल मैं उनको पढ़ता हूं। वे कह रहे हैं, "What is this bogus subsidy on petrol?" अब इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पम्प न लग करके अंबानी और एस्सार के पेट्रोल पम्प लगेंगे। यह प्रयोग एक बार हो चुका है, लेकिन वे फेल इसलिए हो गए थे, क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे थे। अब यह सब्सिडी खत्म करने की बात होगी और सब्सिडी खत्म की गई, तो तकरार होगी। हम इसको नहीं होने देंगे। ये "मनरेगा" को effectively implement नहीं कर पाए। इससे बड़ी कोई स्कीम एशिया में नहीं होगी। उससे बहुत बेरोजगारी खत्म हो सकती थी, लेकिन सीएजी कह रही है कि उसमें भी बेईमानी हुई है। आप इसका effective implementation कीजिए। इसको खत्म मत कीजिए और इसमें कमी मत लाइए।

महोदय, अब मैं खाद्य सुरक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। तेन्दुलकर कमेटी से लेकर और सारी कमेटियों ने बताया कि देश के गरीबों की क्या हालत है। अगर इसमें इतनी सी भी कटौती हुई, तो गरीब लोगों के पेट पर तलवार चलेगी और फिर आपके वोटों पर भी तलवार चलेगी। इसलिए यह भी गरीबों के लिए होली गीता, कुरान की तरह से है, इसको भी छूने का प्रयास मत कीजिएगा। देश के पूंजीपति लोग पांच लाख करोड़ का कैश रिजर्व दबा कर बैठे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी के बड़े लाडले थे।

महोदय, थॉमस साहब आपके राज्य से आते हैं, जो पिछली सरकार में खाद्य मंत्री थे। आपके राज्य में एक क्विंटल गन्ना पैदा नहीं होता है, लेकिन वे गन्ने के दाम तय कर रहे हैं। मैंने शरद

पवार साहब से कहा कि जो Commission for Agricultural Costs and Prices है, उसमें किसान को रख दीजिए। वहां डा. कोठारी बैठे हैं। डा. कोठारी को बैठाने का क्या मतलब है? नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। कोठारी साहब अगर बिजनेस करें, तो समझ में आता है, डाक्टरी की दुकान चलाएं, तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे किसानों के उत्पाद के भाव कोठारी साहब तय करेंगे, यह बात समझ में नहीं आती है। इस कमिशन में तीन मेम्बर और थे, जिनमें से कोई भी किसान नहीं थे। Therefore, you are there. अगर इन्होंने ठीक नहीं किया, तो they will also be there. हमें पिछले साल के मुकाबले गन्ने का दाम 20 रुपये प्रति क्विंटल कम मिला है। ऐसा पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने जो कमिटी बनाई, उसमें शरद पवार जी हमारे नेता बना दिए गए। वे गन्ना मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं और उनकी अपनी मिलें भी हैं। मैं उनकी शान में कोई खराब बात नहीं कहना चाहता। ऐसा पहली बार हुआ जब इस देश का जो एस्मा है, जो चीनी मिलों के मालिम हैं, वे सरकार को डांट रहे थे कि खबरदार जो इस बार कम किया तो। हम किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम मिले हैं। उसका अगर मैं हिसाब लगाऊं तो वह हिसाब हजारों करोड़ में बैठेगा। आज गन्ने का काम खत्म हो चुका है और हमारा 4,800 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है।

मेरे साथ एक बार ग्रुप डिस्कशन में ...**(व्यवधान)**... मैं अच्छी बात कह रहा हूं, प्लीज़ सुन लीजिए। उस ग्रुप डिस्कशन में एक अविनाश शर्मा नामक व्यक्ति आ गए। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एस्मा का सेक्रेटरी हूं। मैंने पूछा कि आप पहले कहां थे? उन्होंने बताया कि वे फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। इस देश के अंदर यह भी एक बीमारी हो गई है। मेरे एजेंडे में यह भी है कि सरकार के अंदर बड़े पदों पर नौकरी करते हुए अगर कोई सेक्रेटरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपने कार्यकाल में कभी न्यूट्रल नहीं रहा होगा। अगर रॉ का चीफ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो जाहिर है कि वह अपने जीवनकाल में न्यूट्रल नहीं रहा होगा। ऐसे ही अविनाश वर्मा, जो कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का सेक्रेट्री था और एस्मा का सेक्रेटरी बन गया, वह हम गरीब आदमियों के साथ कैसे न्याय करेगा? इस देश में तीन लाख किसानों ने आत्महत्याएं कीं। क्या किसी चीनी मिल मालिक ने आत्महत्या की? यह केवल मेरा सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरे हाउस का सवाल है। रॉ का चीफ, आईबी का चीफ, कैबिनेट सेक्रेट्री, सीबीआई का स्पोक्समैन, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन कर रहे हैं। हम 40-40 सालों से जेल जा रहे हैं और हमारी जवानी के दो-दो, तीन-तीन साल जेलों में बीते हैं, फिर भी हमें टिकट नहीं मिल रहा है और इनको वहां जाते ही टिकट मिल जाते हैं। बीजेपी के मेरे कई मित्र हैं। चौरसिया जी हैं, वे 25 साल से हमारे साथ हैं, उनका टिकट कट गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वहां कोई पदाधिकारी आ गया था। आप क्या करना चाहते हैं? आपकी पार्टी में इतने एफिशियंट लोग हैं, आप उनको टिकट दीजिए। अब जो पूर्व होम सेक्रेट्री है, वह कहता है कि दो घंटे में यूपी की सरकार को बर्खास्त करो। क्या यह म्यूनिसिपैलिटी है? मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में चार-चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं। काम करने में कोई शिकायत हो सकती है, कोई गलत काम हो सकता है, लेकिन सरकार बर्खास्त होने के दिन अब चले गए। एस.आर. बोम्मई वाले कांड के बाद ऐसा हुआ। हमें वह जमाना

भी याद है जब चौधरी चरण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने के लिए मिसेज गांधी ने जहाज भेजकर ताशकंद से मैसेज मंगाया था, लेकिन अब वे दिन चले गए। यह म्युनिसपैलिटी नहीं है, ये किसी के नौकर नहीं हैं और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वह किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करे, इसलिए संघवाद को और बढ़ाने की जरूरत है। इसे आप लोग शुरू कीजिए। आप लोग केवल हथेली मत बजाइए। आप ममता दीदी से बात कीजिए और सभी क्षेत्रीय पार्टियों को इनके खिलाफ इकट्ठा कीजिए।

श्री उपसभापति: त्यागी जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री के.सी. त्यागी: सर, मेरे कितने मिनट हो गए?

श्री उपसभापति: आपका टाइम खत्म हो गया है, अब यह माइनस में है। ...**(व्यवधान)**... अभी इस पर बहुत लोग बोलने के लिए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी: जब हम गये, तो प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि चीनी का संकट है। उन्होंने चीनी मिल मालिकों की मदद करने के लिए कमेटी बना दी। उनको 7,000 करोड़ रुपये का सस्ता ऋण दे दिया। हमने कहा कि हमने तो किसानों के लिए कहा था। हम शरद पवार साहब के पास कहने के लिए गए कि हमने तो किसानों के लिए चिट्ठी लिखी थी। आप सरकार में मेरे वरिष्ठ साथी हैं और अच्छा होता कि उन दोनों में से कोई यहां होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को भंग कीजिए और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, जिसके साथ हमने कई धरने रखे हैं, उनके अच्छे-अच्छे लोगों को उस संगठन में रखिए, क्योंकि उनको कम से कम कॉस्ट एंड प्राइस का तो पता होगा, इनको क्या पता कि क्या प्राइस है, क्या नहीं है? अब आप प्रेम चन्द गुप्ता जी को बना दीजिए। हालांकि ये गरीबों की पार्टी में है, लेकिन हमारे साथ न्याय थोड़े ही कर पाएंगे। ...**(व्यवधान)**... करेंगे? अच्छा ठीक है।

इसलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे ही योजना आयोग है। एक बार डा. लोहिया कह रहे थे कि तीन आना रोज़ पर देश का गरीब आदमी गुज़ारा करता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और एक दूसरे समाजवादी नेता, अशोक मेहता उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तीन घंटे के अंदर मुझे इसकी जानकारी चाहिए कि लोहिया सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऐसा होगा कि मोंटेक अहलुवालिया ने एक दिन हिन्दी नहीं बोली। मुझे अरुण जेटली एक हजार गुना अच्छे लग रहे हैं चिदम्बरम से। वे कभी हिन्दी नहीं बोलते थे कि कहीं उनका अपमान होता था। सिर्फ इस बात के लिए मैं आपके प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं कि अंग्रेजी बाबुओं के मुकाबले में उन्होंने हिंदी में बोलने का फैसला किया है। मैं सलाम करता हूं इस चीज को।

श्री उपसभापति: त्यागी जी, मैं हिन्दी में बोल रहा हूं कि आप बैठिए।

श्री के.सी. त्यागी: मुझे प्रसन्नता होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ...**(व्यवधान)**... ये कह रहे हैं कि मुझको छ: बजे तक बोलना है और ये मेरे पुराने समाजवादी साथी हैं, मैं इनकी बात टाल भी नहीं सकता।

श्री उपसभापति: त्यागी जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री के.सी. त्यागी: सर, मेरा यह निवेदन है कि "अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा।" इन्होंने तो बना ही दिया था। ये तीन-चार थे। चिदम्बरम थे, मोंटेक सिंह थे, अगर बैठे न हों तो रमेश जी भी थे। ये हिन्दी भी नहीं बोलते थे। "Let us sit together and pass something together." उसमें यह नतीजा निकला कि 44-45 पर आ गए और सुनो, मैं नहीं चाहता कि गांधी की पार्टी की यह स्थिति हो। इनके पुरखों ने बहुत कुर्बानियां की हैं।

श्री उपसभापति: त्यागी जी, प्लीज।

श्री के.सी. त्यागी: एक सेकंड। आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन गांधी जी की और जवाहर लाल नेहरू जी की जो विरासत है वह बहुत बड़ी है। जवाहर लाल नेहरू आजादी की लड़ाई में साढ़े ग्यारह साल तक जेल में रहे हैं। उसकी बहन कृष्णा हथी सिंह ने लिखा है कि हमारा बैग परमानेंटली जेल जाने के लिए तैयार रहता था। कांग्रेस हटाओ लेकिन इस देश की गांधी-नेहरू की विरासत को खत्म करने का काम मत करो।

उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे दाएं बाजू के साथी और बाएं बाजू के साथी भी और सुनना चाहते थे लेकिन आपके समय की प्रतिबद्धता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: आपने बहुत अच्छा बोला। It was interesting. Now, Prof. Ram Gopal Yadav. ...*(Interruptions)*...

श्री तरुण विजय (उत्तराखण्ड): मैं त्यागी जी के बारे में यहां दो करेक्शन करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: अपना टाइम आने पर बोलना।

श्री तरुण विजय: मैं आपका मित्र हूं चौधरी चरण सिंह जी के समय से। लेकिन आपने तिरंगा जलाने वाले और तिरंगे के लिए जान देने वाले, दोनों की तुलना करके बहुत दुखी किया। मुनव्वर राणा मेरे भी दोस्त हैं। उन्होंने लिखा कि -- "तेरे आगे अपनी मां भी गंगा जैसी लगती है, तेरी गोद में गंगा मैय्या अच्छा लगता है।" वह एक देश भक्ति की पराकष्ठा है, जिन्होंने यह लिखा कि -- "जिस जगह से सिन्धु गुजरे समझो हिन्दुस्तान है", तो उसका भी आप जिक्र करिए और तिरंगा जलाने वाले और तिरंगे के लिए जान देने वाले, दोनों को बराबर मत तौलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, अब केवल 5 मिनट बाकी हैं इसलिए कल किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Today morning, when we discussed, it was informally said that we might extend the time by one hour that is, up to 7.00 p.m. if the House agreed. ...*(Interruptions)*... Kindly listen to me. I will explain the problem. I have a long list of speakers. Unless we extend the time and sit up to 7.00 p.m. today, it will be very

difficult tomorrow. Therefore, let us extend the House up to 7.00 p.m. Now, all of you kindly take your seat. बैठिए-बैठिए। And, Mr. Minister of Parliamentary Affairs, you should be here. I need your help. बोलिए-बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा प्रारम्भ हुई है और नक़वी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं वहीं से ही अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। ...**(व्यवधान)**... श्रीमन्, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह ऐसा वक्त होता है कि इस समय हाउस आर्डर में नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. ...*(Interruptions)*... Please, maintain order in the House. ...*(Interruptions)*... Those who are talking, please take your seats. ...*(Interruptions)*... Either you go out or take your seats. Don't stand in the passage.

प्रो. राम गोपाल यादव: उपसभापति महोदय, हमारे काबिल दोस्त नक़वी साहब ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आखिरी पैरा को क्वोट करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण शुरू किया और उसमें स्पष्ट जनादेश का उल्लेख किया है।

मान्यवर, श्री त्यागी जी ने स्पष्ट रूप से और इशारों से भी अपनी बात कह दी है। मैं भी कहना चाहता हूं कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि स्पष्ट जनादेश पाने के बाद भी वे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। महोदय, अगर अतीत से कुछ सीखा तो अपने को संभाल कर हम कुछ कर सकते हैं और अगर नहीं सीखा, तो 1947 से 77 से लगातार स्टेबल व पत्थर की चट्टान की तरह मजबूत मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स इस देश में रही हैं, लेकिन देश कहां से कहां पहुंच गया, वह सब ने देखा है। आप याद रखिए कि जब-जब असामान्य परिस्थितियों में जनता ने अपना आदेश दिया है, उसके बाद का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं रहा है। चाहे वह 1971 की हवा हो, चाहे 1977 की हवा हो, चाहे 1984 की हवा हो, उसके बाद सभी पार्टियां हारी हैं। वर्ष 1984 में उनकी 414 सीट्स आई थीं, आप तो 282 सीट्स ही ला पाए हो। इसलिए अगर अतीत से कुछ नहीं सीखोगे और अतीत से सीखकर जो वायदे किए हैं, जो सपने चुनाव के दौरान आपने दिखाए हैं, आपने जो अच्छे सपनों के सौदागर की तरह से वायदे किए हैं, वे आपके लिए मुश्किल समय लाने वाले हैं। आप सफल सौदागर साबित हुए हैं, लेकिन अगर उन सपनों को मूर्तरूप देने का काम नहीं किया, तो आपने अपने भाषण को जिस बात से शुरू किया है, उसका अंतिम रिजल्ट बिल्कुल फ्यूटाइल होगा, वह आपके पक्ष में नहीं होगा।

महोदय, मैं कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात रखने से पहले प्रस्तावक और समर्थक की एक-एक बात की चर्चा करूंगा। महोदय, अब सदन के नेता श्री अरुण जेटली जी हैं, वह इस तरफ बैठते थे, इसलिए उन्हें नेता विरोधी दल कहने की आदत पड़ गयी है, जबकि अब वह माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने इस सत्य को स्वीकारा भी है। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि nobody is bound to rule for ever. यह अच्छी बात है कि उनके दिमाग में यह चीज़ है। उन्हें पुरानी-पुरानी बातें याद हैं।

6.00 P.M.

महोदय, नड्डा साहब ने कहा कि इंट्रोस्पैक्शन की जरूरत है। मैं भी कहता हूं कि इंट्रोस्पैक्शन की जरूरत है क्योंकि ये लोग 10 साल तक सत्ता में रहे, तब बीजेपी ने इंट्रोस्पैक्शन किया और ऐसा इंट्रोस्पैक्शन किया कि जो लोग बीजेपी को इस स्थिति में लाने वाले थे, उन सारे नेताओं को किनारे लगा दिया। यह जो आपने इंट्रोस्पैक्शन किया, मेरी समझ में इस तरह का इंट्रोस्पैक्शन भी अच्छा नहीं होता।

महोदय, इस अभिभाषण में 50 पैरा हैं, लेकिन मैं सबसे पहले कृषि की बात करूंगा। इसमें एग्रीकल्चर में, खेती में लाभकारी मूल्य की बात कही गई है। त्यागी जी ने अभी बात ही दिया है कि जो कमिशन होता है, वह मूल्य निर्धारित करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो। मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चार साल चेयरमैन रहा हूं, जब मैं उस सदन में चौदहवीं लोक सभा का सदस्य था। तो उस समय कमिशन से पूरी कमेटी ने जिद की थी कि आप यह बताइए कि किस तरह से आप यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकालते हैं और हमें यह भी बताइए कि जो व्हीट और पैडी है, इसकी प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल कितनी लागत आती है? तब उस वक्त बामुश्किल कमिशन ने कमेटी को यह बताया था कि लगभग आठ सौ प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं की लागत आती है और उससे थोड़ी ज्यादा पैडी की आती है। उस वक्त जो यह लागत थी, आप आश्चर्य करेंगे कि आपकी एमएसपी उससे कम थी। तब हम लोगों ने कहा कि जब एमएसपी लागत से कम हो, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा? मुझे कमेटी के सदस्यों को लेकर उन जगहों पर भी जाना पड़ा, जहां किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, जहां पूरे के पूरे परिवार ने, जैसे कोलार में आत्महत्या की, तो उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा बचा था। हम उस घर में भी गए। जब इस तरह के लोग कमिशन में होंगे, तो आप किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिला सकेंगे। इसलिए जो भी सीएसीपी, या जो भी कमिशन बने, अगर उसमें किसानों के प्रतिनिधि नहीं होंगे, खेती-बाड़ी को जानने वाले नहीं होंगे, तो किसानों का भला होने वाला नहीं है। अभी तो उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो गेहूं और बाजरे में अंतर नहीं जानते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जानते हैं, वे हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। आप बताएं कि क्या यह सही नहीं है? जब ऐसे लोग वहां होते हैं और मूल्य तय करते हैं, तो देश का किसान कैसे संपन्न होगा? देश की आजादी के बाद अगर आज भी कोई सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। आज भी 63-64 परसेंट से लेकर 66 परसेंट तक लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन खेती पर जो लोग निर्भर हैं या जो किसान हैं, उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है।

महोदय, 1950 में इस देश में जो जीडीपी था, उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा 50 फीसदी था, जो अब 13 परसेंट के आसपास रह गया है। उस समय खेती पर 72 परसेंट, 74 परसेंट लोग निर्भर करते थे, अब भी 63-64 परसेंट लोग निर्भर करते हैं। स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि खेती सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं है। इसलिए हम लोगों ने बार-बार यह बात कही है और यह कहा है कि जो लागत मूल्य आए, उसका कम से कम डेढ़ गुना किसान की उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, जो उसको मिलना

चाहिए। जब तक आप यह नहीं करेंगे, तब तक किसान के लिए खेती घाटे का सौदा ही रहेगी।

महोदय, यहां फूड प्रोसेसिंग की भी बात की गई है, जो इस खेती से जुड़ा हुआ है। कुछ साल पहले तक यह कृषि मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय अलग बनाया गया है। गवर्नमेंट अभी तक इस फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम बजट देती रही है। अब देखते हैं कि यह गवर्नमेंट इधर क्या करती है? बजट आने वाला है। माननीय वित्त मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ये बातें नोट हो रही होंगी। फूड प्रोसेसिंग इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार लगभग पचास हजार और साठ हजार करोड़ प्रति वर्ष के बीच का लॉस है, जो कुछ साल पहले पचास हजार करोड़ था। जो पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और जो मांस वगैरह है, वह नष्ट हो जाता है, जिसकी वेल्यू लगभग पचास हज़ार करोड़ से साठ हजार करोड़ रुपए सालाना है। इतने बड़े पैमाने पर लॉस होता है, without proper food processing. केवल दो परसेंट या ढाई परसेंट के आसपास फूड प्रोसेसिंग हमारे यहां है। ब्राज़ील में यह अस्सी फीसदी है, अमेरिका और इंग्लैंड में सत्तर परसेंट के आसपास है, लेकिन हिंदुस्तान में दो और ढाई परसेंट है, जो कुछ दिनों पहले एक परसेंट ही थी। इसलिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बजट सेशन में इसके लिए प्रोविज़न किया जाना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं लोक सभा में था, उस वक्त मैंने अपनी पार्लियामेंटरी कंस्टीट्यूएंसी में देखा कि वहां बहुत बड़े पैमाने पर टमाटर होता था। कभी-कभी जब मैं वहां जाता था तो पता चलता था कि ट्रकों के ट्रक टमाटर पड़े हुए होते थे। मैं जब पूछता था कि क्यों पड़े हैं, तो पता चलता कि उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए फेंक दिए। तो इस प्रकार सब सब्जियां बेकार हो जाती हैं, सब फल बेकार हो जाते हैं। एक-दो दिन से ज्यादा वे चल ही नहीं पाते हैं। आलू के अलावा किसी के लिए ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। आलू के लिए तो कोल्ड स्टोरेज हैं, जहां वह बचता है, वरना दूसरे किसी फल या सब्जी के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रोसेसिंग का कोई तरीका नहीं है। दुनिया में दूसरी जगहों में तो यह होता है। सारा सेब विदेश से आ रहा है और यहां बिक रहा है। खान मार्केट से सेब लीजिए, ऐसे लगता है कि बिल्कुल ताज़ा है, जबकि हमारे यहां का लें तो वह खाया ही नहीं जाता है। दो दिन बात ही उसमें ऐसा फर्मेन्टेशन हो जाता है कि अजीब स्थिति हो जाती है, इसलिए इस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगा कि अगर आप किसानों को सम्पन्न देखना चाहते हो तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जो लागत आए, उसका कम से कम डेढ़ गुना पैसा उनको मिले, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए जाने चाहिए, ताकि जो बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, औने-पौने दामों पर लोगों को अपनी सब्जी बेचनी पड़ती है, फेंकनी तक पड़ती है, तो फल सड़ जाते हैं, वे बच सकें और उनको उसकी वाजिब कीमत मिल सके।

महोदय, इसमें वाटर सिक्योरिटी की बात भी कही गयी है। पानी के संरक्षण के बारे में यह बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार जल स्तर नीचे

जा रहा है। सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, वे कुछ वर्षों में फेल हो जाते हैं। पीने के पानी के लिए जो हैंड पम्प लगाए जाते हैं, वे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है, वह नदियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। उसको रोकने की, उसका संचयन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इसके संचयन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अगर ज़मीन को रीचार्ज नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा, जब सारी जमीन बंजर हो जाएगी और ज़मीन की सिंचाई के लिए पानी तो दूर, पीने के पानी की भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। हमारे बुन्देलखंड में हर बार ऐसी समस्या होती है। मैं एक बार दक्षिण भारत में रंगा यूनिवर्सिटी में गया था। वे मुझे वहां नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए ले गए। उन्होंने बताया कि वहां पहले नदियों में पानी आता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए ड्रिप सिस्टम से वे वहां सिंचाई कर रहे थे, क्योंकि पानी खत्म हो गया है और स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो पूरे देश में यह स्थिति खराब हो रही है, इसलिए जो आपने कहा है, और अच्छा होता यदि इसमें एक लाइन यह जोड़ी जाती कि इसके लिए हम इस तरह से ये-ये काम करेंगे, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, वाटर सिक्योरिटी के लिए यह बहुत जरूरी है और हमने कहीं पढ़ा भी था कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जितने पैराग्राफ्स हैं, वे सब के सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर सही दृष्टि से उन पर अमल किया जाए तो देश का कल्याण हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगर ये केवल सपने ही रह गए – हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, हमारे नेता डा. लोहिया कहा करते थे कि सपना बड़ा देखिए। जो बड़ा सपना नहीं देख सकता, वह बड़ा काम नहीं कर सकता। मोदी जी ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन केवल सपने बेचने का काम करने से काम नहीं चलेगा, इनको जमीन पर उतारने से काम चलेगा।

सर, इसमें विदेशी नीति की भी बात की गयी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं। उस देश की विदेश नीति सबसे सफल मानी जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने मित्र देशों की संख्या में वृद्धि और शत्रु देशों की संख्या में कमी करता है। मित्र बढ़ें और शत्रु कम हों, अगर इस तरह की विदेश नीति है, तब वह सफल है। दूसरी बात यह है कि विदेश नीति का मूल मंत्र यह होता है कि देश का हित सर्वोपरि हो। हमारे देश की लाखों वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में है और चीन अब भी हमें आंख दिखाता रहता है। पता नहीं, ये आंख मिलाकर बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी यहां अकेले बैठे हुए हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं?

श्री डी. राजा: कैबिनेट मिनिस्टर।

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं कह रहा हूं कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वे पीछे की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : गोयल जी भी यहां बैठे हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: वे तो बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। उनके पिताजी हमारे दोस्त थे। वे भी मिनिस्टर थे। मैं यह कह रहा था कि लाखों वर्ग मील ज़मीन है। प्रतिदिन चीन की सेनाएं एक-दो फुट आगे बढ़कर हमारी ज़मीन पर लाल निशान लगा जाती हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इनके ज़माने में भी यह मामला उठाया गया था। वे लोग 15-15 किलोमीटर अंदर घुसकर टेंट लगाकर उसमें आकर बैठ जाते हैं। हमारी यह सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पता नहीं आप हिम्मत करेंगे या नहीं करेंगे कि इस पर बात कर सकें? अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन खुलेआम कह रहा है कि वह हमारा हिस्सा है। हमारे चारों तरफ जो देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अच्छे होते तो किसी पर दबाव भी बनाया जा सकता था। एक वक्त था जब हमारे श्रीलंका से बहुत अच्छे रिश्ते थे, नेपाल से हमारे घरेलू रिश्ते थे, बंगलादेश तो हमारे सहयोग से ही बना, उससे बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब उनसे भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जब हमारे सब पड़ोसी ही हमारे खिलाफ हो जाएं या उनसे हमारे रिश्ते अच्छे न रहें तो हम किसी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं हो सकते कि हमारी विदेश नीति सफल है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी। देश कठिन से कठिन मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है। भूखा रहना बर्दाश्त है, लेकिन देश की सीमाएं नहीं सिकुड़ें, इसके लिए सारा देश हमेशा एक रहता है। जब ये लोग यहां बैठे थे, हम लोगों ने एक बार नहीं, अनेक बार कहा कि पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश की ताकत, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके साथ हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सीमाओं को लोग अपने में मिला रहे हैं, इनको रोकने के लिए कदम उठाइए। जब पूरी संसद और संसद के माध्यम से सारे देश की जनता आपके साथ है तो आपको कदम उठाने में या बात कहने में क्या डर लगता है? दुनिया में कई ऐसे देश हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर उनके एक आदमी को मार दिया जाता है तो एक मिनट के अंदर हमला हो जाता है और बदला ले लेते हैं। हमारे लोगों के सिर काट कर ले जाते हैं, हम लोग जाते हैं, कंडोलेंस कर आते हैं, परिवार को कुछ मदद दे देते हैं, लेकिन सीमा पर आंख टेढ़ी करके बात नहीं कर सकते, यह स्थिति है। सीमाओं की सुरक्षा की जो स्थिति है, मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास जितनी जमीन थी, तब हमारी जितनी सीमाएं थीं, अब उससे कम है, बहुत कम है, बहुत सारे हिस्से पर दूसरे देशों के द्वारा कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का एक हिस्सा तो पाकिस्तान ने कब्जा ही लिया है। कुछ और हिस्सा कब्जा लेते, कारगिल में आ गए थे जब इनकी सरकार थी, इन लोगों को पता ही नहीं चला था। एक गड़रिया ने बताया था तब मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान की फौज कारगिल तक आ गई है। बाद में यह पता चला कि कारगिल की पूरी जमीन मुक्त नहीं हुई है, अभी भी कारगिल इलाके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। उसको लेने के लिए भी पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते। जब देश की जनता इस मामले में आपके साथ है, देश की पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है, उसके बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, देश की सीमाओं को वापस लेना तो दूर है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। इसलिए आपने जो सपने दिखाए हैं कि ऐसा होगा देश, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, अगर आंख मिलाकर

बात करेंगे, तो स्वागत है। हम आपको धन्यवाद देंगे, पूरे देश की जनता आपको धन्यवाद देगी कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा डेलीगेशन चीन से, पाकिस्तान से आंख मिलाकर बात कर रहा है। पाकिस्तान से तो कोई भी आंख मिलाकर बात कर सकता है, लेकिन असली चीज़ चीन से आंख मिलाकर बात करने की है और असली खतरा वहीं से है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक पैरा इंटरनल सिक्योरिटी पर भी है। देश को बाहर से भी ज्यादा खतरा देश के अंदर से हो गया है। जो नक्सलवादी हैं, जो माओवादी हैं, उनसे देश को खतरा हो गया है। मुझे याद है, एक बार नार्थ-ईस्ट के प्रभारी मंत्री श्री अरुण शौरी साहब थे। उनसे हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नार्थ-ईस्ट के लिए अलग से बजट ईयर-मार्क होता है। हर विभाग में दस परसेंट बजट नार्थ-ईस्ट के लिए रखा जाता है। उसमें जो पृथकतावादी लोग हैं, जो वहां extremists हैं, वे extortion करते हैं, वे पैसा ले लेते हैं। अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को दोबारा देखने के लिए जा नहीं सकता है। यह स्वयं शौरी जी ने स्वीकार किया और कहा कि अगर हम सीधे-सीधे एक-एक लाख, दो-दो लाख रुपया हर आदमी को दे देते, तो वहां का हर आदमी लखपति होता, लेकिन जो पैसा बजट के जरिए जाता है, वह उन तक नहीं पहुंचता क्योंकि एक ही चीज़ के बार-बार प्रोजेक्ट बनाकर, अलग नाम से दे दिया जाता है और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह स्पॉट पर वेरिफिकेशन करने जाए। आतंकवादी और उग्रवादी लोग पैसा ले लेते हैं, कुछ पैसा ठेकेदार लोग ले लेते हैं, वहां पर काम कुछ नहीं होता है। यहां तक कि कर्मचारियों के वेतन के लिए जो पैसा जाता है, उसमें से भी दो-तीन परसेंट उग्रवादी ले लेते हैं, इसके बिना वे पेमेंट नहीं होने देते हैं। यह स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और कई जगहों पर गवर्नमेंट की बहुत कोशिश के बाद और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बाद भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। इसके लिए पुलिस का मॉडर्नाइजेशन आवश्यक है। आज मैंने पेपर्स में भी पढ़ा है और टीवी में भी देखा है कि माननीय गृह मंत्री जी ने अनुमति दे दी है कि वहां हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे लोकेशन ली जा सके और कार्यवाही की जा सके। हालांकि केवल ताकत के बल पर ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जब जनता की लड़ाई के नाम पर अस्तित्व में आने वाले लोग लूटपाट करने लगें, लोगों की हत्याएं करने लगें और योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से विद्याचरण शुक्ल जी और उनके साथी मारे गए थे, ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं घटी हैं। ये इतनी दुखद घटनाएं थीं कि बल प्रयोग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में ये लोग सक्रिय हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हैं। पीपुल्स वार ग्रुप के जरिए, यह आंध्र प्रदेश से ट्रेनिंग देनी शुरू हुई थी। पता चला कि पहले यह ट्रेनिंग तमिल टाइगर्स ने उन लोगों को दी थी और वहां से बढ़ा और यह सीधा झारखंड होते हुए, नेपाल तक पहुंच गया। यह एक बहुत ही गंभीर खतरा है। हमारी आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है और कभी-कभी जब मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा को बाहरी खतरे से भी ज्यादा खतरा है, इन माओवादियों से, नक्सलवादियों से या पीपुल्स वार ग्रुप के लोगों से या और जो इन नामों से काम कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे।

इसमें शिक्षा पर भी चर्चा की गई है। आप जानते हैं कि चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन सब के पीछे ...**(व्यवधान)**... अभी कितना समय हो गया।

श्री उपसभापति: समय खत्म हो गया है।

प्रो. राम गोपाल यादव: अभी नहीं हुआ है, आप हमें बोलने दीजिए। शिक्षा में जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है, वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप उसको चाहे जितने अच्छे इंस्टिट्यूट में भेज दीजिए, यदि वह भुलक्कड़ है तो कुछ नहीं होगा। जो उसकी मेधा होती है, जो स्मृति होती है, वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर बुद्धिमान बच्चे के हाथ में कम्प्यूटर होगा, तो वह उससे बहुत कुछ सीख जाएगा। यदि उसे इंजीनियर बनाओगे तो वह उससे लाभ उठाएगा। हमारी शिक्षा मंत्री जी का नाम तो स्मृति है, वे स्वयं नाम से मेधा हैं। वे क्या करती हैं, यह देखना है, लेकिन इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा और बच्चों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये जितनी आधुनिकतम सुविधाएं हैं, वे बहुत सम्पन्न और शहरी लोगों को ही प्राप्त हो पा रही हैं। इसलिए गैर-बराबरी और बढ़ती चली जा रही है। गांव के गरीब आदमी का बेटा इन शहरी और सम्पन्न लोगों से कम्पिटिशन नहीं कर सकता है।

आप देखेंगे कि दिल्ली में एक घर में पांच-पांच आई.ए.एस. और दस-दस इंजीनियर्स हैं। दूसरी तरफ आप गांव में चले जाइए, तो दस-दस जिलों में एक आई.ए.एस. भी नहीं मिलेगा। पचास-पचास लाख और एक-एक करोड़ की आबादी में कोई एक भी आई.ए.एस. नहीं मिलेगा और यहां पर तो एक-एक घर में मिल जाएंगे। यह आई.ए.एस. है, यह आई.एफ.एस है. यह इंजीनियर है, यह चीफ इंजीनियर है। एक तरह से यह गैर-बराबरी हो रही है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी का बच्चा उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, जिनमें काफी सुविधाएं होती हैं। जब वे कम्पिटिशन में बैठते हैं तो वे आगे नहीं निकल पाते हैं। दिल्ली के तमाम ऐसे नर्सरी स्कूल हैं, जिनमें एडमिशन लेने के लिए बीस-बीस लाख, पचास-पचास लाख डोनेशन देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि उनसे निकला हुआ बच्चा बनेगा आई.ए.एस. या बारह आना या एक रुपया फीस देकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उनका कैसे मुकाबला कर सकता है? आप यह दोहरी शिक्षा प्रणाली खत्म कीजिए और सबके लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करवाइए। यह बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर चाहें तो प्रधानमंत्री जी यह करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे इनकी एक ही बात अच्छी लगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन्होंने अपनी बात हिंदी में ही कही। यह नहीं कि यदि तमिलनाडु में चले गए, वहां भाषण देने लगे तो अंग्रेजी में बोले। वे हर जगह हिंदी में बोले। जिस बैकग्राउंड का आदमी होता है, वह समझता है कि अगर हम इस तरह का काम करें तो आम लोगों को भी लाभ मिल सकता है। लेकिन वह जिन लोगों के बीच में है, वे सब हाई-फाई हैं। आप यह ध्यान रखिए। अब यह समान शिक्षा की बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हम लोग तो डॉ. लोहिया के जमाने से कहते-कहते थक गए, पर नहीं कर पाए। अगर प्रयास करें, तो हो सकता है। पिछली बार गवर्नमेंट ने यहां पर किया भी था कि दाखिले के लिए मां-बाप का टेस्ट नहीं होगा। पहले मां-बाप को भी इंटरव्यू देना पड़ता था। बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है, मां-बाप का टेस्ट हो रहा है।

श्री उपसभापति: अभी आपका टाइम ज्यादा हो रहा है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, केवल एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं। ब्लैक मनी की बात हो रही है। ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार की बात है। मुझे नहीं लगता कि ये ब्लैक मनी वापस ला पाएंगे, क्योंकि उस समय तो चुनाव हो रहा था। हम सभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमको केवल बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ रहा था, एक ऐसे गठबंधन से लड़ना पड़ रहा था, जो बीजेपी और मीडिया का था। यह गठबंधन बीजेपी और मीडिया का था। यह एक बहुत बड़ा एलायंस था, जिस एलायंस का हम मुकाबला नहीं कर पाए। आपका जो एलायंस पार्टनर था, उस पर इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया, आप इस ब्लैक मनी को कहां से निकालेंगे? आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इस काले धन को रोकने के लिए कोई सक्षम उपाय कीजिए। आपने जो वादा किया है, जो आपकी सरकार का डॉक्यूमेंट है, महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अभिभाषण के जरिये देश के सामने रखा है। इसलिए आपने जो कहा है, अगर उस पर ईमानदारी से अमल करेंगे तो देश की जनता ने आपको जो अभी बहत जबर्दस्त समर्थन दिया है, वह कुछ दिन आपके साथ रहेगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो जितनी तेजी से आपको समर्थन मिला है, वह नहीं रहेगा। ऐसे-ऐसे लोग एम.पी., जो आप प्रधान का चुनाव लड़ें, तो हार जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर काम करना है तो इन सारे वादों पर ईमानदारी से काम कीजिए, देश की जनता की भलाई कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Ram Gopalji. Now, Shri Devender Goud. Mr. Goud, you have two speakers from your Party. There is one more speaker. If only you are speaking from your side, then you can take your full time.

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. There is a confusion in my Party. Actually, my colleague also wants to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No problem. Both of you can speak. Then, you can take nine-ten minutes.

SHRI DEVENDER GOUD T.: Sir, on behalf of our party, and on my own behalf, I want to thank the hon. President for his Address which he gave in the joint Session of Parliament. Sir, I was keenly observing the proceedings of this august House. The LoP has said that 90 per cent of their Schemes are there in the President's Address. Many intellectuals and very well experienced people are there in the Congress. They must interact among themselves that why for the first time after Independence, their Party has been thrown away and there is no opposition at all in the People's House; why has this happened that in spite of 90 per cent implementation of your schemes, people didn't believe you. You must realize it and you must interact amongst yourselves as to what is the reason for it. Instead of criticizing them, they must introspect why

people have denied the Congress Party even the status of having the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. That is what I want to say. I want to make one request to the present Government. A new development has taken place in my region. A new State has been formed. I hope that the Government of India will cooperate in the development of the two States of Andhra Pradesh and Telangana. The Pranahita Chevella Project must be declared a national project for the benefit of the people of that region. Many things have been promised by the new Government. We are hopeful and confident about the Government's promises. They know the problems of both the States very well. They have promised many things during the elections. I hope that they would keep the promises and help develop both the States.

Thank you, Sir. We don't want to take much time. Let us give time to the present Government. You may give suggestions to them at this stage, but not criticize them. The only suggestion I wish to make to the Congress Party is that they must introspect, instead of criticizing others, as to why the people have not believed in them and given them even the status of having the Leader of Opposition in the Lok Sabha. You must understand the reality and introspect. Your leader of Opposition himself said that 90 per cent of your programmes have been included in the President's Address. If you had implemented 90 per cent of the programmes, then why did the people of this country reject you? You must realize that. You must introspect. There are many points given here, such as internal security and others. I do not wish to go into the details of the President's Address. As it is a new Government, let us give them time. Since today morning I have been listening to all the speakers. Shri Ghulam Nabi Azad said that 90 per cent of their Government's programmes have been included in the Address. If that were really the case, then they must introspect why the people have not given them even the status of Opposition. They must introspect. Thank you, Sir.

श्री डी.पी. त्रिपाठी (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमारे परम मित्र मुख़्तार अब्बास नक़वी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव और माननीय श्री नड्डा जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मुझे अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। 11 मार्च, 1999 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय अटल जी ने कहा और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं – "हम आलोचना का स्वागत करते हैं। निंदकाचे घर असावे शेजारी – मराठी की एक कहावत है। "निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।" आलोचना करने वालों को अपने पास रखो, क्योंकि हां में हां मिलाने वाले आपका फायदा नहीं करेंगे।" यह अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए 11 मार्च, 1999 को कहा था। उसी संदर्भ में सबसे पहले मैं यह जनादेश मिलने के लिए और आप लोगों को, जो इधर से उधर गए हैं,

अब सत्ता में आए हैं, आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी जनादेश की बहुत चर्चा हुई है। सबसे पहले इस जनादेश पर ही कुछ बात कर ली जाए। इस चुनाव में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जिनको सामाजिक-वैज्ञानिक social-scientist paradigm shift कहेंगे। यह भारतीय राजनीति में आजादी के बाद पहली बार हुआ है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने योग्य और पढ़े-लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन में है, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, जो कि इस जनादेश की सबसे सकारात्मक बात है। भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गौरव और गरिमा है, पहली बार इस जनादेश में एक गरीब परिवार से आया है। यह इस देश के लिए सबसे गौरव की बात है।

इस जनादेश की दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसका जिक्र अभी प्रो. राम गोपाल यादव जी ने किया और हमारे मित्र के.सी. त्यागी जी ने भी किया, उसको जरा सैद्धांतिक स्तर पर ऊपर ले जाइए, सिर्फ हिन्दी बोलने की ही बात नहीं है कि पहली बार भारत का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर non-anglicized है, कम्प्लीटली अंग्रेजीदां नहीं है। यह पहली बार हुआ है। पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं है, पब्लिक स्कूल को हम misnomer कहते हैं, क्योंकि असल में वह साहब स्कूल है, पब्लिक स्कूल का उससे कुछ लेना-देना नहीं है।

इस जनादेश में इस देश के लोकतंत्र की एक और बहुत बड़ी शक्ति है। ये दो सकारात्मक बातें हैं। एक और तीसरी बात हुई है, जहां मैं सहमत हूं, क्योंकि वह जनता के सपनों का, जिसका जिक्र अभी प्रो. राम गोपाल यादव जी कर रहे थे, उसे जाहिर करता है। बात यह है कि इस चुनाव ने आशा और बदलाव के लिए वोट दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके आगे जाकर मैं यह आपको आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि इस विजयी बहुमत के साथ आप आए हैं, एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में हम हमेशा आपका सहयोग करेंगे। लेकिन, इसका भी आपको विश्लेषण करना चाहिए कि इस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 31 प्रतिशत, जिसका जिक्र हमारे मित्र देरेक ओब्राईन ने किया और एन.डी.ए. को लगभग 39 प्रतिशत वोट मिले। यानी अगर आप इस जनादेश को देखें कि उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भी तमाम जगहों पर आपकी जीत का जो अन्तर है, वह बहुत बड़ा है। तो इस तरह से इन रूपों में यह जनादेश ऐतिहासिक है, लेकिन इसका बहुत विनम्रता से विश्लेषण करना होगा।

मैं आप सबसे एक विशेष अनुरोध करूंगा। मैं चूंकि उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता, जो अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, कुछ नयी बातें ही आपके विचार के लिए रखना चाहता हूं। अभी यहां माननीय वित्त मंत्री भी नहीं हैं, तो भी, वे नयी बातें मैं रखना चाहता हूं। एक तो इस देश की तीन सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनका महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र ही नहीं है, जैसा कि अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने, नेता सदन ने कहा कि यह हमारी सरकार का रोड मैप है, लेकिन उसमें ये तीन बातें हैं, जिनका जिक्र नहीं है। वे ये हैं कि इस भारत में लगातार जितनी सरकारें आईं, सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रही है – बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर इन पचास पैराग्राफ्स

में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, जो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इतने योग्य लोग नयी सरकार में हैं, फिर भी ऐसा कैसे सम्भव हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बहुत बड़ी बात, क्योंकि यहां 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की बात कही गयी है, जब तक 'सभ्य भारत' नहीं होगा, तब तक वह श्रेष्ठ भारत भी नहीं होगा। अब यह सभ्य भारत कैसे होगा? जिस देश में बच्चों पर इतने अत्याचार होते हैं, children atrocites पर पिछली सरकारों ने तमाम एक्ट्स बनाए हैं, तो बच्चों पर अत्याचार का जिक्र भी इन पचास पैराग्राफ्स में कहीं नहीं है। जिस देश में, जिस समाज में बच्चों पर अत्याचार हो, उससे असभ्य और बर्बर कोई नहीं हो सकता है। जब देश को, समाज को सभ्य बनाने की बात है, तभी श्रेष्ठता की तरफ जाएं। इसमें उसका जिक्र नहीं है।

महोदय, जलवायु परिवर्तन, जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, उसका जिक्र तो किया गया है, लेकिन उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका जिक्र नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनका जिक्र तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं है और इस पर आप धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं और इसका जिक्र भी किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण हुए हैं, उनसे बिल्कुल अलग है, qualitatively different है। यह क्यों है, वह मैं बताता हूं। उसका भी जिक्र श्री देरेक ओब्राईन ने एक वाक्य में किया है, सीताराम येचुरी जी ने एक वाक्य में कहा, लेकिन उसको जरा और ऊंचें स्तर पर देखिए। 25 अक्टूबर, 1999 को अटल जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार जीत कर आई थी, उस समय जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ था, उस अभिभाषण को मैं अभी पढ़ रहा था। उसमें भी चुनाव अभियान के दौरान का कोई नारा या वाक्य का जिक्र नहीं है। यह महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण है, जिसमें सरकार ने अपने भविष्य की योजनाओं को रखते हुए चुनाव अभियान के दौरान कही गई सभी बातों को समाहित किया है। यह महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण है, जिसमें ये सारे नारे शामिल हुए, इसलिए यह qualitatively different है। पहली बार ऐसा अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन में हुआ है। अगर आप एक नारा छोड़ दें, जिसकी जरूरत नहीं थी, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि खाली "अबकी बार मोदी सरकार" इसको अगर छोड़ दें, तो चुनाव के जितने नारे थे, सब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडु: उसको इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वह तो हो गया।

श्री डी.पी. त्रिपाठी: हां, वह तो हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यह कैसे गुणात्मक रूप से अलग है। एक और बात जिस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, यहां वेंकैया जी हैं और तमाम लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, माननीय सदस्यगण हैं, इतने विद्वान विधिवेत्ता और वकील आपके साथ हैं, अरुण जेटली जी से लेकर रवि शंकर प्रसाद तक, तो यह जो पैरा 23 है, जिसमें आपने कहा है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम कृतसंकल्प हैं, determined हैं, और पहले कदम के रूप में हम एसआईटी ले आए हैं। इतने सुप्रसिद्ध वकीलों के होने के बावजूद आप लोग यह कैसे भूल गए हैं? इस पर मुझे अचंभा होता है कि इस अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार को इसके लिए एसआईटी बनाना पड़ेगा और जहां तक मुझे जानकारी है ...**(व्यवधान)**...

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): उसकी स्थापना की गई।

श्री डी.पी. त्रिपाठी: उसमें जजेज़ के नाम भी आए हैं, जिनके नाम आपने लिए हैं। वे भी सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाए थे और इसके लिए एक डेडलाइन दी गई थी। मैं उतना बड़ा वकील तो नहीं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने विद्वान लोगों से, पढ़े-लिखे लोगों से यह भूल कैसे हो गई, उसमें मुझे बहुत अचंभा हो रहा है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया, जो बहुत बड़ी बात इस अभिभाषण में है, वह पैराग्राफ 24 है। इसमें आपने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की बात की है। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की जो बात आपने की है और कहा है, 'Justice delayed is justice denied.' ये सब उसमें है। समय बचाने के लिए मैं उसको उद्धृत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे स्मरण है। यह न्याय व्यवस्था में जो परिवर्तन की बात है, वह खास तौर से criminal justice के principle में जब तक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक समाज की civility का पता भी नहीं लगता। कोई भी देश या समाज कितना सभ्य है, वहां फौजदारी न्याय की क्या व्यवस्था है, यह उससे पता लगता है। आज हमारे देश में ऐसी विचित्र स्थिति है कि अपराधी कानून से डरता नहीं है और पीड़ित को न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, तो इस अवस्था को बदलना होगा। मैं यह बात सभी मित्रों से कह रहा हूं, आपके भी बहुत से नेताओं से की और हमारी पार्टी में जो वकील हैं, एक-आध राज्य सभा में भी आए हैं, बहुत एमिनेंट वकील, मंजीत मेमन साहब, उनसे मैं इसको डिस्कस करता हूं। इस पर किसी माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिलाया। लेकिन अगर आप हमारे देश में न्याय व्यवस्था को देखें, तो हिन्दी कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं:-

"ओढ़कर क़ानून का चोगा खड़ी चंगेजशाही,
न्याय का शव तक कचहरी में नज़र आता नहीं।"

आज हम राजनीति पर बड़ी चर्चा करते हैं। मैं मानता हूं कि राजनीति में पतन हुआ है, राजनीति के वे मूल्य कमजोर हुए हैं जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन न्याय-व्यवस्था, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो एक तरह से उसका आलोचनात्मक स्तम्भ होता है, सुधारात्मक स्तम्भ होता है, अगर वही चरमरा जाएगी, तो देश की हालत क्या होगी? इसलिए उस पैरा 24 के लिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे और मैं चाहूंगा कि सभी दल हमारे देश में मिलकर एक आम राय बनाएं कि न्याय-व्यवस्था में किस तरह से सुधार हो सकता है। चूंकि हमारे पास बहुत ही योग्य क़ानून मंत्री, श्री रवि शंकर प्रसाद जी आए हैं, इसलिए हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पेश करते हुए नक़वी साहब ने एक और बात कही कि वे सकारात्मक होकर सोचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद यही कहा था कि मैं आशावादी हूं, आशावाद से ही सुधार हो सकता है और जो निराशावादी है, वह देश और समाज में आशा का संचार नहीं कर सकता। यह माननीय प्रधानमंत्री ने नेता चुने

जाने के बाद ही अपने भाषण में कहा। मैं यह मानता रहा हूं कि सकारात्मक दृष्टिकोण तो रखिए, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है, the best way to plan is to think of the worst. सबसे खराब क्या हो सकता है, जब आप यह सोचेंगे तभी आप सबसे अच्छी योजनाएं बना सकेंगे कि किस तरह से उसका मुकाबला किया जा सकेगा। आप दुनिया में सभ्यताओं के इतिहास को देखिए, संस्कृतियों के इतिहास को देखिए, जिसका जिक्र सीताराम येचुरी जी ने किया है और जिसका अभिभाषण में भी जिक्र है। अभिभाषण में हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक भारत की महान परम्परा का जिक्र किया गया है। वहां भी मुझे एक आश्चर्य यह है कि उसमें एक बार आपने कहा है कि हम भारत की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करेंगे। यह तो ऐसी बात हो गई कि जैसे देश की प्रतिष्ठा ही चली गई थी और उसको फिर से स्थापित करेंगे। मेरी समझ में यह भी नहीं आया है।

मैं यह कह रहा था कि जिस परम्परा को आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जिस महान परम्परा की बात आप कर रहे हैं, वह उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है, जिस प्रक्रिया से निकलकर यह बड़ा चुनाव, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों ने किया है, आया है, जो विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग और उत्सव है। लेकिन, उसी के साथ जब उन्होंने आशावाद का जिक्र किया तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अपनी परम्परा को ले लीजिए और दुनिया की हर जगह की सभ्यताओं और संस्कृतियों के इतिहास को ले लीजिए, राजनीतिक परम्परा और प्रणालियों को ले लीजिए, तो यह दुनिया आशा और निराशा दोनों से चली है, दोनों से आगे बढ़ी है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि आशावादी ने अगर वायुयान बनाया, तो निराशावदी ने पैराशूट बनाया। If the optimist made the plane, the pessimist made the parachute while thinking if the plane fails, what to we do? तब हम क्या करेंगे? इसलिए अगर इसको आप थोड़े ऊंचे स्तर पर ले जाकर सोचेंगे, तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस सबसे बड़ी चीज़ की जरूरत है, वह है एक निरंतर उत्साह, एक लोकतांत्रिक आम सहमति और सामाजिक सहमति। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सोशल कंसेंसस टूटेगा, तो उसका हम सभी को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसे राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

श्री उपसभापति: त्रिपाठी जी, आपका टाइम खत्म हो गया।

SHRI D.P. TRIPATHI: Sir, I won't take much time. I will abide by what you say. Let me just finish. मैं आपसे यह जिक्र कर रहा था कि वह सामाजिक समरसता, जो हम सभी को मिलकर बनाए रखनी पड़ेगी, उसी से देश की प्रगति को और गति मिलेगी।

आखिर में, अब चूंकि आदेश हो गया है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अपने निष्कर्ष पर जाते हुए फिर से आपको बधाई देता हूं... और संस्कृत का वही वाक्य कहता हूं - "शिवास्ते सन्तु पंथानम", आपके रास्ते शुभ हों, मंगलमय हों। लेकिन वे कैसे शुभ होंगे क्योंकि अभी तक चौतरफा स्वागत की सुगंध आ रही है, जय-जयकार हो रही है, अभिनन्दन हो रहा है। लेकिन अगर आप हिन्दी के महान साहित्यकार जय शंकर प्रसाद के दो वाक्यों को याद रखेंगे तो संभवत: जीवन में

बहुत मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता हुई माननीय वित्त मंत्री और नेता सदन का भाषण सुनते हुए, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई सरकार में स्थाई तौर पर नहीं आता। यह सही है कि कोई स्थाई तौर पर नहीं आता। मैंने चुनाव के पूर्व ही कहा था कि कोई मॉनोपौली पॉवर नहीं होती डेमोक्रेसी में। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे अच्छी बात है, उसी पर अच्छे दिन टिके रहते हैं। तो जय शंकर प्रसाद जी ने जो कहा, वह सत्ताधारियों को हमेशा याद रखना चाहिए – महत्वाकांक्षा का मोती। उन्होंने दो नाटकों में दो वाक्य कहे हैं। "महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है" और दूसरा वाक्य जो जय शंकार प्रसाद ने कहा है वह दूसरे नाटक में है – "अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है।" इसलिए आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये चार पंक्तियां हैं उस कविता की, और अगर आपके ध्यान में रहेगा तो इस खुशबू से, इस स्वागत की सुगंध में आप कहीं मादकता की तरफ नहीं जाएंगे कि प्रभुता आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी। इसमें दिल्ली शब्द को आप दिल्ली शहर नहीं मानें, यह दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए लोगों के विषय में है। मैं ये चार वाक्य सुनाकर अपनी बात समाप्त करुंगा। ये कविता की चार पंक्तियां हैं, यह आपके लिए विशेष तौर से आज के संदर्भ में हैं:-

"शौके सितम से, आप जरा बाज़ आइए,
दिल के नगर जला के, न दिल्ली सजाइए।
झुलसें न हाथ आपके, खुशबू की आंच में,
फूलों का रंग देख के, धोखा न खाइए।"

धन्यवाद।

SHRI H.K. DUA (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me a chance to speak on the Motion of Thanks to the President for his Address. It is a wide-ranging Address, touching issues of important concerns on a very broad field before the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Duaji, there are two Nominated speakers. So, you have fifteen minutes.

SHRI H.K. DUA: But, I will like to focus only on issues concerning foreign policy which has been neglected in the debate throughout the day. Nobody can differ with the broad content of the foreign policy approach that is to defend and to promote enlightened self-interest of the country. 'The enlightened self-interest of the country' the phrase came from Jawaharlal Nehru and it is still sustainable, and most of the parties in the House as well as all sections of wider society will support this approach of particular interest was the emphasis that this Government will seek and continue to seek better relations with all the neighbours — Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, Bhutan — and this is evident from the forthcoming visit of the Prime Minister to Bhutan and of the Minister of External Affairs to Bangladesh. All sections of the

House and people outside supported the invitation which was sent to the Leaders of the South-Asian countries to attend the swearing-in ceremony of the new Prime Minister. I have been a supporter of the moves made by Mr. Atal Bihari Vajpayee and Dr. Manmohan Singh for seeking peace with Pakistan. Unfortunately these did not mature into durable peace with Pakistan. The people know all the factors, I don't have the time to narrate what the factors are. But I am a little worried about the situation which is developing in the North-West of India. Look at the reports which are coming from Karachi. For three days a serious attack has been launched on the Karachi Airport. This is not an isolated incident. Pakistan has been in the grip of jihadi movements, fundamentalists and terrorists. Often there are similar incidents. But Karachi became the centre of this kind of attack after the Mehran attack earlier on its naval establishment. That it took three days for Pakistan to tackle the situation is a matter of concern not only for Pakistan but it is a matter of concern for us also. Recently, there was an attack on Indian consulate General in Herat. An Indian aid worker has also been kidnapped. There is an attack on Mr. Abdullah. Abdullah who is likely to take over as the President of Afghanistan. That is why I am referring to the situation developing in Indian's North-West. If the Pakistan Government is divided between its civilian Government and its military establishment, and there are some sections of its military like the ISI which are not having their own government, no one knows who will control the situation in Pakistan and Afghanistan. If there is fire next door, I don't think India can remain unaffected. If there is fire next door, despite our very good intentions for peace, and I have been a supporter of the peace moves, we cannot neglect the situation. The fundamentalists and jihadi elements have been objecting to any move which the civilian Pakistan Government would like to make. In the past, our experienced shows whenever there was a slight progress in the dialogue with Pakistan, there were attempts to scuttle that effort by staging terrorist attacks either on this side of the border or in their own country. The argument given is that Pakistani itself is a victim of terrorism. Yes, it is. But we are the victim of terrorism which is exported to us.

The President's Address says that there will be zero tolerance towards terrorism in India. The Pakistan Government is not able to say that there will be zero tolerance towards terrorism in Pakistan. Let us look at the scenario. If Pakistan fails to tackle terrorism on its soil and if it fails to prevent terrorists from creating incidents in India, it can lead to a very bad situation on the subcontinent. Also, this will have an impact on Afghanistan. The US troops are leaving Afghanistan by the end of year. A large chunk of troops have already left. Post there can be a vacuum in Kabul. We have

7.00 P.M.

invested considerable political, strategic and economic capital in Afghanistan during the last ten years as a matter of policy. We have spent two billion dollars worth of economic development funds there and it has helped in stabilising the situation in the strife-torn nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Duaji, one minute. I want to take the sense of the House. Can we sit for another thirty minutes?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, my request is this. We have to complete the discussion tomorrow by sharp 5 o' clock...*(Interruptions)*... The Prime Minister has to give the reply. It has been decided in the Business Advisory Committee or internal consultation that it will be over by that time. If the House wants to have discussion, you can continue for some more time so that other Members can also participate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyway thirty minutes is agreed to. I have another request to the Parliamentary Affairs Minister. Your Party and the Opposition Party have given a number of names. Please discuss and try to reduce the names. Please do that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are trying to do that. Both the MoS and the Deputy Leader are holding discussions and I hope they will be able to work it out. We don't want to do it arbitrarily.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please continue Mr. Dua.

SHRI H.K. DUA: Sir, I will cooperate and be brief.

Sir, in the situation in Pakistan and then in Afghanistan, which is likely to see the withdrawal of American troops this year, who will fill the vacuum? It is Pakistan-supported Taliban who would like to fill the vacuum. All accounts suggest that those are the plans. Already there are talks between Pakistan and Afghanistan Taliban. They have not given up the aim to come to power in Kabul and the attacks on Indian Embassies twice — earliest and the recent attack in Herat and the kidnapping of an Indian — show that the intentions are not benign as far as India is concerned. I would like that the Prime Minister should take the House into confidence as to how we are going to meet the situation after the American troops withdraw from Afghanistan. The USA is going to leave only 6,000 to 9,000 troops plus drones in Afghanistan. Now, drones can kill people, but they cannot control the situation on the ground. The 6,000 to 9,000 US troops or NATO troops which would be there cannot control the situation. We have entered into an agreement, a strategic partnership agreement, with the Karzai

Government. We are definitely giving them some arms training, but we also don't want to get involved in the imbroglio that is there in Afghanistan. Whosoever has gone into Afghanistan has burnt his fingers. There has to be some clarity in the Government about the various policy issues involved. I would like the Prime Minister to make a statement when he speaks tomorrow here in this House to make it clear as to what is our policy on Afghanistan, what is our policy in Afghanistan after the US troops pull out. We cannot let the effort which we have made for ten years for economic and political stability in Afghanistan go waste. We cannot afford a situation in Afghanistan which is against Indian interests. If the Government is not able to control the terrorists groups in Afghanistan, the situation can be worse. There is another danger of failure by the authorities, whatsover is there in power in Pakistan. They can divert the Taliban to Kashmir which can create another problem for us. So, I would like to suggest that the Prime Minister should make a statement on what will be our policy, how he is looking at it, how the Government is looking at the developing situation in Pakistan and Afghanistan. I have a feeling that there will be consensus in the House as well as outside in the country for whatever policy we choose to adopt in respect of Pakistan. Even a peace initiative that the Prime Minister takes would be supported by the People and Parliament but the situation which is developing in the neighbourhood is not very congenial, Actually it should be a warning for us. There was talk of consensus by the Leader of the House which was responded positively by Mr. Ghulam Nabi Azad when he said that his party provide constructive opposition.

Sir, with this point, I will conclude. Consensus is certainly needed on foreign policy, security policy, both internal and international security and terrorism. Consensus is also needed on the working of this Parliament. This consensus was sadly missing during the last 3-4 years and it cost the nation and Parliament a great deal in prestige among the people. Initiative for evolving consensus has to come from the Prime Minister and his Government. I have a feeling based on the debate today. All sections of the House, Mr. K.C. Tyagi, Mr. Ghulam Nabi Azad, Mr. D.P. Tripathi and others, have responded to the idea of consensus. Consensus is very important for running the House, as well as, outside.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair will be very happy if there is a consensus.

SHRI H.K. DUA: Thank you very much for it, Sir.

I will just add an effective security policy, as well as, foreign policy will also

require a social coherence in the country for which we should all work for. Thank you very much, for giving me a chance to speak at this late hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Duaji, thank you very much. Now, Shri Sanjay Raut. You have only ten minutes.

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Okay, Sir.

डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुख़्तार अब्बास नक़वी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

सर, देश का माहौल बदला है। माहौल अंदर भी बदला है, माहौल बाहर भी बदला है और इस बदले हुए माहौल का प्रतिबिम्ब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दिख रहा है। सर, राष्ट्रपति जी ने नई सरकार को बधाई देते हुए कहा है – "तीस साल में पहली बार किसी को बहुमत मिला है।" इसका मतलब यह है कि इस देश में "डिवाइड एंड रूल" वाला राज अब खत्म हो गया है। राजनैतिक ब्लैकमेलिंग और वोट बैंक की राजनीति इस देश से खत्म हुई है, इसलिए मैं इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूं।

सर, मैं आज के अखबार में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां पढ़ रहा था। आनन्द शर्मा जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उनकी टिप्पणी पढ़ रहा था। उनका मानना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ शब्दों की बाज़ीगरी है। भाषण में कोई नई सोच या नया दृष्टिकोण नहीं है। इसमें वे सब नारे हैं, जो छः महीने से हम सुन रहे थे। अगर हम शर्मा जी की बात को सच मानें तो ये नारे वही हैं, जो नारे आप 60 साल से लगा रहे थे, लेकिन किया कुछ नहीं। इसलिए इन नारों पर नई सरकार काम करने की शुरुआत कर रही है। सर, देश में एक ऐतिहासिक प्रयोग की शुरुआत हो रही है और कुछ बातें पहली बार देखने को मिल रही हैं, जो शायद आपको हज़म नहीं होंगी। देश की दशा जिस तरह से बनी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए ही देश की जनता ने यह नई सरकार चुनी है। देश बर्बाद इसलिए नहीं होता कि देश के जो दुष्ट और भ्रष्ट लोग हैं, वे सक्रिय हैं। देश इसलिए बर्बाद होता है कि देश के अच्छे लोग निष्क्रिय होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, देश के सभी अच्छे लोग सक्रिय हुए और एक अच्छी सरकार, एक मज़बूत प्रधानमंत्री लाने के लिए सक्रिय हुए, अच्छे दिन लाने के लिए सक्रिय हुए और नतीजा हमने देख लिया कि इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री और एक मजबूत सरकार मिली।

डिप्टी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपनी सरकार गरीबों, युवकों और महिलाओं को समर्पित की है, उससे देश की जनता जानना चाहती है कि सरकार के दिमाग में क्या नई ठोस योजनाएं हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है? कश्मीर के बारे में, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की सोच क्या है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की सोच और प्राथमिकताओं का प्रतिबिम्ब साफ दिखता है।

सर, अब तक क्या हो रहा था? योजनाएं बहुत बनीं। कागज़ पर बनीं, फाइलों पर बनीं। इस सदन में हम भाषण सुन रहे थे, लाल किले से घोषणाएं हुई, लेकिन कुशासन की वजह से ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार ने निगल लीं, लेकिन नई सरकार का नारा है – "सुशासन द्वारा विकास"। इस बार देश की जनता ने, मतदाताओं ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और विकास और स्थिरता को लेकर, एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की दिशा स्पष्ट की है। सरकार ने ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के बारे में नए वायदे किए हैं। हमें विश्वास है कि ये वायदे पूरे हो जाएंगे। देश भर में सौ नए मॉडल शहर बनाने की बात सरकार ने की है, लेकिन जो पुराने शहर हैं, जो अब तक मॉडल शहर बने थे, जैसे मुम्बई, बैंगलुरू है, कोलकाता है, ये भी मॉडल शहर बने थे, उन शहरों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, मैं मुम्बई से आया हूं इसलिए मैं खासकर मुम्बई के बारे में जानना चाहूंगा कि वहां के बारे में सरकार की सोच क्या है? मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी रहा है। पूरा देश मुम्बई में बसता है। आज मुम्बई की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुम्बई जैसा शहर देश के रेवेन्यु में बढ़ोत्तरी करता है, वह देश की तिजोरी में दो लाख हजार करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यु देता है, लेकिन इसके बदले में मुम्बई को क्या मिलता है? यह सवाल हमने हमेशा किया है। मुम्बई के ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, मुम्बई की रोड का सवाल है, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सवाल है, उस बारे में नयी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और मुम्बई जैसे शहरों के विकास का रोडमैप बनाना चाहिए। मुम्बई की बहुत सी योजनाएं आज भी केन्द्र सरकार में अटकी पड़ी हैं। केन्द्र सरकार ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में विदेशों से काले धन की वापसी का निर्णय लिया है और इसके लिए एसआईटी का गठन किया है। विदेशों में जो काला धन है, वह जब आएगा, जा आएगा, लेकिन जो देसी काला धन है, जो हमारे देश में छुपा है, जो देश में छुपाकर रखा हुआ है, उसके बारे में सरकार कौन सा ठोस कदम उठाएगी, उस बारे में सोचना पड़ेगा।। यह जो काला धन है, जब चुनाव आता है, तब वह बाहर आता है। वह कहां से आता है? इस देश के काले धन की गंगोत्री हमारी चुनाव प्रक्रिया है। इसलिए चुनाव में काले धन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। उस बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस बार तो सभी को झटका लगा है – जातिवाद को लगा है, क्षेत्रवाद को लगा है और इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले सभी लोगों को जनता ने नकारा है। आश्चर्य की बात यह है कि हमेशा इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार रहे, उनको भी झटका लगा है। आज इस चुनाव में एक बात सबने देखी है कि इस देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, शिवसेना को वोट दिया है और उन्हें वोट देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि ये सभी समाज, सभी धर्मों के लोग आज विकास के पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, अब तक वोट बैंक की राजनीति चलती थी। उस वोट बैंक की राजनीति का सफाया हुआ है क्योंकि वहां का मुस्लिम समाज, वहां का दलित समाज भी चाहता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा रोज़गार मिले, उन्हें बुनियादी सुविधा मिले। ये सुविधाएं सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए नई सरकार का चुनाव हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है – "एक भारत-श्रेष्ठ भारत।" इस नारे का अर्थ स्पष्ट है कि इस देश में सिर्फ विकास ही धर्म रहेगा। इस देश में कोई अल्पसंख्यक

राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में न कोई अल्पसंख्यक रहेगा और न कोई बहुसंख्यक रहेगा। जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश को मातृभूमि मानता है, उसको वे सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो अन्य लोगों को मिलती हैं – यही हमारा उद्देश्य रहेगा। हमारे अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने मदरसों को आधुनिक बनाने की बात कही है। मुझे लगता है कि शिक्षा में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। धर्म की राजनीति, धर्म की शिक्षा से विकास नहीं होगा, इसलिए मदरसों को आधुनिक बनाने की बात की गयी है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमारी सरकार ने कही है कि कश्मीर में जो हमारे हिन्दू पंडित हैं, जो हमारे हिन्दू भाई हैं, उन्हें वापस घाटी में लौटाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। अपने देश में निर्वासित होने का दुख अब तक हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित झेल रहे थे, सालों-साल झेल रहे थे। उनके दुख, उनकी वेदना की फिक्र अब तक किसी ने नहीं की थी। कश्मीरी पंडितों को न्याय और हक देने वाली सरकार अब आ गई है, अब कश्मीर पर पूरे देशवासियों का अधिकार रहेगा, अब सिर्फ कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराएगा, इस प्रकार की सरकार इस देश में आई है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिसे मोदी जी ने कहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सरकार पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहती है, इस बात को हम भी मानते हैं। जिस तरह से सार्क देशों के सभी राष्ट्र प्रमुख नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, खास कर पाकिस्तन के प्रधान मंत्री, मियां नवाज शरीफ यहां आए, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। हमारी पार्टी हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने के खिलाफ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, उसके कारण हमने माना है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं होने चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... फिर भी, एक सरकार आई है, इसको एक मौका मिलना चाहिए। अगर यह मौका मिलता है, तो उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये लोग गले लगते हैं, मीठी-मीठी बात करते हैं और मीठी-मीठी बातें करने के बाद भी कभी कारगिल करते हैं, कभी हमारे जवानों का सिर काटते हैं, कभी कसाब की टोली मुम्बई में आकर हमला करती है। शांति होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मेरी पार्टी शिव सेना इस बारे में सरकार को अलर्ट करना चाहती है। मीठा शहद बनाने वाली मधु मक्खी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए आप होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं, फिर भी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारते हैं, तो मोदी सरकार को एक मौका मिलना चाहिए। पिछली सरकार ने 60 सालों में क्या किया, क्या नहीं, उस बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नई सरकार को कम से कम 60 महीने का समय मिलना चाहिए और 60 महीने के बाद सामने वाले हमसे पूछ सकते हैं कि हमने क्या किया? हम एक मजबूत देश बनाएंगे। ...**(व्यवधान)**... आपने 60 साल में क्या किया, इसका हिसाब हम नहीं मागेंगे। ...**(समय की घंटी)**... लेकिन 60 महीने के बाद हमने क्या किया है, उसका हिसाब आप जरूर मांग सकते हैं, यह हम आपको चैलेंज देते हैं।

श्री उपसभापति: संजय राउत जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय राउत: गंगा को पवित्र करने का जिम्मा हमारी सरकार ने उठाया है। गंगा पवित्र

होगी, लेकिन इस देश की जनता ने इस देश की राजनैतिक गंदगी को साफ किया है और वह एक पवित्र सरकार लाई है। इस देश की जनता ने पवित्र काम किया है। आप इस सरकार को काम करने दीजिए, इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि भारत वर्ष के एक अत्यंत महान अभ्युदय, एक अद्भुत सूर्योदय और एक नई सुबह के बारे में, मुझे यहां बोलने का अवसर मिला है। यह अनेक सदियों के बाद एक ऐसा क्षण आया है कि जब भारत में आसेतु हिमाचल, एक उत्सव का वातावरण हुआ, साधारण-साधारण भारतीय ने यह महसूस किया कि अब उसकी कठिनाई, अब उसके अंधकारमय युग, अब उसके भ्रष्टाचार का जो रोज़ जलवा दिखता था इस देश में, उससे वह मुक्त होकर, एक ऐसी सरकार के अंतर्गत भारत वर्ष के नये अभ्युदय का अभियान देखेगा, जो भारत वर्ष विश्व के परिदृश्य में अपना नियति द्वारा प्रदत्त स्थान प्राप्त करने के लिए तय है। श्री अरविंद ने कहा था कि हमेशा यह स्मरण रखो कि भारत अपनी नियति को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। वह नियति इसलिए नहीं है कि वह शक्तिशाली होकर दूसरों को दबायेगा। वह शक्तिशाली होकर अपने पड़ोसियों के ऊपर औपनिवेशिक शासन स्थापित करेगा बल्कि उसकी शक्ति, उसकी विद्या लोगों को निर्भय बनाने के लिए, लोगों को आश्वस्त करने के लिए एक सर्वपंथ सम्भाव का आदर्श वातावरण बनाने के लिए होंगी और 26 मई के दिन जब भारत के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में देखा कि भारत के नये प्रधानमंत्री ने तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, जिनमें नवाज शरीफ साहब थे, अफगानिस्तान के करजई साहब थे, नेपाल, बांगलादेश, भूटान, श्रीलंका, मालद्वीप एक ऐसा अद्भुत शक्ति का पुंज वहां पर दिखा और ऐसा लगा कि सम्पूर्ण विश्व को भारत वह संदेश दे रहा है, जो सदियों पहले ऋषियों ने सिंधु नदी के तट पर दिया था – वसुधैव कुटुम्बकम। सम्पूर्ण जगत हमारा परिवार है। हमारी किसी से शत्रुता नहीं और हम सबसे मित्रता चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ और हम उनके आभारी हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और उन्होंने नरेन्द्र मोदी जी का निमंत्रण स्वीकार किया। हम उनके कृतज्ञ हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब दिल्ली में आए और इस्लामाबाद जाकर बयान में कोई तब्दीली नहीं हुई और एक हवा बही कि उम्मीद है, एक हवा बही कि हर दिल में एक चिराग रोशन हो रहा है, हो सकता है कि हमारी उम्मीदें खरी उतरेंगी। हम लोग किसी के आतंक, किसी की शरारत को कभी सहन नहीं करेंगे, हम हिन्दुस्तानी हैं। हमने अपने इतिहास में दिखाया है, हमारा कोई देवी और देवता शस्त्र के बिना नहीं है। जब तक कोई अन-रिपेंटेड विकेट होता है, तो उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन अगर शांति की उम्मीद है तो क्यों न उसको मौका दिया जाए। मैं 13 बार पाकिस्तान गया हूं। मैंने वहां पर देखा कि साधारण जन में दो वर्ग हैं – एक भारत से शत्रुता रखते हैं, जिसमें तालिबान है, हाफिज़ सईद है, दाऊद इब्राहिम है, लश्करे तैयबा है, लेकिन एक वह वर्ग भी है, जो भारत से जेनुइन दोस्ती की इच्छा रखते हैं। यह बात मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान के विरुद्ध सबसे कठोर भाषा का इस्तेमाल करता है। मैं स्वयं अनुभव करके आया हूं, इसलिए मैं आपके सामने यह सत्य कह सकता हूं। सम्पूर्ण विश्व में एक उम्मीद जगी है। यूरोप में, अमेरिका में यह उम्मीद जगी कि यह नरेन्द्र मोदी का हिन्दुस्तान विश्व के पटल पर सबकी बराबरी के क्षेत्र में आ रहा है और उन्होंने सिद्ध किया कि भारत में विदेश नीति स्वदेश

को, उसकी सुराक्षा को, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

उपसभापति महोदय, आप देखिए कि उनकी विदेश यात्रा का क्या दौरा है। वे पहले भूटान जा रहे हैं, जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। वह हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है और बहुत ही अधिक सामरिक महत्व का देश है। वहां पर लोकतंत्र प्रफुल्लित हो रहा है, वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है, वहां पर राजा के स्थापित होने के बावजूद। वे भूटान के बाद टोकियो जाएंगे। भारत का एक श्रेष्ठ, सामरिक मित्र है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वह हमारा हर मौसम का मित्र है। इसलिए हमारे जापान के साथ जो रणनीतिक संबंध हैं, वे वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, They are one of the most important strategic bilateral ties in the present geo-political situation of the world. यह नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। वे टोकियो के बाद ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। ब्राजील में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी।

महोदय, जब वे वाशिंगटन पहुंचे तो वाशिंगटन पहुंचने से पहले शिंजो आबे, पुतिन, सी जिनपिंग, इन सबके साथ नरेन्द्र मोदी की मुलाकातें एक अद्भुत परिदृश्य में होंगी। वैश्विक पटल पर, वैश्विक परिदृश्य में यह जो भारत का उदय है, यह एक अद्भुत आशा का संचार करता है। मैं अभी संग्रीला डॉयलॉग में भारत के एक सांसद के पूर्वी देशों का पिछले 17 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां गया था। वहां के लोगों ने, वहां के सम्पादक श्रेष्ठ टाइम के एडिटर, वहां के नेता ने कहा, Mr. Vijay, India must increase its presence in the East Asian region because your presence does not scare anyone. Your presence does not create any suspicion in the minds of anyone. India's presence in the East Asia, India's presence in the Asia Pacific region has its cool impact, has its friendly impact. Everyone feels very comfortable when India is active in Asia Pacific region. एशिया प्रशांत सागर में अगर भारत की उपस्थिति, उसकी सक्रियता बढ़ती है तो किसी देश के मन में कोई संशय, संदेह या डर पैदा नहीं होता है, बल्कि आश्वस्ति मिलती है, आश्वासन मिलता है और उनको लगता है कि भारत का जो प्रभाव है, वह सबके लिए अनुकूल है, सबके लिए शांति प्रदान करने वाला है।

उपसभापति महोदय, भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं। 80 अरब डॉलर से अधिक भारत का और आसियान देशों के साथ संबंध है। मैं 2012 की आसियान-भारत की कार रैली में भारत का नेतृत्व करके आठ हजार किलोमीटर गाड़ी चलाकर, सात देशों में चलकर आया हूं। यह सम्पूर्ण एशिया भारत का स्वाभाविक मित्र क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में आप जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं अंगकोरवाट काम्बोज देश में है, वे कहते हैं कि आपके ऋषि यहां आए थे और उन्होंने इस काम्बोज देश को बनाया था। महाभारत और रामायण वहां के मंदिरों पर है। वियतनाम चम्पा शिव मंदिर, थाईलैंड, श्याम देश, हर घर में गणपति और सरस्वती हैं। जापान में सरस्वती है। मैं चीन गया, शिचुआन विश्वविद्यालय में मेरे तीन व्याख्यान हुए, उसके बाद वहां के

प्रोफेसर ने कहा, "But, Mr. Vijay, whatever you say, you say because, I know, you belong to the RSS. But, there is a China in every Indian home today." And, he was right. Right from bulbs to furniture to cycles to textiles, you find Made-in-China en every Indian home. I suddenly said, "Professor Lo, you are right, लेकिन चीन के हर घर में एक हजार साल से हिन्दुस्तान है। जहां-जहां बुद्ध है, वहां-वहां भारतवर्ष है, जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। वर्तमान मेड इन चाइना को आप कितना भी हटा दीजिए, लेकिन भारत का जो संदेश वहां पर गया है, वह मिट नहीं सकता है।

उपसभापति महोदय, कल्पना कीजिए, 1150 पहले भारत के नौजवान काशी से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से चेंगदू गए, जो बीजिंग से 2000 किलोमीटर उत्तर में है। वहां पर उन्होंने दुनिया की 1250 फुट की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा बनाई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है। अगर कोई चीन के राजगुरु के रूप में अभिषिक्त हुआ है, तो उसका नाम कुमारजीत है। वे कश्मीर के थे, काषगर गए और उनको तंग डायनेस्टी ने 950 साल पहले "The teacher of China" का खिताब दिया था। यह हमारी हेरिटेज है, यह हमारा उत्तराधिकार है, यह हमारे पूर्वजों की पुण्याई है। इस पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, हमारी सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। यह जो सम्पूर्ण एशिया-पेसिफिक महासागरीय क्षेत्र है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में विभिन्न महाशक्तियों की जो सक्रियता है, वह भारत के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। भारत वहां पर जा रहा है और उसके सभी के साथ अच्छे संबंध हों। हमें वियतनाम, फिलीपींस, चीन और जापान के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए एशिया-प्रशांत महासागर के चित्र में भारत की विजय ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun Vijay, you have only three more minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री तरुण विजय: उपसभापति जी, मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं, आप लोगों को पंद्रह-पंद्रह मिनट देते हैं, आप मुझे साढ़े तीन मिनट तो दीजिए। यह क्या बात है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is not the problem; we have to adjourn at 7.30 ...*(Interruptions)* He can speak tomorrow; I have no problem. ...*(Interruptions)*... We have to adjourn the house by 7.30. ...*(Interruptions)*...

श्री तरुण विजय: अध्यक्ष महोदय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के इर्द-गिर्द दो परमाणु शक्तियां है। एक शक्ति की 4000 किलोमीटर की सीमा है, तो दूसरी शक्ति की 3500 किलोमीटर की सीमा है। इन दोनों के साथ हमारे सीमा विवाद हैं। क्या लोग चाहते हैं कि हम तुरंत पेटेंट टैंक और बारूद लेकर युद्ध करें? नहीं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी गरीबी दूर करनी है। हम लोग तो यहां पर बहुत विशेषाधिकार सम्पन्न लोग हैं। हम लोग सब्सिडी वाला खाना खाते हैं, लेकिन आप संसद भवन के बाहर दो कदम जाकर देखिए, 47 डिग्री की तपती धूप में पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले और मजदूर लोग काम करते हैं और फुटपाथ

पर सोते हैं, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के स्टेशनों पर जूठन बटोरकर रेल की पटरियों पर खाना खाते हैं। किसके दिल में इसका दर्द पैदा होता है? हमें यह दर्द दूर करना है। हमें सबसे पहले भारत की गरीबी दूर करनी है। हमारा "रामराज्य" का स्वप्न है – "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराजु नहीं काहि व्यापा।'

वह स्वप्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का – अंत्योदय कर दो। किसी की गरीबी हमें सहन नहीं चाहिए। हर भारतीय को धनी, समृद्ध और सुशिक्षित और सुरक्षित होना चाहिए तब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार कर पाएंगे। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only two more minutes. You are not listening to me. You have only two more minutes.

श्री तरुण विजय: इसके लिए जरूरी है कि हम अपने दोनों पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाएं।

उपसभापति महोदय, चीन के विदेश मंत्री भारत में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। यह अच्छी बात है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री तरुण विजय: सर, टू मिनिट्स। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो विदेश नीति है, वह सबको आश्वस्त करने वाली और मित्रता करने वाली होनी चाहिए और हमारी जो समर नीति है, वह शत्रु के हृदय में भय पैदा करने वाली होनी चाहिए। उसका कभी दुस्साहस नहीं होना चाहिए कि वह कभी हमारी सीमा का अतिक्रमण भी कर पाए। यह साहस, यह हिम्मत, यह बुलंदगी, यह स्टील विल, जो फौलादी इच्छाशक्ति है, जो नरेन्द्रभाई मोदी ने दिखाई है, उसके कारण हम यह कह सकते हैं कि,

"तेरे लब पे है इराको, स्याम, मिश्र और रोम, चीन, लेकिन
अपने ही वतन के नाम से वाकिफ़ नहीं, सबसे पहले मर्द बन,
हिंदोस्तां के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते।"

यह हिंदुस्तान हमें बनाना है। जैसा कि मेरे मित्र और बहुत अच्छे पठित स्वाध्यायी ने अनेक कविताएं सुनाईं। भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जो पटना के थे, ने भारत के भविष्य के बारे में दो पंक्तियां कही थीं। वे संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। उन्होंने कहा था, "एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान।" वह हिंदुस्तान हम उठाएंगे, हम भारत का अभ्युदय करके दिखाएंगे, वह भारत का भाग्यविधाता बनेगा। भारत का गरीब, किसान, मजदूर, अध्यापक, डॉक्टर भाग्यविधाता बनेगा, अमीर लोग नहीं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you can conclude. The time is over. समाप्त कीजिए।

श्री तरुण विजय: वह साधारण जनता एक ऐसा वातावरण बनाएगी कि भारत संपूर्ण विश्व को शांति, सुरक्षा और सहअस्तित्व का संदेश देगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. The time is over.

श्री तरुण विजय: मैं इस नवीन अभ्युदय को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम्।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

The House stands adjourned to meet at 11.00 hours on Wednesday, the 11th June, 2014.

The House then adjourned at thirty minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 11th June, 2014.